राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 197

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 25 दिसंबर 2019

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 16

आठ सेवाओं के विलय के साथ रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे के विभिन्न विभागों में व्याप्त गुटबाजी से कामकाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से नाराज सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत रेलवे की आठ विभिन्न सेवाओं को आपस में मिलाकर 'इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस' नामक नई सेवा में तब्दील करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ रेलवे बोर्ड में आठ की जगह सिर्फ चार सदस्य होंगे, जबकि चेयरमैन को चेयरमैन-सह-सीईओ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला हुआ।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को इस कैबिनेट फैसले के बारे में बताया कि वर्ष 1905 से भारतीय रेलवे में आठ अलग-अलग सेवाओं के जरिए काम होता आया है। परंतु वक्त के साथ इससे विभागों के बीच वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी को बढ़ावा मिलने से रेलवे की प्रगति बाधित होने लगी। इसलिए आठों विभागों का एक सेवा में विलय कर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (आइआरएमएस) के रूप में नई केंद्रीय सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इसी के साथ अब रेलवे का आकार भी अपेक्षाकृत छोटा किया जाएगा। जिसमें चेयरमैन और सीईओ के अलावा सिर्फ चार कार्यकारी मेंबर (इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, रोलिंग स्टॉक तथा फाइनेंस) के अलावा कुछ स्वतंत्र और अनुभवी विशेषज्ञ मेंबर होंगे। इनके लिए उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र तथा प्रबंधन का 30 वर्ष का अनुभव जरूरी होगा। चेयरमैन के पास मौजूदा मेंबर स्टाफ की तरह काडर कंट्रोल की तमाम शक्तियां भी होंगी, जिन्हें वो डीजी-एचआर की सहायता से कार्यान्वित करेगा। इसी के साथ इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस (आइआरएमएस) को इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस (आइआरएचएस) के नाम से जाना जाएगा।

बदल जाएगी सूरत

नई दिल्ली में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद मीडिया को फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। प्रेट्र

- पृथक सेवाओं के बजाय अब केवल एक 'इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस' होगी

- बोर्ड में सिर्फ चार मेंबर होंगे, चेयरमैन कहलाएगा सीईओ, ताकतवर होंगे जीएम

27 जीएम सचिव के समकक्ष

निर्णय के तहत सभी जोनों तथा उत्पादन इकाइयों के 27 जीएम को रेलवे बोर्ड के सदस्यों की भांति भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा मिलेगा। जबकि रेलवे बोर्ड चेयरमैन प्रधान सचिव के स्तर के बने रहेंगे।

चार समितियों की सिफारिश थी

गोयल ने कहा कि प्रकाश टंडन से लेकर राकेश मोहन, सैम पित्रोदा तथा बिबेक देबराय की अध्यक्षता वाली चार समितियों ने इन सुधारों की सिफारिश की थी। हम इन्हें अब लागू कर पा रहे हैं। इन सुधारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय रेल को भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बनाने के सपने को साकार करने में सहायक साबित होंगे।

निर्णय लेने में आएगी तेजी

रेलवे बोर्ड के अफसरों के मुताबिक इन संगठनात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप गुटबाजी खत्म होने से नौकरशाही पर लगाम लगेगी। निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे रेलवे के आधुनिकीकरण, यात्री सेवाओं में सुधार तथा ट्रेनों की गति बढ़ाने के अलावा यात्रियों को उच्चतम सुरक्षा प्रदान करने की मुहिम को और बल मिलेगा।

निर्णय की आलोचना शुरू

इस निर्णय की आलोचना भी शुरू हो गई है। आलोचकों का कहना है कि काडर विलय से रेलवे का भी वही हाल हो सकता है जो इंडियन एयरलाइन के विलय से एयर इंडिया का हुआ है। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, मौजूदा सेवाओं के अफसरों को नई एकीकृत सेवा में स्वयं को ढालने में मुश्किलें आएंगी, जबकि नई भर्तियों के लिए नया ढांचा तैयार करना पड़ेगा। आधी ऊर्जा इन कार्यों पर खर्च होने से रेलवे के कामकाज पर उलटा असर पड़ सकता है। वहीं, नए स्वतंत्र मेंबरों की भूमिका स्पष्ट नहीं है।

देश को बहुत जल्द मिलेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अलग-अलग तरह की सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे देश को बहुत जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) मिलेगा जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के साथ रणनीति तय करेगा। चार महीने पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी। मालूम हो कारगिल समीक्षा समिति ने इसकी सिफारिश की थी। 1999 में कारगिल युद्ध के समय देश की सुरक्षा प्रणालियों और रणनीति में खामी की समीक्षा के लिए यह समिति बनाई गई थी। कारगिल समिति के सुझाव के बाद भी यह प्रस्ताव लंबित ही था। (पेज-3 देखें)

वाजपेयी की जयंती के पूर्व छह हजार करोड़ की अटल पेयजल योजना मंजूर पेज>>3

आइवीसी में कुछ संशोधनों के साथ आएगा अध्यादेश पेज>>12

सरोकार

प्रीति ने बदली रीत, बधाई की जगह सिखा रहीं शिक्षा के गीत

संगरूर : पंजाब के संगरूर जिले के किन्नर डेरे की प्रमुख प्रीति महंत थर्ड

जेंडर बच्चों का भविष्य संवारने में जुटी हैं। डेरे की शरण में आए थर्ड जेंडर बच्चे स्कूल में सामान्य बच्चों संग पढ़ रहे हैं। अपनी सोच के चलते प्रीति अलग नजर आती हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

नए कश्मीर में मिलजुल कर बना रहे तरक्की की नई राह

श्रीनगर : श्रीनगर-बारामुला हाईवे पर गुरुद्वारे और झेलम पर पुल की राह में

पड़ रही मस्जिद को लेकर लोगों ने अड़ियल रुख छोड़ दिया। लोगों को मनाने में उपायुक्त डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने भी अहम भूमिका निभाई है। (पेज-11)

बनेगा एनपीआर, दस्तावेज जरूरी नहीं

कैबिनेट का फैसला ▶ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर व जनगणना के लिए 13 हजार करोड़ रुपये मंजूर

अप्रैल-सितंबर 2020 के बीच एनपीआर, 9-28 फरवरी 2021 के बीच होगी जनगणना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

असम को छोड़कर पूरे देश में अगले साल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट किया जाएगा। अप्रैल से सितंबर, 2020 के बीच देश भर में घरों की गिनती के दौरान एनपीआर के लिए डाटा एकत्र किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एनपीआर को अपडेट करने और जनगणना के लिए लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, एनपीआर के डाटा एकत्र करने के दौरान किसी से भी किसी तरह का कोई प्रूफ, दस्तावेज या बायोमीट्रिक नहीं लिया जाएगा। लोग जो जानकारी देंगे, उसे मान लिया जाएगा। 'सरकार को अपने नागरिकों पर पूरा भरोसा है।

कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए जावडेकर ने कहा कि एनपीआर से किसी को कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह उसी तरह से है जैसा कि 2010 में हुआ था। उन्होंने भी कहा कि एनपीआर के तहत किसी को कोई जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस बार एनपीआर का डाटा जुटाने के लिए घर-घर जाकर विस्तृत डाटा एकत्रित करने के साथ-साथ एक एप के सहारे भी डाटा हासिल किया जाएगा। कोई व्यक्ति इस एप के जरिए अपनी पूरी जानकारी दे सकता है। इस पर 3941.35 करोड़ खर्च आएगा। जावडेकर ने कहा कि देश में नौ फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच होने वाली 16वीं जनगणना डिजिटल होगी। 30 लाख कर्मचारी जनगणना के आंकड़ों को एप के जरिए एकत्र करेंगे और इस पर 8754 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अभी तक जनगणना के आंकड़ें आने में वर्षों लग जाते थे, जबकि डिजिटल जनगणना के आंकड़े एक-दो साल में ही सरकार के पास उपलब्ध हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को बनाते समय किया जा सकेगा।

- घर-घर जाकर विस्तृत डाटा एकत्रित करने के साथ-साथ एक एप के सहारे भी डाटा हासिल किया जाएगा
- शाह ने कहा, पहली बार वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने तैयार करवाया था एनपीआर

नई दिल्ली में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद मीडिया को फैसले की जानकारी देते केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

गौरतलब है कि जनगणना से पहले एनपीआर तैयार किया जाता है। 2021 की जनगणना के बाबत इसकी तैयारी हो गई है। लेकिन जिस तरह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर सियासी संग्राम व आंदोलन छिड़ा है उसे देखते हुए खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सामने आकर स्पष्ट किया कि इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ही एनपीआर तैयार कराया था। दस साल बाद सरकार ने इसे अपडेट करने का फैसला भर किया है।

शाह ने कहा, एनपीआर के लिए केंद्र सरकार ने 31 जुलाई को ही अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके बाद सभी राज्यों ने अधिसूचना जारी की। यदि एनपीआर को लेकर कोई आशंका होती, तो राज्य सरकारें अधिसूचना क्यों जारी करतीं। राज्य सरकारों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को कोई दस्तावेज या जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार में विचार-विमर्श की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ कड़े रुख के साथ ही पश्चिम बंगाल और केरल द्वारा एनपीआर तैयार नहीं करने के एलान पर अमित शाह ने कहा कि वे और गृहमंत्रालय के अधिकारी इस संदर्भ में संबंधित राज्य सरकारों से बात करेंगे। वे नहीं चाहेंगे कि कोई भी राज्य एनपीआर से बाहर रहे, क्योंकि इससे मुख्यतौर पर वहां रहने वाले गरीबों को नुकसान होगा और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वे वंचित रह जाएंगे। शाह ने स्पष्ट कहा कि एनआरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है। इसे पूरे देश में लागू करने को लेकर न तो कैबिनेट में और न ही संसद में कोई चर्चा हुई है। एनआरसी पर फिलहाल बहस करने की जरूरत नहीं है।

अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के दौरान नहीं खुले डिटेंशन सेंटर पेज>>3

तृणमूल कांग्रेस का आरोप, जनता से धोखाधड़ी कर रही केंद्र पेज>>3

लोन घोटाले में फंसे मारुति के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर

- 110 करोड़ के घोटाले में सीबीआइ ने की एफआइआर दर्ज, ठिकानों पर छापे
- खट्टर की कंपनी कारनेशन ऑटो ने पीएनबी से लोन लिया था, जो एनपीए हो गया

नई दिल्ली, एजेंसियां : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने मारुति उद्योग के पूर्व प्रबंध निदेशक जगदीश खट्टर के खिलाफ 110 करोड़ रुपये के लोन घोटाले में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जांच एजेंसी द्वारा हाल में दर्ज एफआइआर में खट्टर और उनकी कंपनी कारनेशन ऑटो इंडिया लिमिटेड पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 110 करोड़ रुपये नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सीबीआइ ने 77 वर्षीय खट्टर और कारनेशन ऑटो के ठिकानों पर सोमवार शाम छापेमारी भी की।

खट्टर 1993 से 2007 तक मारुति उद्योग में रहे थे, जहां से वे प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उन्होंने कारनेशन ऑटो इंडिया लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिये उन्होंने 2009 में पंजाब नेशनल बैंक से 170 करोड़ रुपये का लोन लिया। 2015 में लोन एनपीए घोषित हो गया। पीएनबी की शिकायत पर सीबीआइ ने आइपीसी की विभिन्न धाराओं में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

एफआइआर के मुताबिक, बैंक द्वारा केजी सोमानी एंड कंपनी से फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया। इससे पता चला कि खट्टर ने धोखाधड़ी से 6,692.48 लाख की अचल संपत्ति बैंक की मंजूरी के बिना 455.9 लाख रुपये में बेच दी। यह संपत्ति बैंक को सिक्युरिटी के तौर पर दिखाई गई थी, लेकिन इसे बेचने के बाद पैसा बैंक में नहीं जमा कराया गया। छानबीन में यह भी पाया गया कि आरोपित कर्जदार ने धोखाधड़ी कर लोन का पैसा अपनी दूसरी कंपनियों में लगाया। इसलिए इसे बैंक के पैसे का दुरुपयोग माना गया, जिसमें रकम का इस्तेमाल निजी काम के लिए किया गया।

जगदीश खट्टर की फाइल फोटो। प्रेट्र

बैंक अफसरों की भूमिका की होगी जांच पेज>>3

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

हेमंत सोरेन 29 को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

रांची : हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ मोरहाबादी मैदान में होगा। इसके लिए एक बजे का समय निर्धारित किया गया है। मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर हेमंत ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और शपथ की तारीख की सूचना दी। शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

आइएमएफ ने गिनाईं भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने सोमवार देर रात अमेरिका में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर रिपोर्ट जारी की है। आइएमएफ ने कहा है कि आर्थिक सुस्ती के दौर से निपटने के लिए राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और वित्तीय सुधार से जुड़ी नीतियों को लेकर कुछ बड़े बदलाव करने होंगे।

जेयू में फिर राज्यपाल का रास्ता रोका, लौटने को किया मजबूर

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल की ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चल रही तनातनी में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के दीक्षा समारोह में पहुंचे राज्यपाल और कुलाधिपति धनखड़ को छात्रों और तृणमूल कांग्रेस कर्मचारी संघ के प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश करने से रोक दिया। छात्रों ने पहले से ही तय कर रखा था कि कुलाधिपति के हाथों डिग्री नहीं लेंगे। विरोध के बाद धनखड़ विश्वविद्यालय परिसर से वापस लौट गए। ऐसे में उनके बगैर ही जेयू का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ।

लगे गो बैक के नारे, दिखाए गए काले झंडे : मंगलवार को धनखड़ विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेने गए थे। इस दौरान छात्रों और तृणमूल कांग्रेस कर्मचारी संघ के प्रदर्शनकारियों ने धनखड़ को काले झंडे दिखाए और सुबह साढ़े दस बजे कैंपस के गेट नंबर पांच पर उनकी कार रोक दी। प्रदर्शनकारियों ने 'गो बैक' के नारे लगाए और 'नो एनआरसी, नो सीएए' के पोस्टर भी लहराए।

कोलकाता में मंगलवार को जादवपुर विवि में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद मीडिया से मुखातिब जगदीप धनखड़। प्रेट्र

रिमोट से चल रहे हैं कुलपति पेज>>4

मेरठ पुलिस ने राहुल-प्रियंका को रोका, कहा-दो दिन बाद आना

मेरठ : नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हुई हिंसा में मारे गए छह लोगों के परिजनों से मिलने आ रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मेरठ पुलिस ने मंगलवार को परतापुर थाने के पास रोक दिया। पुलिस ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को दो दिन बाद आने की बात कह कर वापस कर दिया। (पेज-5)

शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, और गिरेगा पारा

नई दिल्ली : उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप मंगलवार को भी जारी रहा। इसका असर दिल्ली एनसीआर व हरियाणा में भी दिखा। पहाड़ों पर बर्फबारी से कश्मीर और लेह में तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया। हिमाचल के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे जा पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बुधवार को बादल छाए रहेंगे। (पेज-7)

कमेटी ने दिया जीएसटी दरें बढ़ाने का सुझाव

- छूट वाली कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने की भी सलाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार की सिफारिश के लिए गठित कमेटी ने जीएसटी दरें बढ़ाने और कुछ छूट वाली वस्तुओं को इसके दायरे में लाने की सलाह दी है। कमेटी की ये सिफारिशें जीएसटी के राजस्व में उम्मीद के अनुरूप वृद्धि नहीं होने के आंकड़ों के बीच आई हैं। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कंपेंसेशन सेस में 60,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट का अनुमान है।

केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई इस कमेटी ने आपसी विमर्श और संबंधित पक्षों से सलाह के बाद 18 दिसंबर को अपना प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के समक्ष पेश किया था। कमेटी ने जीएसटी के दायरे से बाहर की कुछ वस्तुओं को इसमें लाने की सलाह दी है। वर्तमान में मांस, मछली, शहद, दूध के उत्पाद, सब्जियां, फल और मेवा जैसी वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाई जा रही है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कमेटी ने पांच परसेंट जीएसटी वाली वस्तुओं को 12 परसेंट और 12 परसेंट वाली वस्तुओं को 18 परसेंट के स्लैब में डालने की सिफारिश की है। इसमें मोबाइल फोन जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इसके साथ ही कमेटी ने जीएसटी काउंसिल से कहा है कि 28 परसेंट से 18 परसेंट जीएसटी वाले स्लैब में लाई गई कुछ वस्तुओं पर फिर से विचार किया जाए।

इस समय जीएसटी के अंतर्गत चार स्लैब पांच, 12,18 और 28 परसेंट हैं। इसमें 28 परसेंट की कैटेगरी वाली वस्तुओं पर सेस भी लगाया जाता है। यह सेस एक से 25 परसेंट तक हो सकता है।

पिछले सप्ताह हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस पर कोई फैसला लेने की बात कही थी। काउंसिल की अगली बैठक में इन सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। कमेटी का कहना है कि पांच फीसद की दर से बढ़ते हुए चालू वित्त वर्ष में कंपेंसेशन के तौर पर राज्यों को 1.6 लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ सकती है। इस दर से 2019-20 में सेस गैप 63,200 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

कच्चा माल और तैयार उत्पाद पर ड्यूटी के फर्क से बढ़ रहा बोझ

नई दिल्ली : कच्चा माल और उससे तैयार उत्पाद में ड्यूटी की दर में फर्क के चलते सरकार को हर साल 20000 करोड़ रुपये का रिफंड देना होगा। ऐसी करीब दो दर्जन वस्तुएं हैं जिनके कच्चे माल पर जीएसटी की दर अधिक है जबकि तैयार माल पर ड्यूटी की दर कम है। जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में इस असंतुलन को दूर करने के संबंध में काउंसिल अपनी अगली बैठक में विचार कर सकता है। (पेज-12)

बयां की पीड़ा

पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों ने दिल्ली में सुनाया दर्द, कोहली सरनेम की युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या

पाक की असलियत, विराट के शतक की खीझ में बर्बरता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

क्रिकेट मैच में भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के शतक से झल्लाए मुसलमानों ने पाकिस्तान में ही रहने वाले कोहली परिवार की एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में उसकी हत्या कर दी। मानवता को तार-तार करने वाली इस जघन्य वारदात के बाद भी उन युवकों का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पाक में ऐसे धार्मिक उन्माद को सियासी और धार्मिक संरक्षण प्राप्त है। इसी तरह तालिबान शासन में अफगानिस्तान में एक सिख कारोबारी को गोलियों से भून दिया गया।

रूह कंपा देने वाली यह हकीकत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने बताई है। वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध व ईसाई गुलामों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता देने का कानून लाने पर देशभर में हंगामा हो रहा है। नागरिक संशोधन कानून (सीएए)-2019 पर हंगामे के बीच शरणार्थी अल्पसंख्यकों ने दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में उक्त कानून पर लोगों से सहानुभूतिपूर्वक विचार की अपील की है। ये देश के विभिन्न शरणार्थी कैंपों से यहां आए थे।

पाकिस्तान से आए शरणार्थी भागचंद बेलजी ने कहा, कराची में महिलाओं का अपहरण, बलात्कार व धर्मपरिवर्तन आम बात है। वहां ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हमारी वहां कोई नहीं सुनता है। इसी तरह शरणार्थी चीतम शर्मा, अर्जुन सिंह, दयाल दास व प्यारा सिंह समेत अन्य ने भी अपनी व्यथा सुनाई। इस मौके पर पाक से शरणार्थी के रूप में आई आरती अपनी 20 दिन की बच्ची के साथ आई थी, जिसका नाम नागरिकता रखा गया है। इस कार्यक्रम में सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे व शंकर लालवानी के अलावा अन्य समाजसेवी भी मौजूद रहे।

हम खुशी से भारत नहीं आए हैं: मेघवाल : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आए गोवर्धन दास मेघवाल ने कहा, वे खुशी से भारत नहीं आए हैं। हम लोगों के साथ काफी बुरा बर्ताव हुआ है। जिस दिन बंटवारे की रेखा खिंची गई और देश आजाद हुआ, उसी दिन से उन लोगों की गुलामी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान समेत अन्य इस्लामिक पड़ोसी मुल्कों में उनके साथ बर्बरता हो रही है। इसलिए लोग मानवता की खातिर उनसे सहानुभूति रखें। उनकी मदद करें। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध न करें। वे भी उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं।

प्यारा सिंह ने कहा, हिंदू हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे: अफगानिस्तान से आए प्यारा सिंह ने कहा, सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोग हमारी तकलीफ को नहीं समझ सकते हैं। तालिबान के शासन में मेरे भाई को गोलियों से भून दिया गया। कारोबार पर ग्रहण लग गया। उन्हें अपने धर्म के लिए जजिया कर देना पड़ता था। शिया ईरान जा सकते हैं। सुन्नी पाकिस्तान जा सकते हैं। वहीं, सिख और हिंदू हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे?

दयाल सिंह बोले हमारा नहीं, मानव जाति का कर रहे विरोध: पाकिस्तान के सिंध से आए दयाल सिंह ने कहा,उन लोगों को शवदाह से भी रोका जाता है। आस-पास के मुस्लिम कहते हैं इससे बदबू आती है। आप (प्रदर्शनकारी) हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। बल्कि मानव जाति और इंसानियत का विरोध कर रहे हैं।

सौ से ज्यादा शरणार्थियों ने सुनाई जुल्म का दास्तां : कार्यक्रम में 100 से ज्यादा शरणार्थियों ने अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां सुनाई। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि भारत की नागरिकता मिलने के बाद वह भी सम्मान से जीवन जी सकेंगे। सम्मान की जिंदगी की खातिर ही वह पाकिस्तान व अन्य इस्लामिक मुल्कों से अपना घर-कारोबार, जमीन व रिश्तेदार छोड़कर यहां आए हैं।

नई दिल्ली में मंगलवार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के कार्यक्रम में अपनी बेटी नागरिकता के साथ शरणार्थी आरती। साथ में भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा और सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे (बीच में)। जागरण

पत्नी ऐश्वर्या को हर माह 22 हजार रुपये गुजारा भत्ता देंगे तेजप्रताप

पटना : बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पारिवारिक न्यायालय के आदेशानुसार पत्नी ऐश्वर्या को भरण-पोषण और आवास के लिए हर माह 22 हजार रुपये गुजारा भत्ता देना होगा। उन्हें यह राशि अगस्त 2019 से ही देनी होगी। इसके अलावा तेजप्रताप को मुकदमे में हुए खर्च के रूप में भी ऐश्वर्या को एकमुश्त दो लाख रुपये देने पड़ेंगे। (पेज-4)

विश्व क्रिकेट में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धौनी का डंका

सिडनी : कप्तान विराट कोहली के साथ-साथ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी का विश्व क्रिकेट में डंका बज रहा है। जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) की आधिकारिक वेबसाइट ने धौनी को दशक (2010-19) की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम और विराट को टेस्ट टीम का कप्तान चुना है तो वहीं क्रिकेट की बाइबल विजडन ने भी पिछले 10 सालों के लिए चुनी अपनी दोनों टीमों में भारतीय कप्तान को जगह दी है। (पेज-15)

5.7 डिग्री सेल्सियस रहा मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान। यह सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 दिसंबर तक शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 25 दिसंबर 2019

आप सरकार की रिपोर्ट कार्ड में केजरीवाल पास

लेखा-जोखा ▶ सीएम ने कहा, सबसे अधिक काम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, 8 हजार करोड़ अनधिकृत कॉलोनियों पर खर्च किए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में अपनी सरकार के पांच साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। रिपोर्ट कार्ड में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान, कच्ची कॉलोनियों आदि को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे अधिक कार्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। इससे पहले चुनाव आने से पहले सभी पार्टियां कहती थीं कि अनधिकृत कॉलोनियों में काम कराएंगे, मगर कराते नही थे, हमने इस परंपरा को बदला है। हमने 8 हजार करोड़ रुपये इन कॉलोनियों में खर्च किए हैं। हमें जो मौका दिल्ली के लोगों ने दिया है। हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, प्रदेश संयोजक गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, इमरान हुसैन व राजेंद्र पाल गौतम सहित पार्टी के सभी सांसद, विधायक व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की है। दिल्ली में एक नई पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी। पार्टी को बने हुए अभी कुछ समय हुआ था कि जनता ने हमें 70 में से 67 सीट देकर इतिहास कायम किया। पार्टी बनने से पहले अन्ना आंदोलन हुआ था। जनता ने देखा यह लड़के तो ईमानदार हैं, संघर्ष करते हैं, डरते नहीं हैं साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं, इनको एक मौका मिलना चाहिए और जनता ने हम जैसे आम लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आज 5 साल के बाद जब मैं जनता से बात कर रहा हूं मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपनी दिल्ली की जनता का सीना चौड़ा कर दिया है। जब हम यह रिपोर्ट कार्ड बना रहे थे तो हमें बड़ी मुश्किल हुई कि हम क्या लिखें और क्या न लिखें बहुत सारे काम हुए।

सीएम ने कहा की मुझे एक बात की पूरी संतुष्टि है कि दिल्लीवालों ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी थी हमने दिन रात मेहनत की और आज मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि सबसे ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की आई है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने हमारा पांच साल का ऑडिट कराया, केंद्र सरकार को हमारे खिलाफ कुछ नही मिला। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार है जो मुनाफे में है। आज पांच साल के बाद हम सारी जांच एजेंसियों से क्लीन चिट लेकर बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स विभाग, ईडी ने सारे मुकदमों में क्लीन चिट दे दी।

70 फीसद तक अधिक कमाते हैं दिल्ली में अब श्रमिक

8,632 रुपये न्यूनतम मजदूरी से बढ़ाकर की 14,842 रुपये

आप कार्यालय में बीते पांच सालों के विकास कार्यों की जानकारी देते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (नीली स्वेटर में)। साथ में (बाएं से) मंत्री सत्येंद्र जैन, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम। ध्रुव कुमार

रिपोर्ट कार्ड अगले दो हफ्तों में घर-घर पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी : इस दौरान प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता सात टाउन हॉल मीटिंग, सात सौ मोहल्ला सभा और 35 लाख घरों तक डोर-टू-डोर अभियान के तहत इस रिपोर्ट कार्ड को दिल्ली की प्रत्येक जनता तक अगले दो हफ्तों में पहुंचाएंगे। यह अभियान 26 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।

विकास की हुई तेज रफ्तार : दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ रुपये से बढ़कर हुआ 60,000 करोड़ रुपये। दिल्ली देश का अकेला राज्य जिसका बजट मुनाफे में (रेवेन्यू सरप्लस) है।

महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान : अपराधमुक्त दिल्ली के लिए 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। अभी 1.4 लाख और कैमरे लगाने की तैयारी है। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। डीटीसी बसों में 13,000 बस मार्शल नियुक्त किए गए हैं।

अनधिकृत कॉलोनियों का रखा ध्यान

- 8,000 करोड़ की लागत से अनधिकृत कॉलोनियों में किए विकास कार्य।
- 1797 कच्ची कॉलोनियों में से 1,281 कॉलोनियों में हुआ सड़क निर्माण ।
- 1,130 कच्ची कॉलोनियों में बिछाई गईं सीवर लाइनें।

रिपोर्ट कार्ड में बताई गईं प्रमुख उपलब्धियां

शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन

आप सरकार ने पिछले पांच साल में क्रांतिकारी कार्य किए हैं। सबसे पहला काम है शिक्षा। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ुंत साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि शिक्षा में परिवर्तन की चर्चा आज पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। लेकिन, अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो हमने दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए चाहे वह गरीब हो या अमीर, हमने अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। जब हमारी सरकार बनी थी तब शिक्षा का बजट 6600 करोड़ था जो आज 15600 करोड़ का है। हमने 20,000 से ज्यादा नए क्लासरूम बनाए हैं। पहले दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में कुल मिलाकर 70 सालों में सारी सरकारों ने मात्र 17000 क्लासरूम बनाए थे। 2019 में 12वीं कक्षा के स्तर पर प्राइवेट स्कूलों में 93 फीसद नतीजे आए। जबकि सरकारी स्कूलों में 96 फीसद नतीजे आए। हमारी सरकार से पहले प्राइवेट स्कूल हर साल अनाप-शनाप फीस बढ़ाया करते थे। पिछली सरकारों के साथ उनकी सेटिंग रहती थी हमने उस सेटिंग को खत्म किया और पिछले 5 सालों में हमने अधिकतर स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी।

हर घर पहुंची सस्ती बिजली

पूरे देश में दिल्ली अकेला राज्य है जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का अकेला शहर है। यही नहीं, 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे रखे गए हैं। आज 31 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली पहुंचाने का काम आप सरकार ने किया है।

घरों में पहुंचा नल का पानी

हर घर को प्रतिमाह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी। 14 लाख से ज्यादा घरों का पानी का बिल हुआ शून्य। पाइप के जरिये पानी आपूर्ति 58 फीसद से बढ़ाकर की 93 फीसद। दिल्ली को मिली टैंकर माफियाओं से निजात। 1,554 कच्ची कॉलोनियों तक पहुंचाया पीने का पानी।

हर इंसान को बेहतर इलाज

- स्वास्थ्य पर बजट का 13 फीसद खर्च करने वाला दिल्ली अकेला राज्य। बजट 3,500 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़।
- जन-जन तक पहुंचाया मुफ्त इलाज, खोले 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लीनिक और किया सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प।
- डेंगू पीड़ितों की संख्या 2015 के 15,867 से घटकर 1,301 हुई। मरने वालों की संख्या 60 से घटकर शून्य पर पहुंची।

मुख्यमंत्री बताएं कितने चुनावी वादे पूरे हुए : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के पांच साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के साथ धोखा बताया है। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने कितने चुनावी वादे पूरे किए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि शिक्षा को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन के तमाम बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री को 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज बनाने के वादे का क्या हुआ। 20 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का वादा किया गया था, परंतु एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया। स्कूलों में नए कमरे बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसी तरह से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अस्पतालों के विकास व मरीजों की सहायता के लिए रोगी कल्याण समिति ने कोई काम नहीं किया।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल सरकार के पांच साल का रिपोर्ट कार्ड जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड झूठ का पुलिंदा है।

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने रिपोर्ट कार्ड को छलावा रिपोर्ट बताया है। चोपड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल विज्ञापनों की सरकार बनकर रह गई है। इस सरकार ने 200 यूनिट बिजली सब्सिडी देने के नाम पर न केवल बड़ा घोटाला किया है, बल्कि निजी कंपनियों को हजारों करोड़ों का लाभ पहुंचाया है।

निर्भया के तीन गुनहगार डालेंगे पुनर्रीक्षण याचिका, चौथे का जवाब बाकी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया कांड में फांसी की सजा पाए चार दोषियों में से तीन ने जेल प्रशासन को नोटिस का उत्तर भेजा है। अक्षय, विनय व पवन की ओर से जेल प्रशासन को बताया गया है कि अब उनके पास दया याचिका से पूर्व क्यूरेटिव याचिका दायर करने का विकल्प बचा है। क्यूरेटिव याचिका दायर करने के बाद जो नतीजे आएंगे, उसके आधार पर आगे क्या करना है, यह तय करेंगे। दोषियों में मुकेश की ओर से अब तक जेल प्रशासन को जवाब नहीं दिया गया है। मुकेश अपना जवाब बृहस्पतिवार तक जमा कर सकता है। तिहाड़ जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक राजकुमार ने बताया कि अब कोर्ट को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी।

गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट से मिले निर्देश के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से निर्भया के दोषियों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में उन्हें सात दिन का वक्त देते हुए कहा गया था कि दोषी अक्षय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। अब चारों दोषी मौत की सजा के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली जेल नियमावली 2018 के नियम 837 के तहत यदि आपने दया याचिका दायर नहीं की है तो सात दिनों के भीतर आप राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल कर सकते हैं।

क्यूरेटिव व दया याचिका : क्यूरेटिव याचिका के नियम सख्त हैं। सामान्य तौर पर क्यूरेटिव याचिका पर भी सुनवाई न्यायाधीश सर्कुलेशन के जरिये चैंबर में ही करते हैं। इस याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ में तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और बाकी फैसला देने वाले न्यायाधीश होते हैं। मसलन, अगर दो न्यायाधीशों का फैसला है तो उस मामले में क्यूरेटिव याचिका पर तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश और दो फैसला देने वाले न्यायाधीश समेत कुल पांच न्यायाधीश सुनवाई करेंगे।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अजय वर्मा बताते हैं कि क्यूरेटिव याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से फैसले में उपचार की मांग करते हुए तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान दिलाया जाता है। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता की सिफारिश पर ही दाखिल की जा सकती है। अगर क्यूरेटिव याचिका खारिज हो जाए तब दया याचिका का प्रावधान है। दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष दाखिल की जाती है। इस याचिका के निर्णय के दौरान राष्ट्रपति केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगते हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाती है। इसे देखने के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजती है और फिर राष्ट्रपति इस पर फैसला लेते हैं। दया याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी होता है। डेथ वारंट जारी करने और फांसी पर लटकाए जाने के बीच 15 दिन का अंतराल होना चाहिए।

'ठोस सुबूतों व उचित कारणों के आधार पर ही हो गिरफ्तारी'

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस अपनी मनमर्जी अनुसार नियम कानून को ताक पर रखकर किसी को न तो गिरफ्तार कर सकेगी और न ही हिरासत में रख सकेगी। ऐसा करने पर तुरंत उनके परिजनों, दोस्तों अथवा रिश्तेदारों को जानकारी देनी होगी। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने एडवाइजरी जारी करते हुए महकमे को साफ कहा है कि ठोस सुबूतों व उचित कारणों के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस अधिकारी मनमर्जी से जब चाहे तब किसी को गिरफ्तार कर लें या हिरासत में ले लें। आदेश का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना तो माना ही जाएगा साथ ही जांच अधिकारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

पिछले कई सालों से थानों में हिरासत में मौत हो जाने व अथवा जांच अधिकारी द्वारा मनमर्जी से किसी को भी हिरासत में लेने को लेकर पुलिस आयुक्त को अक्सर शिकायतें मिल रही थीं। इससे महकमे की बदनामी हो रही थी।

2008 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त वाईएस डडवाल ने गिरफ्तारी व हिरासत में रखने के नियम-कानून को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ साल बाद ही आदेश की अनदेखी होने लगी थी। अब 11 साल बाद पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने इस मामले में एडवाइजरी जारी की है। इसकी प्रति सभी विशेष आयुक्त व संयुक्त को भेज दी गई है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि ठोस सुबूत व उचित कारण पर ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। केवल आरोप लगाने पर पुलिस अधिकारी अपने मन मुताबिक किसी को हिरासत में नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 21 व 22 (1) में लोगों को मूलभूत अधिकार मिला हुआ है कि अगर किसी को हिरासत में रखा गया है अथवा गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस को उनके परिजनों, रिश्तेदारों अथवा दोस्तों को बताना होगा। उसकी एंट्री केस डायरी में कारण के साथ दर्ज करना जरूरी है। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के नाम व रैंक भी केस डायरी में स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

हिरासत में रखे गए आरोपित का हर 48 घंटे पर डॉक्टर से मेडिकल जांच कराना होगा। गिरफ्तारी का मेमो तुरंत इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा।

अमूल्य पटनायक

किस आरोपित को कहां से पकड़ा गया है जांच अधिकारी को तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी देनी होगी। साथ ही नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी करना होगा। दहेज प्रताड़ना और ऐसे अपराध जिसमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है, ऐसे मामले में आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। गिरफ्तार करना अगर बहुत जरूरी है तभी गिरफ्तार किया जाए। दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपितों को गिरफ्तार न करने के बारे में दो हफ्ते के अंदर जांच अधिकारी को एरिया मजिस्ट्रेट को बताना होगा।

आदेश में आयुक्त ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक 2011 के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि दहेज प्रताड़ना का केस बिना डीसीपी व एडिशनल डीसीपी की मंजूरी के दर्ज नहीं होना चाहिए। दहेज प्रताड़ना के मामले में जांच के बाद ही डीसीपी व एसीपी की मंजूरी के बाद आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए। मामले में पहले दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की जाए। समझौता न हो पाने पर सभी पहलुओं की जांच करने के बाद ही एफआइआर दर्ज की जाए। अगर बुजुर्गों के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़, दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप है तो जांच अधिकारी बारीकी से जांच करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर गिरफ्तारी की जरूरत है तो जांच अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बुजुर्ग की उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुए गिरफ्तारी का निर्णय लें। यह भी देखा जाए कि गिरफ्तार न करने पर बुजुर्ग भाग सकते हैं या नहीं।

मालिकाना हक देने से पहले आपत्तियां मांगेगा डीडीए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

1731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को अपने घरों के मालिकाना हक के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। यह इंतजार एक हफ्ते से एक पखवाड़े तक का हो सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पहले हर संपत्ति पर आपत्तियां मंगाएगा उसके बाद ही उसकी कन्वेंस डीड जारी करेगा।

जानकारी के मुताबिक डीडीए द्वारा तैनात चार निजी एजेंसियों ने सोमवार से पोर्टल पर आवेदन कर रहे लोगों के घरों पर जाकर जीयो को-आर्डिनेट और की-प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में वेबसाइट पर डीडीए की तरफ से दो से तीन दिनों में एक लिंक भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

यहां सभी आवेदकों की संपत्ति का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति पर आपत्ति है तो वह उक्त लिंक के माध्यम से उसे दर्ज करवा सकता है। अधिकारियों के अनुसार आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कम से कम एक हफ्ते और अधिक से अधिक पंद्रह दिनों का समय दिया जा सकता है। इस दौरान डीडीए के अधिकारी उक्त संपत्ति पर जाकर उसका मुआयना करेंगे। यदि आवेदक द्वारा दी गई दी जानकारी सही पाई गई और उक्त संपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं आई तो उसके आवेदक को कन्वेंस डीड उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर किसी ने ऐतराज जताया तो दोनो पक्षों को सुनने के बाद 180 दिनों में फैसला लिया जाएगा। फैसला नहीं होने पर उक्त आवेदन को रद कर दिया जाएगा। ऐसे में आवेदक दोबारा से मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकता है। डीडीए के अनुसार पूरा काम वेबसाइट के माध्यम से ही होना है। लोगों की मदद के लिए 25 हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। अभी तक वेबसाइट पर 25 हजार से अधिक लोग पंजीकरण करवा चुके हैं, लेकिन जीयो को-आर्डिनेट और की-प्लान का काम सोमवार से ही शुरू हुआ है।

झुग्गी वाले 65 हजार परिवारों को मिलेगा पक्का घर : केजरीवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : झुग्गियों में रहने वाले 65 हजार परिवारों को मंगलवार को दिल्ली सरकार की ओर से सर्वे सर्टिफिकेट दिया गया। अंबेडकर नगर में आयोजित समारोह में लाभार्थियों को सर्टिफिकेट देने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है, उन्हें झुग्गी के पास ही पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। तब तक झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। शेष बचे लोगों को भी जल्द ही सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। दिल्ली के हर नागरिक को इज्जत की जिंदगी देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं।

शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आप और भाजपा में यह अंतर है कि गुजरात के सीएम ने अपने लिए 191 करोड़ रुपये का हेलीकॉप्टर खरीदा है। जबकि दिल्ली के सीएम ने महिलाओं का बस में सफर मुफ्त करने के लिए 140 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस दौरान अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त व देवली से विधायक प्रकाश जारवाल, निगम पार्षद दिनेश कुमार व प्रेम चौहान भी मौजूद रहे।

झुग्गी में रहा हूं, इसलिए आपका दर्द पता है : केजरीवाल ने कहा- सीएम बनने से पहले एनजीओ के माध्यम से उन्होंने झुग्गियों में काम किया है। कई महीने खुद झुग्गियों में रहा हूं। इसलिए झुग्गी वालों का दर्द पता है। कई बार मैं और मनीष सिसोदिया झुग्गी बचाने के लिए बुलडोजर के नीचे लेटे हैं। झुग्गी वालों को हमेशा डर रहता है कि डीडीए वाले झुग्गियां तोड़ देंगे। बाकी नेता वोट लेने झुग्गी वालों के पास आते हैं और जीतने के बाद झुग्गियां तोड़ने के लिए बुलडोजर भेजते हैं। लेकिन, हम झुग्गियों में सड़कें, सीवर व गलियां बना रहे हैं।

ऐसा है सर्टिफिकेट : सर्वे सर्टिफिकेट में झुग्गी का नंबर, झुग्गी में रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के साथ फोटो, कोड संख्या, सर्वे कोड संख्या और लाभार्थी परिवार के वोटर आइडी कार्ड का नंबर दर्ज है। डूसिब ने गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए 675 झुग्गी बस्तियों में सर्वेक्षण किया। यह सर्वे गरीबों के लिए घरों के निर्माण की मांग का आकलन करने में सरकार की मदद करेगा।

मेरी क्रिसमस...

क्रिसमस की पूर्वसंध्या पर मंगलवार को गोल डाकखाने के पास स्थित चर्च में कैंडल जलाते श्रद्धालु। ध्रुव कुमार

जेवर एयरपोर्ट

प्रभावित तालाबों के लिए तीन गांव में जमीन चिह्नित

दो गुना क्षेत्रफल के होंगे विकसित होने वाले तालाब, जिला प्रशासन ने आकलपुर, फलैदा बांगर, तकीपुर बांगर में चिह्नित की जमीन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित तालाबों को तीन गांवों में बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने तालाबों को विकसित करने के लिए यमुना प्राधिकरण को पत्र भेजा है। यह तालाब दोगुने क्षेत्रफल के होंगे। तालाब विकसित होने से इलाके में भूजल स्तर के साथ साथ ग्रामीणों को सुविधा होगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दयानतपुर, रोही परोही, बनबारीवास, किशोरपुर, रन्हेरा गांव की 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। इसमें अस्सी फीसद जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। शेष जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रशासन ने किसानों से मुआवजा उठाने व जमीन पर कब्जा देने की अपील की है।

जिस जमीन पर जेवर एयरपोर्ट प्रस्तावित है, वहां पर एक दर्जन से अधिक तालाब हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल 3.8510 हेक्टेयर है। जमीन अधिग्रहण के लिए इन तालाबों को दूसरी जमीन पर विकसित किया जाना है। जिला प्रशासन ने इसके लिए तीन गांवों की जमीन चिह्नित की है। यह तालाब आकलपुर, फलैदा बांगर, तकीपुर बांगर गांव में होंगे। इनका कुल क्षेत्रफल 6.3370 हेक्टेयर होगा। आकलपुर व फलैदा बांगर गांव में बंजर व तकीपुर गांव में नवीन परती जमीन पर तालाब बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने तालाब निर्माण की कार्रवाई के लिए यमुना प्राधिकरण को पत्र भेज दिया है। एयरपोर्ट की वजह से तीन माइनर नहर भी प्रभावित हो रही हैं। माइनर का रास्ता बदलकर उसे एयरपोर्ट क्षेत्र से बाहर किया जाएगा। सिंचाई विभाग इसका प्लान पहले ही शासन को भेज चुका है। यह कार्य विभाग अपने बजट से कराएगा।

जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत जमीन पर मौजूद तालाबों को दूसरी जगह पर विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने तालाबों के लिए तीन गांवों में जमीन चिह्नित की है। नए तालाब दोगुना क्षेत्रफल के होंगे।

-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

एनएमआरसी से एलएमआरसी को जाएगी एयरपोर्ट मेट्रो की डीपीआर

जासं, ग्रेटर नोएडा : जेवर एयरपोर्ट मेट्रो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) से वापस लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एलएमआरसी) को भेजी जाएगी। एलएमआरसी जेवर एयरपोर्ट मेट्रो के लिए फंडिंग पैटर्न तय करेगा। शासन ने डीपीआर को अध्ययन एवं फंडिंग पैटर्न तय करने के लिए एनएमआरसी को भेजा है। फंडिंग पैटर्न तय होने पर मेट्रो परियोजना पर काम आगे बढ़ेगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो कनेक्टिविटी देने के लिए यमुना प्राधिकरण ने डीएमआरसी से डीपीआर तैयार कराई थी। डीएमआरसी ने एक्वा लाइन मेट्रो के नॉलेज पार्क दो स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने पर रिपोर्ट दी है। प्राधिकरण ने मेट्रो के लिए फंडिंग पैटर्न तय करने के लिए शासन को डीपीआर भेजी थी। शासन ने इस रिपोर्ट को एनएमआरसी को अध्ययन व फंडिंग पैटर्न तय करने के लिए भेजा था। हालांकि सरकार ने प्रदेश में विकसित होने वाली मेट्रो परियोजना के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को नोडल एजेंसी बना रखा है। इसलिए यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट मेट्रो की डीपीआर को एनएमआरसी से लेकर एलएमआरसी को भेजने का आग्रह किया है।

पंजाबी बाग में मेट्रो बदलने को मुफ्त मिलेगी ई-बस की सुविधा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पंजाबी बाग में ग्रीन लाइन व पिंक लाइन के स्टेशन के बीच एक इलेक्ट्रिक बस मेट्रो फीडर के रूप में चलेगी। इसका मकसद यात्रियों को पंजाबी बाग में मेट्रो इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध कराना है। ताकि, ग्रीन लाइन के स्टेशन पर उतरकर पिंक लाइन की मेट्रो पकड़ने के इच्छुक लोग आसानी से दूसरे स्टेशन पर पहुंच सकें। मेट्रो बदलने वाले यात्री फीडर बस में निशुल्क सफर कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि यह सुविधा जल्द शुरू होगी।

दरअसल, ग्रीन लाइन (कीर्ति नगर-इंद्रलोक-बल्लभगढ़) पर पंजाबी बाग स्टेशन है। वहीं पिंक लाइन (मजलिस पार्क-शिव विहार) पर पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। ये दोनों स्टेशन थोड़ी दूरी पर हैं। इस वजह से पंजाबी बाग में अभी तक इंटरचेंज की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना है। इसमें 32 सीटें उपलब्ध होंगी।

हालांकि पंजाबी बाग में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉल्टिंग स्टेशन बनाने की भी योजना है। इसके तहत पंजाबी बाग चौराहे के नजदीक हॉल्टिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत ग्रीन लाइन के कॉरिडोर पर स्टील का प्लेटफार्म व हॉल्टिंग स्टेशन बनेगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ मेट्रो बदलने के लिए किया जाएगा। इसके लिए करीब 230 मीटर का फुटओवर ब्रिज (वॉक-वे) भी बनेगा, जो हॉल्टिंग स्टेशन से पिंक लाइन के पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन के साथ जुड़ा होगा।

35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 4,320 शहरी निकायों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर लिया है। इनमें से 4,167 शहरी निकायों की तीसरे पक्ष से जांच भी करा ली गई है।

देश को जल्द मिलेगा सीडीएस

1999 कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा समीक्षा को लेकर गठित समिति ने सीडीएस का सुझाव दिया

26 दिसंबर देश के पहले सीडीएस का हो सकता है ऐलान, बिपिन रावत सबसे आगे

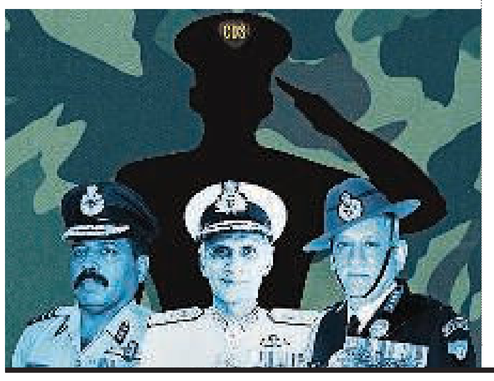

अलग-अलग तरह की सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे देश को बहुत जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) मिलेगा जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के साथ रणनीति तय करेगा। चार महीने पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी। चार स्टार जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ बनाया जाएगा। इसे लेकर काफी समय से मंथन चल रहा था, लेकिन अब जाकर यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की बात कही थी तभी से माना जा रहा था कि इस पद को लेकर सरकार जल्द कोई कदम उठा सकती है।

इसलिए पड़ी जरूरत

- तीनों सेनाओं को समान गति से आगे बढ़ाने के लिए।
- युद्ध और सुरक्षा की परिस्थितियां बदल रही हैं।
- सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रही है।
- फैसले लेने में सैन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।
- सेनाओं के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देने के लिए।
- भारत अब अलग-अलग दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ना चाहता।

यह है प्रस्ताव

माना जा रहा है कि सीडीएस रक्षा और इससे जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकीकृत सलाहकार के रूप में काम करेंगे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय में एक नए विभाग 'डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स' का गठन होगा और सीडीएस इसके सचिव होंगे। इस विभाग को केवल सैन्य क्षेत्र का ही काम देखना होगा, जब रक्षा विभाग देश के अन्य बड़े मामलों से निपट रहा हो। उस वक्त सशस्त्र बल इस विभाग की सीमा में होगा। साथ ही सैन्य मामलों के लिए विषय विशेषज्ञता होगी।

उद्देश्य

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ का मकसद देश की सेनाओं को ट्रेनिंग, इंतजाम, स्टॉफ और विभिन्न अभियानों के लिए एकीकृत करना है। इसके साथ ही सैन्य सलाह की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे राजनीतिक नेतृत्व को इन सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। साथ ही सैन्य मामलों में विषय विशेषज्ञता विकसित करना है।

भूमिका और जिम्मेदारी

तीनों मुखिया सेवा संबंधी विशेष मामलों के बारे में रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे। सीडीएस किसी भी कमांड के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों को खुफिया सूचनाओं की जानकारी देंगे। सीडीएस रक्षा संपदा परिषद और रक्षा प्लानिंग कमेटी के सदस्य होंगे। साथ ही वह ऑपरेशन, ट्रेनिंग, कम्यूनिकेशन और मेंटिनेंस जैसी अन्य बातों के लिए तीनों सेनाओं के एकीकरण पर काम करेंगे।

सबसे बड़ा फायदा

किसी भी युद्ध के वक्त तीनों सेनाओं का एकीकरण बहुत बड़ी चुनौती होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ की नियुक्ति का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय रहेगा और सेनाएं बेहतर ढंग से लड़ सकेंगी। पिछले युद्धों में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का अभाव देखा गया था। माना जा रहा है कि इससे काफी असर पड़ेगा।

कारगिल के बाद आया प्रस्ताव

1999 में कारगिल युद्ध के बाद देश की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए थे। युद्ध के बाद बनी समिति ने रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में सीडीएस की नियुक्ति का सुझाव दिया था।

26 दिसंबर को हो सकती है घोषणा

सूत्रों के मुताबिक, सरकार 26 दिसंबर को पहले सीडीएस के नाम की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस हो सकते हैं। बिपिन रावत 16 दिसंबर, 1978 को सेना की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए थे। वह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने उनके स्थान पर नए सेनाध्यक्ष होंगे। सीडीएस पद की दौड़ में जनरल रावत के बाद वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं।

मोदी सरकार के दौरान नहीं खुले डिटेंशन सेंटर : शाह

रखा पक्ष ▶ एनआरसी और सीएए पर लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने में जुटी सरकार

सीएए बलूच, अहमदिया, रोहिंग्या को भारत की नागरिकता से नहीं रोकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और डिटेंशन सेंटर को लेकर फैलाई जा रही कई भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साफ किया कि डिटेंशन सेंटर को लेकर कही जा रही बातें पूरी तरह निराधार हैं और मोदी सरकार के दौरान कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया गया है। इसी तरह सरकार की ओर से प्रश्नोत्तर जारी कर साफ किया कि सीएए आने के बाद भी रोहिंग्या, अहमदिया और बलूचों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करने का रास्ता बंद नहीं होगा। नागरिकता प्राप्त करने का नियम है और वह इसके तहत आवेदन कर सकते हैं।

डिटेंशन सेंटर पर स्थिति साफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि विदेशी नागरिकों के वीजा शर्तों के उल्लंघन या किसी अन्य नियम के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखे जाने का प्रावधान है। ऐसे विदेशी नागरिकों को वापस अपने देश भेजे जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। इसके लिए देश के कुछ भागों में डिटेंशन सेंटर पहले से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विदेशी नागरिकों को प्रत्यर्पण के पहले डिटेंशन सेंटर में रखे जाने का प्रावधान पूरी दुनिया में है। उन्होंने साफ किया कि इसका एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है।

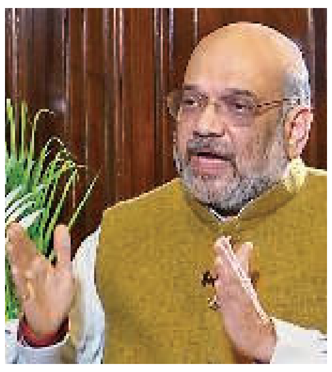

नई दिल्ली में मंगलवार को सीएए, एनआरसी, एनपीआर और डिटेंशन सेंटर के मामले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि संयुक्त राष्ट्र के प्रविधानों के तहत भारत अपने यहां शरणार्थियों की देखभाल का दायित्व पूरी तरह वहन करने को तैयार है और इससे पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। यहां फिलहाल दो लाख श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती, 15 हजार से अधिक अफगान, 20-25 हजार रोहिंग्या समेत सैकड़ों अन्य विदेशी शरणार्थी रह रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन देशों में कभी स्थिति सुधरने के बाद ये शरणार्थी अपने देशों में वापस चले जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी को सीएए के तहत नागरिकता देने की जरूरत स्पष्ट करते हुए सरकार की ओर से बताया गया कि इस कानून में इस सच्चाई को स्वीकार किया गया है कि इन तीन देशों में अल्पसंख्यकों के लिए उत्पीड़न का माहौल सुधरने वाला नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की अफवाहों पर सरकार ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि सीएए का किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना-देना नहीं है। किसी भी विदेशी नागरिक को देश से बाहर भेजने (चाहे वह किसी भी धर्म या देश का हो) की प्रक्रिया फॉरनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत की जाती है। ये दोनों कानून, सभी विदेशियों (चाहे वे किसी भी देश या धर्म के हों) को देश में प्रवेश करने, रिहाइश, भारत में घूमने-फिरने और देश से बाहर जाने की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके तहत राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के पास अधिकार होता है, जिससे वे गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशी की पहचान कर सकता है। उसे हिरासत में रख सकता है और उसके देश भेज सकता है। देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है, जब कोई व्यक्ति विदेशी साबित हो जाए। यही नहीं, संबंधित देश के दूतावास/उच्चायोग को जानकारी देकर उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था की जाती है।

एनपीआर को एनआरसी से जोड़ने की कोशिश कर रही सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने इसे खतरनाक और संविधान की धर्मनिरपेक्ष पहचान के खिलाफ करार दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरसी को लेकर रामलीला मैदान में जो कहा था, उससे भी बड़ा झूठ अमित शाह का यह कहना है कि एनपीआर और एनसीआर में कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में एनआरसी लागू करने को लेकर सरकार में चर्चा नहीं हुई है। जबकि, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा। 2014 में भी तत्कालीन गृह राज्यमंत्री ने इसी तरह का बयान दिया था।

माकन ने दावा किया कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीआर की दिशा में एनपीआर पहला कदम है। उन्होंने इसके समर्थन में गृह मंत्रालय की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट भी दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। माकन ने कहा कि सरकार अपने ही बनाए जाल में फंस गई है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर 2021 की जनगणना के दौरान एनपीआर की इसी तरह कराया जाता है तो यह आपत्तिजनक है। अमित शाह लोगों की नाराजगी के चलते एनआरसी पर गलतबयानी कर रहे हैं।

माकन ने माना कि कांग्रेस सरकार ने ही एनपीआर को शुरू किया था, लेकिन उसने इसे एनआरसी से नहीं जोड़ा। उन्होंने पूछा कि एनपीआर को एनआरसी से कौन जोड़ रहा है? उन्होंने कहा कि एनपीआर अपने आप में सही है। लेकिन जब उसे एनआरसी से जोड़ा जाता है तो वह खतरनाक बन जाता है। तब वह मानवाधिकारों के खिलाफ भी हो जाता है।

जनता से धोखाधड़ी कर रही केंद्र सरकार : तृणमूल

जागरण संवाददाता, कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एनपीआर की आड़ में देश की जनता से धोखाधड़ी करने और उन्हें बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। तृणमूल ने कहा, एनपीआर एनआरसी की दिशा में पहला कदम है। तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, केंद्र सरकार जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। एनपीआर का काम जनगणना के साथ-साथ चलेगा, जिससे लोग उलझन में पड़ जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह जनगणना है और एनआरसी की ओर पहला कदम नहीं है।

नए मानकों पर काम करेंगे अफसर : राजनाथ सिंह

▶ रक्षा मंत्री बोले-हमारी नीति न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन

▶ सीडीएस को कैबिनेट की मंजूरी मिलने को भी बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र के 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन' की अवधारणा पर व्यापक सावधानी के साथ वित्तीय प्रबंधन के मानक तैयार किए गए हैं। इन मानकों के आधार पर ही अफसरों और प्रणालियों को काम करना होगा। उन्होंने सीडीएस के कैबिनेट की मंजूरी मिलने को भी ऐतिहासिक फैसला बताया।

डीआरडीओ भवन में रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग की ओर से आयोजित समग्र वित्तीय सलाहकारों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि वित्त प्रबंधन के लिए सिस्टम को और भी सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ अंगीकार किया जा रहा है। सरकार के कामकाज में न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की विचारधारा नजर आएगी। इसी लिहाज से सरकार की कार्य प्रणालियों को और प्रभावी और सक्षम बनाया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त किसी भी परिवार, समाज, संस्थान या देश की रीढ़ होता है। रक्षा मंत्रालय के मद में देश के कुल बजट का एक-चौथाई हिस्सा आता है। और एकीकृत वित्त प्रबंधन से किसी भी विभाग या मंत्रालय को मजबूती प्रदान करती है। कोई भी मंत्रालय अपने उद्देश्य तभी हासिल कर सकता है जब वह अपनी कार्य संबंधी जरूरतों से कोई समझौता किए बिना बजटीय संसाधनों का उचित प्रबंध कर सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस दिशा में सरकार ने कई अनूठी पद्धतियां अपनाने की पहल की है। जैसे जन वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में रक्षा मंत्रालय ने फंड का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। और कोष के अनुपयोग का चलन लगभग खत्म हो गया है। इसीलिए इन तीन सालों में वित्तीय प्रबंधन से पूंजी और राजस्व हासिल करने में सफलता मिली है। इसके आधार पर ही सशस्त्र सेनाओं ने अपने बल पर ही 500 करोड़ रुपये के साजोसामान हासिल कर लिए हैं। इससे उनके अभियानों की क्षमता भी बढ़ गई है।

नई दिल्ली में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय के वित्त प्रभाग की ओर से आयोजित समग्र वित्तीय सलाहकारों की कार्यशाला को संबोधित किया। प्रेट्र

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) को कैबिनेट की मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस कदम से तीनों सशस्त्र सेनाओं के आपसी तालमेल को बढ़ावा मिलेगा।

प्रकाशन उद्योग पंजीकरण बिल के मसौदे पर सुझाव देने की समयसीमा बढ़ाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक विधेयक के मसौदे पर सुझाव देने की समयसीमा 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि यह विधेयक ब्रिटिश काल के कानून की जगह लेगा। इस विधेयक के तहत समाचार वेबसाइटों के लिए भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक से खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाएगा।

प्रस्तावित प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण (आरपीपी) विधेयक 2019 पुराने प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह लेगा। इस विधेयक में प्रकाशक पर मुकदमा चलाने के पूर्व के प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें नव सृजित प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 नवंबर को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भागीदारों एवं आम लोगों से विधेयक के मसौदे पर एक महीने के भीतर विचार मांगे थे। मंत्रालय ने कहा है कि टिप्पणी और सुझाव सौंपने की समयसीमा 20 जनवरी 2020 तक बढ़ाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने प्रकाशकों, लेखकों के हितों के संरक्षण की दिशा में तमाम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में सरकार नए विधेयक के जरिये और सुधार करना चाहती है।

वाजपेयी की जयंती के पूर्व 6,000 करोड़ की अटल भूजल योजना मंजूर

▶ पहले चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व हरियाणा समेत सात राज्यों के 78 जिलों को मिलेगा योजना का लाभ

नई दिल्ली, आइएएनएस : पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के एक दिन पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपये की अटल भूजल प्रबंधन योजना (अटल जल) को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण क्षेत्र में भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली अटल भूजल प्रबंधन योजना का लाभ पहले चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक को मिलेगा। इन राज्यों के 78 जिलों की 8,350 ग्राम पंचायतों को पहले इसका लाभ मिलेगा।

अटल भूजल प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन पांच वर्षों में (वर्ष 2020-21 से 2024-25) किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक सहभागिता के माध्यम से भूजल का प्रबंधन करना है। योजना की आधी राशि विश्वबैंक के कर्ज के रूप में होगी, जिसे केंद्र सरकार अदा करेगी। वहीं, योजना की बाकी आधी राशि सामान्य बजट में केंद्रीय मदद के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। अटल भूजल प्रबंधन योजना (अटल जल) के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनमें राज्यों में सतत भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना और नेटवर्क की निगरानी का विकास, क्षमता वृद्धि और जल उपभोक्ता संगठनों को सशक्त करना शामिल है।

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को बताया कि अटल भूजल प्रबंधन योजना (अटल जल) के तहत सतत भूजल प्रबंधन किया जाएगा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है।

सामरिक महत्व की रोहतांग दर्रा सुरंग को दिया जाएगा वाजपेयी का नाम

प्रेट्र के अनुसार, रोहतांग दर्रे के नीचे बनने वाली सामरिक महत्व की सुरंग का नामकरण बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। इस सुरंग को बनाने का निर्णय तीन जून 2000 को लिया गया था, तब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। रक्षा मंत्रालय ने बताया, 'सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को सम्मान देने का फैसला किया है। रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरने वाली इस सुरंग का नामकरण बुधवार को स्वर्गीय वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा।' तीन हजार मीटर की उंचाई पर 8.8 किलोमीटर की लंबाई वाली यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है।

नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी को डी लिट से सम्मानित करेगा सीयू

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कलकत्ता विश्वविद्यालय अपने वार्षिक दीक्षा समारोह में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। विवि के वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन 28 जनवरी 2020 को होगा। मंगलवार को विश्वविद्यालय की कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कलकत्ता विवि की सर्वोच्च निर्णायक इकाई ने वर्ष 2020 में होने वाले दीक्षा समारोह में अभिजीत बनर्जी को डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित करने का फैसला किया है। इस संबंध में विवि ने प्रबंधन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई थी। सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव को अभिजीत बनर्जी ने स्वीकार कर लिया है। समारोह में प्रख्यात खगोलविद जेवी नर्लिकर को सर आशुतोष मुखर्जी मेमोरियल मुखर्जी मेडल, वैज्ञानिक समीर के ब्रह्मचारी, अरूप कुमार रायचौधरी व पार्थ प्रतिम मजूमदार को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय मेडल और बांग्ला के प्रख्यात कवि अरबिंदो गुहा को मरणोपरांत और प्रखर लेखक मनोरंजन व्यापारी को रवींद्रनाथ टैगोर मेमोरियल मेडल की उपाधि दी जाएगी।

अभिजीत बनर्जी फाइल

धार्मिक खर्च में कटौती कर बनाएंगे श्रेष्ठ स्तर का स्कूल

▶ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित जिला परिषद के स्कूल को अपग्रेड करने का किया फैसला

▶ 10 लाख रुपये से स्कूल की आंगनबाड़ी और कंप्यूटर प्रयोगशाला में विकसित हो चुकी हैं सुविधाएं

औरंगाबाद, प्रेट्र : महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक गांव के लोगों ने ऐसा फैसला किया है, जो उनके भविष्य की बुनियाद मजबूत करेगी। ग्रामीणों ने धार्मिक कार्यों पर होने वाले व्यय में कटौती करके उस पैसे से गांव में स्थित जिला परिषद के स्कूल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का फैसला किया है। ग्रामीणों के इस फैसले की काफी तारीफ भी हो रही है। यह एक तरह से अपनी तरह का अनूठा फैसला है।

जिला परिषद की कार्यपालक अधिकारी (ईओ) पवनीत कौर ने मंगलवार को बताया, 'पोखरी के ग्रामीणों ने स्कूल परिसर के विस्तार के लिए दो एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया है। अभी स्कूल का क्षेत्रफल करीब 20 हजार स्क्वायर फीट (करीब 0.45 एकड़) है और वहां करीब 240 बच्चे पढ़ते हैं। इस काम में जिला परिषद भी खुले मन से सहयोग करेगी।' उन्होंने बताया कि इस तरह की पहल से गांव में तरक्की भी आएगी और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी।

कार्य की अगुआई करने वाले पोखरी गांव निवासी बालासाहेब भोसले ने कहा, 'स्कूल और उसकी सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए ग्रामीणों ने तीन महीने पहले धार्मिक कार्यों में होने वाले खर्चों में कटौती का फैसला किया था।'

ग्रामीण भागवत सप्ताह समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में टेंट और मिठाई पर होने वाले खर्च में कटौती कर रहे हैं। इस कटौती के पैसे से गांव को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। भोसले ने बताया, 'विभिन्न धार्मिक उत्सवों के दौरान एक जगह पर दाल तैयार की जाएगी, जबकि रोटी ग्रामीणों के घरों से मंगाई जाएगी। बचाई गई राशि स्कूल को अपग्रेड करने में लगाई जाएगी।'

उन्होंने बताया कि स्कूल की आंगनबाड़ी और कंप्यूटर प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए अब तक 10 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इनमें 50 हजार रुपये की मदद ग्राम पंचायत की तरफ से दी गई थी, जबकि बाकी राशि गांव में चंदे से इकट्ठा की गई। भोसले ने कहा, 'गांव में करीब 450 घर हैं। स्कूल को अपग्रेड करने के लिए प्रत्येक घर से कम से कम पांच हजार रुपये का योगदान तय किया गया है। जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन होगी, उन्हें प्रति एकड़ एक हजार रुपये ज्यादा देना होगा। इसके अलावा सरकार और निजी कंपनियों से भी सहायता पाने की कोशिश की जा रही है।'

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर

नई दिल्ली, आइएएनएस : शी-बॉक्स पोर्टल पर दर्ज केसों के अनुसार कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। यह तथ्य इस धारणा के खिलाफ है कि यह राज्य महिलाओं के लिए सुरक्षित है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पोर्टल पर दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों के आंकड़े जारी किए हैं। सेक्सुअल हैरैसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स या शी-बॉक्स एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जिसे सरकार ने महिलाओं द्वारा कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए विकसित किया है। शी-बॉक्स पोर्टल पर जैसी ही शिकायत दाखिल की जाती है, यह सीधे उस संबंधित प्राधिकारी तक पहुंच जाती है जो इस मामले में कार्रवाई करने में सक्षम होता है। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 203 मामलों का निपटारा किया गया है जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के मामले शामिल हैं। वर्ष 2017 से शी-बॉक्स के जरिये निजी व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों में सर्वाधिक 82 महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश से 65, दिल्ली से 50 और तमिलनाडु से 48 शिकायतें दर्ज हुईं।

मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, 'ऐसे भी राज्य हैं जहां से एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन राज्यों में कोई शिकायत ही नहीं है। वहां कई मामले हैं, लेकिन महिलाएं कई बार शिकायत दर्ज नहीं करातीं। राज्य सरकारों को महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे आगे आएं और अपराध दर्ज कराएं।'

स्वच्छता

ओडीएफ घोषित 4,167 शहरी निकायों की तीसरे पक्ष से जांच भी करा ली गई है। लेकिन, बंगाल के 52 शहरों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है

बंगाल छोड़ देश के बाकी शहरी निकाय हुए ओडीएफ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ निर्धारित लक्ष्य से अधिक घरों में शौचालयों का हुआ निर्माण

▶ 4,320 निकायों ने खुद को खुले में शौच मुक्त किया घोषित

प्रतीकात्मक फोटो

शहरी स्वच्छता अभियान अपने निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने में सफल रहा है। इससे देश को खुले में शौच मुक्त बनाने में मदद मिली है। बंगाल को छोड़कर देश के बाकी राज्यों के शहरी निकायों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर लिया है। शहरी स्वच्छता अभियान के दावों की तीसरे पक्ष से जांच भी लगभग पूरी करा ली गई है।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश के शहरी निकायों के 96 फीसद वार्डों में हर घर से कूड़ा-कचरा उठाने का बंदोबस्त कर लिया गया है। इसके लिए 60 फीसद शहरी निकायों में कचरे के निपटान का प्रबंधन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 65.81 लाख घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि लक्ष्य 59 लाख शौचालय बनाने का था।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में उत्साहजनक सफलता मिली है। देश के 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 4,320 शहरी निकायों ने खुद को ओडीएफ घोषित कर लिया है। इनमें से 4,167 शहरी निकायों की तीसरे पक्ष से जांच भी करा ली गई है। लेकिन, बंगाल के 52 शहरों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत दो अक्टूबर, 2014 को हुई थी। सरकार ने दो अक्टूबर, 2019 को ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों को ओडीएफ घोषित कर दिया है। लेकिन, इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट न हो पाने की वजह से इसे फिलहाल छोड़ दिया गया है। साथ ही बंगाल के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रदर्शन को देखते हुए यह लंबित है।

मंत्रालय के जारी आंकड़ों में कहा गया है कि 819 को ओडीएफ प्लस और 312 शहरों को ओडीएफ डबल प्लस घोषित किया गया है, जिससे शहरों में स्वच्छता और शौचालयों के उपयोग और उनकी सतत सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 96 फीसद शहरी वार्डों में कूड़ा हर घर से उठाया जाता है। जबकि 60 फीसद नगरीय कूड़े की प्रोसेसिंग की जाती है। स्वच्छता अभियान की सफलता को जांचने के लिए 12 मानक निर्धारित किए गए हैं।

इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई और मैसूर पांच सितारा कूड़ा मुक्त शहर घोषित हो चुके हैं, जबकि 57 शहरों को तीन स्टार घोषित किया गया है और चार शहरों को एक स्टार बनाया गया है। स्वच्छता अभियान में अब 100 फीसद सीवरेज को साफ कर दोबारा उपयोग पर जोर दिया जाएगा।

बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी होगी जांच

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

सीबीआइ इस साजिश में बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगी। बैंक ने 17 अक्टूबर, 2019 की शिकायत में पांच आरोपितों का जिक्र किया है, जिनमें तीन कंपनियों के नाम गारंटर हैं। इनके नाम हैं-खट्टर ऑटो इंडिया, कारनेशन रियिलटी और कारनेशन इंश्योरेंश ब्रोकिंग कंपनी। हालांकि, जांच के दौरान इनमें किसी के धोखाधड़ी में शामिल होने का पता नहीं चला। इसलिए एफआइआर में इनका नाम नहीं है।

खट्टर ने व्यापार घाटा बताया : इस पूरे प्रकरण में खट्टर ने कारनेशन को व्यापार घाटे का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि ऑडिट के दौरान भी कुछ गलत नहीं पाया गया। बैंक ने तय प्रक्रिया के तहत सीबीआइ से संपर्क किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने छापेमारी भी की। लेकिन, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो जाने के बाद हम आरोपों से बरी हो जाएंगे।

कह के रहेंगे माधव जोशी

9 दलबदलू विधायकों में सिर्फ दो ही जीत हासिल कर सके हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में। जीतने वालों में भानु प्रताप शाही और जयप्रकाश भाई पटेल शामिल हैं। सात को हार मिली है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 25 दिसंबर 2019

29 को सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत

नई पारी की तैयारी ▶ राजभवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया

झामुमो विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता

राज्य ब्यूरो, रांची

29 दिसंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में होगा। इसके लिए एक बजे का समय निर्धारित किया गया है। मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर हेमंत ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और शपथ की तारीख की सूचना दी। शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ-साथ दूसरे राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया जाएगा।

नई सरकार के गठन को लेकर मंगलवार सुबह से ही इस बाबत गतिविधियां तेज हो गई थीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को विधिवत नेता चुनने की घोषणा की गई। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के आवास पर हुई बैठक में दल के सारे 30 विधायक मौजूद थे। इसके बाद शाम पांच बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक आलाकमान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में हुई। शाम सात बजे एक बार फिर विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चाप्रमुख शिबू सोरेन के आवास का रुख किया। यहां विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में सारे विधायकों ने उपस्थिति दर्ज कराई।

रांची में मंगलवार को झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह (बाएं), झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन (बाएं से दूसरे) और राजद नेता तेजस्वी यादव (दाएं) भी मौजूद रहे। जागरण

झामुमो को मिला झाविमो का साथ

हेमंत सोरेन लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं। मंगलवार को इसी क्रम में वह झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी के आवास पर पहुंचे और हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। बाबूलाल मरांडी ने भी खुले मन से उन्हें अपनाते हुए कहा कि राज्य की सेवा करने का जनादेश आपको मिला है। इस मुलाकात के तुरंत बाद झाविमो ने आधिकारिक तौर पर एलान किया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया जाएगा। पूरी पार्टी हेमंत सोरेन के एक-एक निर्णय पर साथ खड़ी रहेगी। इससे पूर्व बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में झाविमो विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें प्रदीप यादव एक बार फिर विधायक दल के नेता चुने गए।

सिंहदेव तय करेंगे कांग्रेस विधायक दल का नेता

नईदुनिया, रायपुर: झारखंड में कांग्रेस विधायक दल का नेता तय करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने सिंहदेव को ऑब्जर्वर बनाया है। एआइसीसी ने सिंहदेव को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। पहले उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। सिंहदेव की अध्यक्षता में पार्टी के प्रत्याशियों का नाम फाइनल हुआ था। झारखंड में कांग्रेस ने 16 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं, इसलिए दल के नेता हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय है। कांग्रेस के पास आरजेडी से ज्यादा सीटें हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस विधायक को मिलेगा। सिंहदेव कांग्रेस विधायकों की बैठक लेकर विधायक दल के नेता का नाम तो फाइनल करेंगे ही, विधानसभा अध्यक्ष के लिए पार्टी के किसी एक विधायक के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।

रघुवर पर भाजपा का भरोसा कायम, झारखंड से भेजे जा सकते हैं राज्यसभा

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न देने के बावजूद रघुवर दास ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा नहीं खोया है। पार्टी रघुवर को वनवास में भेजने के बजाए उन्हें मुख्य धारा में रखेगी। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की जवाबदेही भी सौंपी जा सकती है। सोमवार को चुनाव परिणाम स्पष्ट होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खुद रघुवर से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया था। संकेत साफ था शीर्ष नेतृत्व उन्हें नकारने नहीं जा रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों की मानें तो उन्हें राज्यसभा चुनाव के माध्यम से उच्च सदन भेजा जा सकता है। झारखंड में अगले वर्ष राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पूर्व की सहयोगी आजसू का साथ मिला तो भाजपा राज्यसभा की एक सीट आसानी से हासिल कर सकती है। राज्यसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में होने हैं। रिक्त होने वाली सीटें राजद के प्रेमचंद गुप्ता और परिमल नथवाणी की हैं।

नीलकंठ या सीपी होंगे नेता विधायक दल

झारखंड विधानसभा में नीलकंठ सिंह मुंडा भाजपा विधायक दल के नेता की भूमिका में दिख सकते हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगने की उम्मीद हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक 28 दिसंबर को होने की बात कही जा रही है। नीलकंठ सिंह मुंडा के अलावा सीपी सिंह के नाम पर भी विचार हो सकता है।

भाजपा में हुआ भितरघात नेतृत्व पर उठ रहे सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची

▶ सोशल मीडिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर प्रदेश की कोर टीम

दृष्टांत एक : पासे सभी उलट गए, कुछ दुश्मनों, कुछ अपनों की चाल के ...., हम लाएं हैं कश्ती तूफान से निकाल के।
सीपी सिंह का ट्वीट।

दृष्टांत दो : जब कोई ऊंचाई पर होता है, तो नीचे चीजें वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति उच्च एवं निर्णायक पद पर होते हैं, तो नीचे वाले उपहासीय व ओछे लगते हैं। परंतु ये लाइनें बड़े महत्व की हैं। 'तुम अगर कत्ल भी करो तो कोई बात नहीं, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम' पर आह तो लगेगी ही। **भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय का फेसबुक पोस्ट।**

झारखंड विधानसभा चुनाव परिणामों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भाजपा के दो शीर्ष नेताओं की उपरोक्त टिप्पणियां भाजपा की हार के तमाम कारण बयां कर देती हैं। भाजपा में ही उसकी हार के कारण छिपे हैं। विपक्ष ने तो बस विकल्प पेश किया। सोशल मीडिया पर भाजपा के छोटे और बड़े नेताओं के पोस्ट भाजपा की अंदरूनी खेमेबंदी को अब खुलकर बयां करने लगे हैं। कई पोस्ट आपत्तिजनक भी हैं, निशाने पर प्रदेश भाजपा की मौजूदा टीम है। भाजपा को भितरघात ले डूबा।

कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और टिकट वितरण की असमानता से उपजा यह भितरघात चुनाव के दौरान चरम पर दिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश नेतृत्व ने यह जानकारी होते हुए भी इसकी अनदेखी की है। भाजपा के शीर्ष नेता अब हार को लेकर किसी भी टिप्पणी से कतरा रहे हैं। प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी नंद किशोर यादव ने सोमवार को पटना रवाना होने से पूर्व बस इतना कहा 'जाने दीजिए, कोई टिप्पणी नहीं'। चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने भी मीडिया से दूरी बनाई और रांची छोड़ दिया।

भाजपा के तीन असफल चेहरे

विधानसभा चुनाव भाजपा ने रघुवर दास के नेतृत्व में लड़ा। भाजपा तो हारी ही, रघुवर खुद भी अपनी सीट गवां बैठे, लेकिन इस हार का जवाबदेह सिर्फ रघुवर दास को नहीं ठहराया जा सकता। भाजपा ने झारखंड में चुनाव की जिम्मेदारी कुछ खास लोगों को सौंपी थी। विशेष तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को विधानसभा चुनाव प्रभारी और नंद किशोर यादव को सह प्रभारी बनाया गया था। सहयोगी के रूप में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह थे। लेकिन ये तिकड़ी असफल साबित हुई। ओम प्रकाश माथुर सात राज्यों की सफलता के तमगे के साथ झारखंड आए थे और खराब ट्रैक रिकार्ड लेकर लौटे।

झारखंड भाजपा में व्यापक फेरबदल के आसार

राज्य ब्यूरो, रांची

रघुवर दास फाइल

▶ प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा का चुनाव भी हारे

▶ भाजपा की वर्तमान कार्यसमिति का कार्यकाल अगस्त में हो चुका है पूरा

झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा जल्द ही प्रदेश के ढांचे में फेरबदल करेगी। वैसे भी भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति का कार्यकाल अप्रैल में ही पूरा हो चुका है। चुनाव की दृष्टि से इसे विस्तार दिया गया था। माना जा रहा है कि जनवरी माह में टीम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। संगठन में बदलाव की वजह स्पष्ट है। वर्तमान संगठन पर विधानसभा में भाजपा की जीत की जवाबदेही थी, जीत तो छोड़िए चुनाव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ही चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव भी वह हारे थे।

मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव भी बुरी तरह परास्त हुए। भाजपा ने अपने 13 वर्तमान विधायकों का टिकट काटा था और खुद के तथा आयातित 36 विधायकों पर इस चुनाव में दांव लगाया था इनमें 15 चुनाव हार गए। जाहिर है ऐसा परिणाम देने वाले प्रदेश नेतृत्व और टीम के साथ अब भाजपा आगे नहीं चलना चाहेगी। हालांकि संगठन में फेरबदल के लिए जल्दबाजी नहीं की जाएगी।

मजबूत आदिवासी चेहरे की तलाश : जनजातीय क्षेत्रों के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं के बावजूद भाजपा को आदिवासी सीटों पर सफलता नहीं मिली। राज्य की कुल 28 सीटों में से दो दर्जन पर भाजपा चुनाव हार गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार पाहन दोनों चुनाव हार गए। जाहिर है कि जनजातीय क्षेत्रों में पैठ बनाने के लिए मजबूत आदिवासी चेहरे की तलाश है, जिसे प्रदेश के नेतृत्व की कमान सौंपी जा सके।

बैठक में कार्यकर्ता आपस में उलझे

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) : मुख्यमंत्री रघुवर दास जिस जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांच बार विधायक रहे, उसी सीट से हारना हर किसी को हैरान कर गया। खुद रघुवर दास भी इसकी वजह जानना चाहते थे। इसी उद्देश्य से रघुवर दास मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे शहर पहुंचे। जैसे ही रघुवर हेलीकाप्टर से उतरे सामने देखते ही भाजपा के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार फूट-फूटकर रोने लगे। रघुवर ने दिनेश को दिलासा देते हुए सूर्य मंदिर पहुंचने के लिए कहा। वहां रघुवर दोपहर 12 बजे से कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें चुनाव परिणाम की समीक्षा होनी थी। बैठक में रघुवर ने जैसे ही हार के कारणों पर कार्यकर्ताओं से एक-एक करके पूछना शुरू किया, दिनेश की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक गए। उधर, कार्यकर्ता एक-दूसरे पर भितरघात करने, सरयू राय के समर्थकों से मिलने समेत पूर्व में हुई कई तरह की गलतियों पर बोलने लगे। इसमें जिन-जिन कार्यकर्ताओं पर अंगुली उठती, आंखें तरेरने लगता। धीरे-धीरे समीक्षा बैठक शोरगुल और हंगामे में बदल गया, इससे रघुवर भी खीझ गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नाम ले-लेकर शांत रहने को कहा, लेकिन माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बावजूद करीब दो घंटे तक चली बैठक में कार्यकर्ताओं ने खुलकर भड़ास निकाली।

'शराब और कोयले का ठेका नहीं दिलाने के कारण हार गए पापा'

अंशुल तिवारी, भिलाई

▶ रघुवर दास की हार पर छत्तीसगढ़ में रहने वाली बेटी का छलका दर्द

▶ कार्यकर्ता और सरयू राय के दुष्प्रचार ने किया आग में घी का काम

झारखंड की सत्ता के साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद की सीट भी नहीं बचा सके। इसका दर्द छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक एहसास किया गया। दुर्ग में रहने वालीं रघुवर की बेटी ने कहा कि शराब और कोयले का ठेका नहीं दिलाने व स्पष्टवादिता के चलते पापा की हार हुई। वह नतीजों को देखने सोमवार सुबह से ही टीवी से चिपकी थीं, लेकिन पिता के दोबारा सत्ता में लौटने की आस उस वक्त टूट गई, जब उनको सियासी मैदान में पिछड़ते देखा। हार का झटका ऐसा कि अपने कमरे में जाकर खामोश बैठ गईं। मिलने वाले आते रहे, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं निकलीं। गौरतलब है कि झारखंड में भाजपा महज 25 सीट ही जीत सकी, जिसके चलते सत्ता उसके हाथ से चली गई।

बेटी रेणु साहू और दामाद यशपाल साहू से दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया के प्रतिनिधि ने बात की। उदासी के माहौल में दामाद-बेटी के मुंह से निकला- पापा का स्पष्ट बात करने का नेचर ही हार का कारण बन गया। कार्यकर्ता और भाजपा से बगावत कर पापा के ही खिलाफ ताल ठोकने वाले सरयू राय के दुष्प्रचार ने आग में घी का काम किया, जिससे वह चुनाव हार गए। दरअसल, जब पापा मुख्यमंत्री बने तभी से कुछ कार्यकर्ताओं की बिजनेस उम्मीद बढ़ गई थी। किसी को दारू, किसी को कोयला का ठेका तो किसी को कुछ और चाहिए था। पापा बेहद ईमानदार ठहरे, पार्टी और प्रदेश के लिए कर्मठ हैं। वह किसी भी कार्यकर्ताओं को गलत और अनैतिक कार्य करने ही नहीं देते थे। वह तल्ख लहजे में ऐसे कार्यकर्ताओं को सीधे मना ही कर देते थे। इसी वजह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाने लगा। सरयू राय द्वारा कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने वाले प्रश्न पर दामाद ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बगैर कार्यकर्ताओं के कुछ भी संभव नहीं है। किंतु कुछ कार्यकर्ता और सरयू राय ही शुरू से दुष्प्रचार करते रहे।

छत्तीसगढ़ में दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित निवास पर मंगलवार को रघुवर दास की बेटी रेणु साहू और दामाद यशपाल साहू झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए। साथ में है रेणु साहू का बेटा। नईदुनिया

गौरतलब है कि रघुवर दास की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी की शादी दुर्ग के यशपाल से हुई है। यशपाल एनएसपीसीएल (एनटीपीसी-सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड) में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यहां पद्मनाभपुर में अपने छोटे भाई और परिजनों के साथ रहते हैं।

हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता : रघुवर दास पर लग रहे आरोपों पर दामाद यशपाल ने कहा कि यह सफेद झूठ है, किसी शख्स को उनके परिजन से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पापा के लिए हम लोग थे ही नहीं, उनके लिए हमसे ज्यादा भाजपा परिवार और झारखंड की जनता ही मायने रखती रही है। उन्होंने पहले झारखंड और भाजपा को ही तवज्जो दिया।

कुछ लोगों को बाहरी होने से थी परेशानी : रघुवर दास के दामाद यशपाल साहू कहते है कि पापाजी के बाहरी होने का आंतरिक विरोध भी झेलना पड़ा। उन्होंने कहा-छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड बना। किंतु वहां काफी ज्यादा राजनैतिक अस्थिरता रही। वहां एक या दो वर्ष में नए सीएम बनने की खबरे आती थीं। कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया। इसके मुकाबले पापा (रघुवर दास) ने पांच साल का कार्यकाल पूर्ण किया और एक अस्थिर राज्य को स्थिर सरकार भी दी। इसकी हमें खुशी है।

पत्नी ऐश्वर्या को हर माह 22 हजार रुपये गुजारा भत्ता देंगे तेज प्रताप

जागरण संवाददाता, पटना

बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के दांपत्य जीवन की राह जुदा होती दिखाई दे रही है। मंगलवार को पारिवारिक न्यायालय के आदेशानुसार तेज प्रताप को ऐश्वर्या को भरण-पोषण और आवास के लिए हर महीने 22 हजार रुपये गुजारा भत्ता देना होगा। उन्हें यह राशि अगस्त 2019 से ही देनी होगी। इसके अलावा तेजप्रताप को मुकदमे में हुए खर्च के रूप में भी ऐश्वर्या को एकमुश्त दो लाख रुपये देने पड़ेंगे। अदालत ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।

पटना फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या राय द्वारा दायर भरण-पोषण के आवेदन पर ये आदेश दिया है। ऐश्वर्या ने भरण-पोषण संबंधी आवेदन 13 नवंबर 2019 को दायर किया था। इस पर लंबी बहस चली। ऐश्वर्या ने 17 दिसंबर को अदालत को बताया कि उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। यह भी बताया था कि तेज प्रताप उसके साथ न रहकर अलग रहते हैं।

तेज प्रताप फाइल

ऐश्वर्या राय फाइल

सूत्रों के अनुसार, महिला हेल्पलाइन ने भी तेज प्रताप और ऐश्वर्या मामले की जांच कर सितंबर माह में अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी थी। नवंबर माह में महिला हेल्पलाइन द्वारा एक अन्य जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी। सूत्रों का कहना है कि हेल्पलाइन का मत था कि ऐश्वर्या राय और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का साथ रहना उचित नहीं है। रिपोर्ट में अदालत को यह जानकारी भी दी गई थी कि ऐश्वर्या की आय का कोई साधन नहीं है। अदालत में यह बात सामने आई थी कि तेज प्रताप ने 2015 में विधानसभा चुनाव अपनी संपत्ति 2 करोड़ रुपये बताई थी। तेज प्रताप का एक भारतीय कंपनी में 25 लाख रुपये के शेयर भी हैं और एक बीएमडब्लू कार है। आयकर रिटर्न में उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये है।

चुनाव परिणाम से मोदी-शाह का घमंड चूर : राकांपा

मुंबई, प्रेट्र : झारखंड में जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन को मिली प्रभावी सफलता ने एक नए पैटर्न को रेखांकित किया है जो देश भर में भाजपा का असर कम करने में मदद करेगा। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को यह कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुआई वाली तीन विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की सराहना की। आदिवासी बहुल राज्य में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को चुनावी जीत पर बधाई दी है। राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जनादेश से पता चलता है कि देश लोकतंत्र से चलेगा न कि बंदूक से। झारखंड में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अहंकार को झारखंड की जनता ने चूर-चूर कर दिया।

शरद पवार फाइल

झारखंड की जनता को समझने में भाजपा ने की गलती : शिवसेना

झारखंड में हुई भाजपा की हार पर शिवसेना ने कहा है कि पार्टी ने राज्य की जनता को समझने में गलती की। पार्टी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मान लिया था कि सीएए से हिंदू मतदाताओं के वोट फीसद में वृद्धि होगी, लेकिन झारखंड के मजदूरों और आदिवासियों ने इसे गलत ठहरा दिया। जब जनता सरकार में बदलाव का फैसला ले लेती है तो उसे पैसे या बाहुबल का दबाव नहीं डिगा सकता।

महाराष्ट्र में 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं उद्धव

मुंबई, आइएएनएस : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 30 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने मंगलवार को एक खबर में यह संभावना जाहिर की है। हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार या राजभवन की ओर से इस बारे में कोई सूचना जारी नहीं की गई है।

▶ शिवसेना के मुखपत्र ने व्यक्त की संभावना, सरकार या राजभवन की ओर से कोई बयान नहीं

उद्धव ठाकरे फाइल

महाविकास अघाड़ी सरकार में अभी छह मंत्री हैं। इसमें शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के दो-दो मंत्री शामिल हैं। सरकार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 42 मंत्री हो सकते हैं। प्रस्तावित विस्तार में दस कैबिनेट और तीन राज्यमंत्री शिवसेना एवं राकांपा से और आठ कैबिनेट एवं दो राज्यमंत्री कांग्रेस से शामिल किए जा सकते हैं। सभी मंत्रियों को 30 दिसंबर को शपथ दिलाई जा सकती है। उपमुख्यमंत्री को लेकर अनुमान जोरों पर है। माना जा रहा है कि यह पद राकांपा के खाते में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया है। राकांपा सूत्रों ने संकेत दिया है कि अजीत पवार का नाम अगले उपमुख्यमंत्री के रूप में लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस जटिल सवालों से जूझ रही है। उसके सामने दो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण को समायोजित करने का सवाल है।

कार्यकर्ता चाहते हैं अजीत पवार बनें उपमुख्यमंत्री : नवाब मलिक

महाराष्ट्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अजीत पवार राज्य के उपमुख्यमंत्री बनें। राकांपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और मुख्यमंत्री द्वारा जवाबदेही तय की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी नृत्य महोत्सव में आएंगे राहुल और प्रियंका

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राहुल गांधी होंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई आला-नेता उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे तीन दिनी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज होगा।

छग में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिवसीय इस नृत्य महोत्सव में देश के 25 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही छह देशों के लगभग 1350 से अधिक प्रतिभागी अपनी जनजातीय कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव में 39 जनजाति प्रतिभागी दल चार विभिन्न विधाओं में 43 से अधिक नृत्य शैलियों दिखाएंगे।

सबकुछ टेढ़ी नजर से देखते हैं राज्यपाल : ममता

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि वे टेढ़े आदमी हैं इसलिए सबकुछ टेढ़ी नजर से देखते हैं। ममता ने कहा कि राज्य में एक व्यक्ति खाली बैठे हुए हैं इसलिए यहां सबकुछ ठीक नहीं है। गौरतलब है कि बंगाल के राज्यपाल धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता में विवाद जगजाहिर हैं। राज्यपाल ने कई मौकों पर विभिन्न मसलों पर ममता सरकार की कड़ी आलोचना की है। वहीं, ममता भी अक्सर उन पर निशाना साधती रहती हैं। राज्यपाल ने हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ममता सरकार की ओर से प्रसारित किए गए विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ममता की यह प्रतिक्रिया उसी के परिप्रेक्ष्य में बताई जा रही है।

रिमोट से चल रहे हैं कुलपति : धनखड़

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

इसके बाद धनखड़ ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना दिखाती है कि विवि में कानून के राज की गंभीरता से समझौता किया गया है। धनखड़ ने कहा कि बंगाल में शैक्षणिक व्यवस्था का डीएनए पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। छात्रों को शांत करने के लिए डेढ़ घंटे तक चला प्रयास विफल हो जाने के बाद राज्यपाल की पीड़ा साफ झलकी। राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में धनखड़ ने कहा कि कुलपति रिमोट से चल रहे हैं। उन्होंने पहले ही सरकार को सूचित किया था, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। इसके पहले उन्होंने ट्वीट किया 'मैं हैरान हूं कि कुलपति को नियम पुस्तिका के अनुसार चलने और दीक्षा समारोह के संबंध में मेरे निर्देश देने के बावजूद ऐसी घटना हुई। इस समय पूरी तरह असहाय महसूस करते हुए मैं जेयू परिसर से जा रहा हूं।' इस ट्वीट को उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी टैग किया।

वीसी की निष्क्रियता पर भी उठाए सवाल : सिलसिलेवार ट्वीट कर राज्यपाल ने कुलपति सुरंजन दास पर मूक दर्शक बनने का आरोप लगाते हुए कहा 'मैं हैरान हूं कि इतना विरोध होने पर भी कुलपति निष्क्रिय अवस्था में हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। यह हरकत उन ताकतों की है, जो यह नहीं जानते कि इसका शिक्षा पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप में क्या असर पड़ेगा।' उन्होंने ट्वीट किया 'कुलपति या विश्वविद्यालय में से किसी और ने मुझसे संपर्क नहीं किया है जबकि मैंने अपनी तरफ से उनसे संपर्क किया है।' इस बीच, आर्ट्स फैकल्टी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष देवराज ने कहा 'छात्रों ने राज्यपाल को परिसर में प्रवेश करने से नहीं रोका। हमने केवल तख्तियां दिखाई और एनआरसी तथा सीएए के खिलाफ नारे लगाए।'

2830 पाकिस्तानियों, 912 अफगानियों और 172 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है पिछले 6 सालों में और इनमें से बहुत से लोग उन देशों के बहुसंख्यक समुदाय से थे।

चंद्र कुमार बोस ने पूछा–'मुसलमानों को क्यों नहीं किया शामिल'

जागरण संवाददाता, कोलकाता : एक तरफ भाजपा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में जोरदार प्रचार कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने ही इसपर सवाल उठा दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र कुमार बोस ने इस बाबत सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट के जरिए सवाल किया-'अगर सीएए 2019 का किसी धर्म से संबंध नहीं है तो हम यह क्यों कह रहे हैं-'सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन! मुसलमानों को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? हमें पारदर्शी होने की जरूरत है।'

बोस ने दूसरा ट्वीट कर कहा-'भारत की किसी अन्य देश से तुलना नहीं की जानी चाहिए। यह ऐसा देश है, जो सभी समुदायों और धर्मों के लिए खुला रहा है।' भाजपा के इस रूख पर कि मुसलमानों को उनके देश में सताया नहीं जाता, बोस ने कहा कि अगर वाकई ऐसा है तो वे लोग आएंगे ही नहीं इसलिए मुसलमानों को शामिल करने में कोई नुकसान नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी तरह सच नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले बलूचों के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में रहने वाले अहमदिया समुदाय के बारे में क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस की समावेशी विचारधारा पर चलने और समाज के सभी वर्गों की भलाई करने वाली पार्टी ही 2021 में बंगाल का चुनाव जीतेगी।

मेरठ में पुलिस ने राहुल और प्रियंका को दिल्ली लौटाया

एहतियात ▶ हिंसा में मृत लोगों के परिजनों से मिलने आ रहे थे दोनों

जागरण संवाददाता, मेरठ

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुक्रवार को हुई हिंसा में मारे गए छह लोगों के परिजनों से मिलने आ रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मेरठ पुलिस ने मंगलवार को परतापुर थाने के पास रोक दिया। पुलिस के आग्रह पर वे दिल्ली लौट गए। प्रियंका ने फोन पर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं। जल्द मिलने भी आएंगी। दिल्ली लौटने से पहले प्रियंका ने मीडिया से कहा, हम हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे लेकिन मेरठ में धारा 144 का हवाला देकर पुलिस ने जाने नहीं दिया। हमें उनसे मिलने से रोका गया। हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए लौट रहे हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था पर तंज भी कसा और कहा कि नागरिकता संशोधन कानून की आग में जबरन लोगों को झोंका जा रहा है। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या भाजपा सरकार आपको जनता तक पहुंचने से रोकना चाहती है, तो वह बस इतना बोले कि अब आप ही देख लीजिए, यहां क्या हो रहा है। राहुल बोले, पुलिस से रोके जाने का हमने आदेश मांगा, लेकिन उन्होंने आदेश नहीं दिखाया। बस लौट जाने को कहते रहे।

मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मंगलवार को मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (वाहन में) को पुलिस ने शहर में प्रवेश से रोक दिया। प्रेट्र

काफिले के वाहन से कुचलने से बचे सीओ : इससे पहले राहुल-प्रियंका के काफिले को जब मोहिउद्दीनपुर में सीओ ब्रह्मपुरी चक्रपाणि त्रिपाठी ने रोकने का प्रयास किया तो एक वाहन से वह कुचलने से बाल-बाल बचे। सीओ हट गए, वरना दुर्घटना घट सकती थी। बाद में परतापुर थाने के पास घेराबंदी कर उन्हें रोका गया और वहीं से उन्हें दिल्ली भेजा गया।

आदेश की कॉपी को लेकर चली बहस : पुलिस ने जब परतापुर थाने के पास काफिला रोका और धारा 144 के उल्लंघन की बात की तो दोनों पक्षों के बीच ऑर्डर की कॉपी को लेकर बहस चली। लगभग पांच मिनट की बातचीत के बाद राहुल गांधी ने लौट जाने का निर्णय किया। उनके साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी थे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह सबकुछ भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है। भाजपा सरकार हमें मिलने नहीं दे रही है।

आखिर मोदी और अमित शाह में कौन बोल रहा सच : ममता बनर्जी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ तीन दिन विराम के बाद मंगलवार को एक बार फिर तृणमूल प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरीं। जुलूस महानगर के विधान सरणी स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास से शुरू होकर बेलियाघाटा स्थित गांधी भवन पर समाप्त हुआ। यहां सभा में ममता ने भाजपा पर हमलावर रुख बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया और कहा कि एनआरसी पर दोनों के बयान विरोधाभासी हैं।

सुश्री बनर्जी ने कहा 'दोनों झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी के बारे में न तो कोई चर्चा हुई है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। लेकिन कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी देश भर में लागू होगा। दोनों ही बयान एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। हमें इस बात पर हैरत हो रही है कि आखिर कौन सच बोल रहा है।'

बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद विपक्ष ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। लेकिन ममता ने एनआरसी को लेकर ही केंद्र पर हमला बोला। ममता के निशाने पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ व भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे।

झारखंड से मिला है करारा जवाब : सुश्री बनर्जी ने झारखंड चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि अब लोगों ने केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव में मिली हार से इस अहंकारी पार्टी को करारा जवाब मिला है। झारखंड में भाजपा बिखर गई है और उनका विरोध पूरे देश में हो रहा है क्योंकि यह लड़ाई देशवासियों के अधिकार की लड़ाई है।

राज्य में कोई डिटेंशन कैंप नहीं, देश को बांट रही है भाजपा : ममता ने कहा कि भाजपा देश को विभाजित करने का काम कर रही है लेकिन देश की जनता ऐसा नहीं होने देगी। वहीं, हाल में बंगाल में राज्य सरकार द्वारा डिटेंशन कैंप बनाए जाने की बात को अफवाह बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनाया जा रहा है। यहां सभी स्वीकृत नागरिक हैं और बंगाल में नागरिकता कानून व एनआरसी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा।

तृणमूल सरकार ने किया मतुआ संप्रदाय का विकास : बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी के तौर पर बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बसे मतुआ संप्रदाय को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि मतुआ संप्रदाय को सीएए के तहत नागरिकता देने के बहाने भाजपा राजनीति और झूठा प्रचार कर रही है क्योंकि सबसे पहले मेरी सरकार ने उनकी सुध ली और उनके विकास के बारे में सोचा।

सिलीगुड़ी में 30 दिसंबर को सड़क पर उतरेंगी बंगाल की सीएम

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी के खिलाफ केवल दक्षिण बंगाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि अब वह उत्तर बंगाल का भी रुख करेंगी। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को सिलीगुड़ी में सीएए–एनआरसी के खिलाफ जुलूस निकालेंगी, जिसमें वह खुद शामिल होंगी। उधर, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री 29 दिसंबर से तीन दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर जा रही हैं।

ममता बनर्जी। फाइल

मुस्लिम 150 देशों में जा सकते हैं, हिंदुओं के पास सिर्फ भारत : रूपाणी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : मुस्लिम अपने रहने के लिए दुनिया भर में 150 देशों में से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए अकेला भारत ही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को न्यायसंगत ठहराते हुए यह कहा। साबरमती आश्रम के बाहर सीएए के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस व विपक्षी दलों पर निशाना साधा।

रूपाणी ने कहा देश में रह रहे किसी भी धर्म व जाति के व्यक्ति से इस कानून का संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि सत्ता में आने पर कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, देश में नागरिकता कानून लाकर यहां बसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेंगे तथा देश में छिपे घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। कांग्रेस लोगों को सीएए कानून पर गुमराह कर रही है। रूपाणी ने कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान में 500 मंदिर थे आज 20 मंदिर हैं।

उप्र के उपद्रवग्रस्त जिलों में पटरी पर लौटा जनजीवन

जेएनएन, लखनऊ

नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भड़की आग अब शांत होने लगी। मंगलवार को कानपुर, अलीगढ़, संभल, मेरठ आदि सभी जिलों में जनजीवन पटरी पर लौटता नजर आया। बाजार भी खुले रहे। हालांकि बरेली में जमात रजा-ए-मुस्तफा ने बैठक की तो सहारनपुर में जमीयत उलमा ए हिंद (महमूद मदनी गुट) ने धरना दिया।

हिंसात्मक आंदोलन नहीं करें, पुलिस भी गोली न चलाए : बरेली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर जमात रजा-ए-मुस्तफा की बैठक दरगाह आला हजरत के पास स्थित कार्यालय में मंगलवार को हुई। इसमें सरकार से मांग की गई कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को गोली चलाने से रोका जाए। वहीं, लोगों से अपील की गई है कि हिंसात्मक आंदोलन से गुरेज करें। मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां ने कहा कि संविधान किसी भी विषय या मुद्दे पर विरोध प्रदर्शित करने की आजादी देता है। इसी आधार के तहत सीएए का विरोध देशभर में हो रहा है।

मदनी ने किया सीएए को लेकर लंबी लड़ाई का एलान

सहारनपुर : नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मंगलवार को जमीयत उलमा ए हिंद (महमूद मदनी गुट) ने ईदगाह मैदान में धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए जमीयत उलमा–ए–हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने सीएए के खिलाफ लंबी लड़ाई का एलान करते हुए कहा कि जमीयत अकेले देवबंद में ही नहीं बल्कि हर शहर में गिरफ्तारियां देगी। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा, जब तक यह काला कानून वापस नहीं हो जाता। मदनी ने आगे कहा कि एनआरसी को लेकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

उद्धव ने कहा, महाराष्ट्र में नहीं है हिरासत केंद्र

मुंबई, प्रेट्र : नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन जारी रहने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में कोई हिरासत केंद्र नहीं है। राज्य के मुस्लिम नागरिकों को उनके शासन के तहत डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सोमवार को मुस्लिम समुदाय के कुछ विधायकों के नेतृत्व में मुलाकात करने आए प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल राकांपा विधायक नवाब मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य में मुस्लिम किसी प्रकार के अन्याय का सामना नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने समुदाय की चिंता का समाधान करते हुए कहा कि नवी मुंबई में खारघर में हिरासत केंद्र मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल विदेशी नागरिकों के लिए है। मलिक की पार्टी राकांपा ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में शामिल है। खारघर हिरासत केंद्र में केवल 38 लोगों को रखा गया है। यह विदेशी नागरिकों के लिए बनाया गया है। जेल से रिहा होने के बाद उन्हें उनके मूल देश को प्रत्यर्पित किए जाने तक यहां रखा जाता है। राकांपा नेता ने मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मेरी सरकार किसी भी धर्म या समुदाय के नागरिकों के अधिकार को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगी। मैं राज्य में शांति और सौहार्द की अपील करता हूं।' इस अवसर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल, मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बारवे, शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार मौजूद थे।

मुंबई में मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (बाएं से दूसरे) से मुलाकात के दौरान उन्हें गुलदस्ता भेंट करते पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (दाएं से तीसरे) और सुनील गावस्कर (दाएं से दूसरे)। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के बड़े बेटे आदित्य (बाएं) और छोटे बेटे तेजस भी मौजूद रहे। प्रेट्र

गावस्कर, तेंदुलकर ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

क्रिकेट जगत की हस्ती सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बांद्रा स्थित उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि यह अनौपचारिक मुलाकात थी।

छात्र को नौकरी देने के एएमयू के फैसले पर उठे सवाल

जासं, अलीगढ़ : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान हिंसा में घायल छात्र को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नौकरी दिए जाने के कुलपति प्रो. तारिक मंसूर पर फैसले पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा है, पुलिस-प्रशासन पर पथराव करने वाले छात्र को नौकरी दी जा रही है, इससे पता चलता है कि कुलपति ऐसे हमले को प्रोत्साहित कर रहे हैं। छात्रों के लिए भी सहज रास्ता होगा, पथराव करो और नौकरी पाओ। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संदीप चाणक्य ने इसकी शिकायत मानव संसाधन विकास मंत्री से की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. पुष्पेंद्र पचौरी ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा, इससे साफ पता चलता है कि एएमयू में कौन सी मानसिकता काम कर रही है। अराजकता फैलाने वाले छात्र नौकरी मिलने पर क्या छात्रों को बवाल कैसे किया जाए, यह पढ़ाएंगे? किसी हिंदू छात्र के साथ ऐसा हुआ होता तो देश की सेकुलर जमात चिल्ला रही होती।

अलीगढ़ में एक लाख से अधिक पोस्टर चस्पा, धरपकड़ जारी

जासं, अलीगढ़

▶ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अलीगढ़ के देहली गेट क्षेत्र के शाहजमाल में पथराव करने वालों के एक लाख से अधिक पोस्टर चस्पा किए जा चुके हैं। इनमें 16 से अधिक दंगाइयों के नाम-पते भी पुलिस को मिल गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शाहजमाल में शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद भीड़ ने पथराव किया था। कुछ नकाबपोश उपद्रव के इरादे से सड़क पर उतरे थे। सब नशे में थे। पुलिस की ओर से करवाई गई वीडियोग्राफी में 35 लोग चिन्हित किए गए थे। एसएसपी आकाश कुलहरि ने प्रत्येक चिन्हित व्यक्ति का पता बताने वाले पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। वहीं सोमवार को एएमयू में कैंडल मार्च निकालने के मामले में पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में एक हजार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एएमयू में बाहरी लोग भी आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को निकाले गए कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में बाहरी लोग शामिल हुए थे। इसने इंतजामिया व जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि एएमयू पांच जनवरी तक बंद है। हॉस्टल भी खाली करा दिए हैं। अब एक-दो दिन से देखने को मिल रहा है कि यहां विरोध-प्रदर्शन और मार्च के कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें बाहरी लोग शामिल हो रहे हैं। इस पर नियंत्रण के लिए एएमयू को पत्र लिखा गया है। धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा भी हो रहा है।

सतर्क रही पुलिस : एएमयू के बाबे सैयद पर छात्राएं मंगलवार को भी धरने पर बैठी रहीं। छात्रों की ओर से कैंपस में मार्च निकालने की खबर आई, जो बाद में नहीं निकला। इस खबर पर भी पुलिस सतर्क रही। एएमयू के छात्रों ने तय किया है कि हर साल 15 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। छात्रों ने मांग की है कि राष्ट्रपति भी एएमयू में पुलिस कार्रवाई के मामले को देखें, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं।

नागरिकता कानून के समर्थन में रैली...

गुजरात के सूरत में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने इस कानून को सही ठहराया है। एएनआइ

बहू ऐसी चाहिए, जिसके पास नागरिक होने का हो सुबूत!

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ एनआरसी–सीएए को लेकर चल रहे विवाद के बीच अखबार में छपा अनोखा वैवाहिक विज्ञापन

सुंदर, सुशील, पढ़ी-लिखी बहू चाहिए। ऐसे वैवाहिक विज्ञापन अखबारों में हमेशा छपते रहते हैं। लेकिन एक विज्ञापन में ऐसी बहू की चाहत जताई गई है, जिसके पास नागरिकता का सुबूत हो। यह अनोखा विज्ञापन बंगाल के एक दैनिक अखबार में प्रकाशित हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि यह विज्ञापन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध कर प्रचार पाने का एक हथकंडा है।

विज्ञापन में कहा गया है कि बहू ऐसी चाहिए, जिसके पास भारतीय नागरिक होने का सबूत हो। 1971 से पहले उसके परिवार का भारत में रहना अनिवार्य है। विवाह के लिए कन्या पक्ष को वर पक्ष को बाकायदा कागजी सबूत दिखाना होगा। वर स्कूल शिक्षक हैं और मुर्शिदाबाद में रहते हैं, हालांकि उनका पैतृक निवास उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा में है। विज्ञापन में संपर्क के लिए सिर्फ टेलीफोन नंबर दिया गया है, जो वर के जीजाजी का है।

जब विज्ञापन देने वाले व्यक्ति से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की आंच परिवार पर भी पड़ चुकी है। एनआरसी-सीएए को लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा है, उसे देखते हुए उन लोगों ने निर्णय लिया गया है। शादी के लिए कन्या पक्ष से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भारतीय नागरिक होने का कागजी सबूत चाहिए।

भविष्य में अगर एनआरसी लागू होता है और बहू कोई कागजात दिखा नहीं पाती, तो उसे डिटेंशन कैंप में भेजा जा सकता है। फिर उनके साले का क्या होगा, इसीलिए यह शर्त रखी गई है। यह कहने पर कि कन्या के पास राशन और आधार कार्ड तो होगा, इसपर उन्होंने कहा कि इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार क्या करेगी पता नहीं, इसलिए 1971 से पहले का रिकॉर्ड मांगा गया है। बहू का परिवार 1971 के पहले भारत में रह रहा है, इसका सबूत होना जरूरी है।

संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ही हो भरपाई : पीयूष

जासं, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए संपत्तियों के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने के संबंध में प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय की तरफ से मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई है। इसमें अश्वनी ने अनुरोध किया है कि पीठ मामले का स्वतः संज्ञान ले या फिर उन्हें इस पर आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे।

मुख्य पीठ ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। हालांकि, वह आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं और पीठ इस आवेदन पर सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता उपाध्याय ने पीठ को बताया कि प्रदर्शन के दौरान हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उग्र प्रदर्शन में शामिल हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है।

दूरसंचार सुविधा बंद करने का दावा वाली याचिका खारिज : सीएए के विरोध में बीते दिनों हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान गैरकानूनी तरीके से दूरसंचार सेवा बंद करने का दावा करते हुए दायर की गई याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र सरकार की दलील सुनने के बाद याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया।

केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने पीठ को बताया कि यह 19 अगस्त को सिर्फ चार घंटे के लिए था और इसका ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। संजय जैन ने बताया कि दूरसंचार के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गय, जैसा कि याचिका में दावा किया गया है। हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर किसी को दूरसंचार सेवा बंद होने के कारण परेशानी हुई या फिर वह प्रभावित हुआ तो वह इसकी भरपाई के लिए याचिका दाखिल कर सकता है।

एसएफएलसी.इन की तरफ से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया कि पुलिस उपायुक्त द्वारा दूरसंचार सेवा प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया। याचिका के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रतिबंधित करने का आधार सही नहीं है। याचिका के अनुसार इंटरनेट एक आम नागरिक की निजता और शिक्षा का अधिकार है।

63 से ज्यादा छात्र संगठनों ने की सीएए वापस लेने की मांग : युवा भारत समन्वय समिति के बैनर तले वामपंथ के करीबी देशभर के 63 से ज्यादा छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 26 जनवरी तक नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को वापस नहीं लिया गया तो देशभर के विश्वविद्यालयों में आंदोलन होगा।

संगठन एक जनवरी को संविधान की रक्षा दिवस मनाएगा। आठ जनवरी को विश्वविद्यालयों को बंद करने की अपील भी की गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मंगलवार को समिति के पदाधिकारी समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के वामपंथी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एनआरसी की जगह सरकार को बदहाल हो चुके स्कूल और कॉलेजों का रजिस्टर बनाना चाहिए।

झूठ फैला रही कांग्रेस और आप : पीयूष गोयल

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को दिल्ली की संजय कॉलोनी भाटी माइंस पर सीएए को लेकर आयोजित जनसभा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर पूरे देश में झूठ फैलाया जा रहा है। आप और कांग्रेस झूठ फैला रही है। गोयल ने कहा कि इस कानून के माध्यम से धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेल रहे शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है। ऐसे में तमाम दल मुस्लिमों के बीच झूठ फैला रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों पर सीएए और एनआरसी लागू नहीं होता है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे मामले को धार्मिक रंग देने में लगी हैं।

पीयूष गोयल। फाइल

भड़की हिंसा पर काबू पाने को जवाबी फायरिंग में हुई थी सुलेमान की मौत

जागरण संवाददाता, बिजनौर

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर बिजनौर के नहटौर में गत शुक्रवार को भड़की हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में सुलेमान की मौत हुई थी। सुलेमान को 9 एमएम की गोली लगी थी, इसलिए पुलिस मान रही है कि आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में चली गोली ही सुलेमान को लगी।

पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। बिजनौर में बवाल के दौरान सुलेमान और अनस की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुलेमान को 9 एमएम की गोली लगने की पुष्टि हुई। यह बोर प्रतिबंधित है, जो सिर्फ पुलिस के पास होती है। पुलिस जांच में सामने आया कि भारी हिंसा को काबू में करने के दौरान जवाबी फायरिंग में सुलेमान की मौत हुई। वहीं, पुलिस मानकर चल रही है कि अनस को किसी बलवाई की गोली लगी थी। शुक्रवार को भारी उपद्रव व हिंसा के दौरान सबसे पहले बवालियों की ओर से हुई फायरिंग में सिपाही मोहित को गोली लगी थी। इसी बीच उपद्रवियों द्वारा दारोगा आशीष तोमर की पिस्टल छीन ली गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और जमकर पथराव होने लगा। अंततः बलवाइयों की ओर से घिरी पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी।

> बवाल के दौरान सुलेमान ने तमंचे से सिपाही मोहित को गोली मार दी। इसके बाद सुलेमान जख्मी सिपाही को दोबारा गोली मारने की कोशिश कर रहा था। अंतत : आत्मरक्षा के लिए सिपाही मोहित ने अपनी सर्विस पिस्टल से सुलेमान को गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई।
>
> **–संजीव त्यागी, पुलिस अधीक्षक, बिजनौर**

2.5 हजार से भी अधिक बार गोलीबारी कर चुका है पाकिस्तान इस वर्ष अब तक। इससे पहले वर्ष 2018 में गोलाबारी की 1629 मामले दर्ज हुए थे।

लखनऊ में 200 करोड़ की लागत से बनेगा अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय

सौगात ▶ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे शिलान्यास, लोकभवन में होगा आयोजन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ में आकार लेने जा रहा चिकित्सा विश्वविद्यालय कई मायनों में खास होगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल के फूल की आकृति में बनने वाला विश्वविद्यालय का भवन लखनऊ की नई पहचान बनेगा, जबकि इसके प्रांगण में लगने वाले कदंब, पारिजात व मौलश्री जैसे वृक्ष पूरे परिसर की आभा व परिणाम बढ़ाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। आयोजन तो लोकभवन में होगा, लेकिन विश्वविद्यालय की बुनियाद करीब 11 किलोमीटर दूर चक गंजरिया में पड़ेगी। 50 एकड़ भूमि में बनने जा रहा यह चिकित्सा विश्वविद्यालय सरकारी, अर्द्धसरकारी व निजी क्षेत्र के 40 मेडिकल कॉलेजों, 17 डेंटल कॉलेजों तथा 299 नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों के कुल 20,770 विद्यार्थियों को हर साल पंजीकृत करेगा। इसमें मेडिकल के 6210, डेंटल के 2016 और नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों के 12,544 विद्यार्थी होंगे।

प्रतिमा का भी होगा अनावरण : 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर लोकभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते अधिकारी। जागरण

विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है, जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण से आवंटित भूमि का कब्जा भी चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18 दिसंबर को मिल गया है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ.केके गुप्ता ने बताया कि पहले चरण के तहत विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, संग्रहालय, अतिथि गृह, आवास व अन्य निर्माण किए जाएंगे। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले विश्वविद्यालय का भवन ग्रीन एनर्जी तकनीक से बनेगा, जिससे 65 फीसद ऊर्जा की बचत होगी। विश्वविद्यालय परिसर में 12 मीटर चौड़ा मार्ग होगा, जिसके साथ ग्रीन ब्लेट बनाकर पौधरोपण किया जाएगा। यहां साइकिल ट्रैक के साथ पैदल चलने का अलग रास्ता होगा, जबकि परिसर में लगे फव्वारे भी विवि की भव्यता बढ़ाएंगे।

356 कॉलेजों के 20 हजार छात्रों को संभालेगा अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय

25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का होगा अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अटल की जयंती पर लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। मोदी दोपहर ढाई बजे विशेष विमान से लखनऊ पहुंचेंगे और सीधे लोकभवन जाएंगे। प्रतिमा के अनावरण के बाद प्रधानमंत्री का 25 मिनट का संबोधन होगा। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। शाम पौने पांच बजे प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

गुजरात के दो कांग्रेस विधायक व पूर्व भाजपा सांसद दंगा मामले में दोषी

राजकोट, प्रेट्र : दो कांग्रेस विधायकों और एक पूर्व भाजपा सांसद समेत 10 लोगों को दंगा और तोड़फोड़ के मामले में एक साल कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दंगा करने का यह मामला 2008 में दर्ज किया गया था।

एडीशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रूपा एस. राजपूत ने जूनागढ़ और वांकानेर से कांग्रेस विधायकों भीकाभाई जोशी और मुहम्मद जावेद पीरजादा के साथ-साथ राजकोट पूर्व से पूर्व कांग्रेस विधायक इंद्रनील राज्यगुरु, पूर्व भाजपा सांसद देवजी फतेपारा और छह अन्य को दोषी ठहराया और एक साल कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी 10 दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये के बांड पर जमानत प्रदान कर दी गई।

इस मामले में दिसंबर, 2008 में 179 नेताओं के खिलाफ प्रद्युम्न नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था। इन नेताओं ने जमीन कब्जाने के मामले में तत्कालीन कांग्रेस विधायक कुंवरजी बावलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन में करीब 1,500 लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया था। बावलिया अब भाजपा में हैं।

दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों में राजकोट जिला दुग्ध सहकारी समिति के अध्यक्ष गोविंद रणपरिया के अलावा कांग्रेस नेता अशोक डांगर, जसवंत सिंह भाटी, महेश राजपूत, भीखू वडोडरिया और गोवर्धन दमेलिया शामिल हैं। ये नेता बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे।

बर्फबारी में बंद रास्तों से भी हो सकती है घुसपैठ

गगन कोहली, राजौरी

हर बार सर्दियों में भारी बर्फबारी से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं और पाकिस्तानी गोलाबारी भी लगभग थम जाती है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग जारी रखे हुए है। मतलब साफ है....! पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और आतंकी संगठनों ने मिलकर बर्फबारी के बावजूद घुसपैठ की साजिश रची है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से सीमा पर लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं। कुछ रोज पहले सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत व राज्य पुलिस के प्रमुख दिलबाग सिंह भी यह संकेत दे चुके हैं कि सीमा पर हालात बिगड़ सकते हैं और घुसपैठ के प्रयास बढ़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने जवानों को पूरी तरह सतर्क व मुस्तैद रहने को कहा था।

आतंकियों को दो से पांच फीट बर्फ में चलने का प्रशिक्षण : हाल ही के दिनों में एलओसी व इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। इससे कुछ क्षेत्रों में सीमा पर लगी कंटीली तार को भी नुकसान पहुंचा है और घुसपैठ के अधिकतर मार्ग बंद हो चुके हैं। सूत्रों की मानें तो पाकिस्तान ने ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया है, जहां दो से पांच फीट बर्फ गिरती है। ऐसे इलाकों में चलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सीमा पार आतंकी शिविरों में आतंकवादियों को दो से पांच फीट तक बर्फ को पार करने का प्रशिक्षण दिया गया है।

कहां-कहां मौजूद हैं आतंकी : मौजूदा समय में सीमा पार पाकिस्तान के निकयाल, समानी, अग्रिम बालाकोट, डाकू पोस्ट, कदू पोस्ट, देवा, तत्तापानी आदि क्षेत्रों में काफी संख्या में आतंकी जमा हैं और घुसपैठ का मौका तलाश रहे हैं। इनकी संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है।

बॉर्डर एक्शन टीम के सदस्य भी सीमा के करीब तैनात

पाक सेना ने बार्डर एक्शन टीम (बैट) के सदस्यों को सीमा के करीब तैनात किया हुआ है। बार्डर एक्शन टीम को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वह मौका मिलते ही भारतीय क्षेत्र में दाखिल होकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर वापस अपनी सीमा में सुरक्षित लौट आएं।

ध्यान भटकाने के लिए की जा रही गोलाबारी

भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए ही पाकिस्तानी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी पुंछ व उड़ी तक सैन्य चौकियों व रिहायशी क्षेत्रों में भारी गोलाबारी कर रहा है। पिछले एक माह में खराब मौसम की आड़ में कई बार घुसपैठ के प्रयास किए जा चुके हैं।

चेक की क्लोनिंग कर दिल्ली एम्स के खाते से उड़ाए 12 करोड़ रुपये, पांच हैकर गिरफ्तार

जेएनएन, नई दिल्ली

उप्र के आजमगढ़ में पुलिस ने ऐसे हैकर गिरोह को दबोचा है, जिसने अपने कारनामे से एम्स दिल्ली सहित कई देशों के बड़ी फर्मों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। महराजगंज थाना क्षेत्र के देवनपुर के समीप से गिरोह के सरगना समेत पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्थे चढ़े गिरोह के सदस्य कितने शातिर हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने एम्स दिल्ली के चेक की क्लोनिंग करके 12 करोड़ रुपये उड़ाए थे। इतना ही नहीं पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इन साइबर अपराधियों ने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी समेत विभिन्न देशों के बैंकों को भी हैकर वहां की बड़ी फर्मों के खातों से रुपये उड़ाए हैं। इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने में साइबर ठगों ने एम्स के खाते से ठगी की घटना को अंजाम दिया था। साइबर अपराधियों ने एम्स के निदेशक के खाते से करीब सात करोड़ रुपये, जबकि डीन के नाम वाले खाते से करीब पांच करोड़ रुपये निकाले थे। पकड़े गए हैकर गिरोह में एक बैंक कैशियर, ग्राहक सेवा केंद्र का एक संचालक, दो कंप्यूटर इंजीनियर भी शामिल हैं। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रो. त्रिवेणी सिंह ने पकड़े गए अपराधियों को मीडिया के सामने लाते हुए मंगलवार को इस मामले की विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने बताया कि उक्त अपराधी क्रेडिट, डेबिट कार्ड, चेक, हस्ताक्षर आदि का क्लोनिंग व डंपिंग करते थे।

एक माह में निकाली गई रकम

यह रकम एक माह के दौरान मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आदि शहरों से निकाली गई थी। घटना का पता चलने के बाद एम्स प्रशासन ने ठगी की शिकायत दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्ल्यू), स्टेट बैंक और सीबीआइ में की थी। उधर घटना सामने आने के बाद एसबीआइ ने ठगी में गई पूरी रकम 10 दिसंबर को एम्स के खाते में वापस डाल दी थी। बड़ी रकम निकाले जाने की जानकारी सामने आने पर एम्स प्रशासन ने एसबीआइ बैंक से इसकी जानकारी मांगी थी।

बैंक ने नहीं किया नियम का पालन

ठगी का पता चलने पर एम्स प्रशासन द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सहित पुलिस को इस बारे में अवगत कराया गया था। एसबीआइ भी इस मामले में आंतरिक जांच करवा रही थी। नियम के मुताबिक दो लाख रुपए से ज्यादा की रकम का चेक पास करने से पहले बैंक इसकी सूचना खाताधारक को देता है। लेकिन इस मामले में बैंक ने ऐसा नहीं किया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में बैंक के नियमों की अनदेखी सामने आ रही थी।

बैंक कैशियर व साफ्टवेयर इंजीनियर भी : पकड़े गए अपराधियों में लक्ष्मण यादव निवासी मऊ और कुलदीप सिंह निवासी देवरिया साफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लक्ष्मण ने एमसीए व कुलदीप ने बीटेक किया है। इन दोनों को ही हैकर बताया जा रहा है। शशिरंजन मौर्य गोरखपुर का निवासी है। यह गोरखपुर मझगांवा एसबीआइ ब्रांच का कैशियर है।

लोहरदगा में नक्सलियों के बारूदी सुरंग विस्फोट में किशोरी की मौत

जासं, लोहरदगा : विधानसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक अगले दिन मंगलवार को लोहरदगा में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लोहरदगा जिले के केकरांग झरना के समीप बारूदी सुरंग विस्फोट में किशोरी की मौत हो गई है। वहीं एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल लाया गया। जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया है। एसपी प्रियदर्शी आलोक ने घटना की पुष्टि की है।

वारदात में जान गंवाने वाली किशोरी का नाम जमुना उरांव है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह, लोहरदगा थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक जय प्रकाश राणा, बगड़ू थाना प्रभारी निशिकांत शर्मा ने सदर अस्पताल पहुंच कर घायलों का बयान लिया है। नक्सलियों की घेराबंदी को लेकर पुलिस का अभियान तेज पकड़ चुका है। पुलिस ने सतर्कता के साथ शव को बरामद किया है।

मध्य प्रदेश के बड़वानी के पास चेतक उत्सव में 11 लाख में बिका 'प्रिंस'

नईदुनिया, बड़वानी

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के समीप महाराष्ट्र के शहादा जिले के सारंगखेड़ा में 16 दिनी 'चेतक उत्सव' जारी है। इसमें देशभर के अश्व प्रेमी व व्यापारी शरीक हो रहे हैं। इस बार उत्सव में शामिल होने 3000 से अधिक घोड़े लाए गए हैं। अब तक मेले में 758 घोड़ों की बिक्री व तीन करोड़ से अधिक का कारोबार हो चुका है। मंगलवार को सजे-धजे घोड़ों का नृत्य देख लोग दंग रह गए। उत्सव में प्रिंस घोड़ा सबसे अधिक 11 लाख रुपये में बिका। पांच लाख तक बिकने वाले कई घोड़े थे। घोड़ों की शुरुआती कीमत ही एक लाख रुपये है। 26 दिसंबर को उत्सव का समापन होगा।

चेतक उत्सव में पहली बार पंजाब के अमृतसर से लाया गया 10 करोड़ रुपये का शान घोड़ा भी शामिल हुआ। शान मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। इसके मालिक का दावा है कि दौड़ में इसके आगे कोई घोड़ा नहीं टिका। इसकी खुराक पर एक लाख रुपये महीना खर्च किया जाता है।

300	वर्षों से अश्व मेला लग रहा	**10**	वर्षों में अश्व मेले का हुआ विस्तार
758	अश्वों की हो चुकी है अब तक बिक्री	**16**	दिन तक चलने वाले उत्सव में विदेशी भी पहुंचे

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से लगे महाराष्ट्र के शहादा जिले के सारंगखेड़ा में जारी चेतक उत्सव में नृत्य करते अश्व। नईदुनिया

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक प्रबंधक कार में जिंदा जले

लाडवा-पिपली रोड पर निवारसी गांव के नजदीक चलती कार में लगी आग। जागरण

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाडवा-पिपली मार्ग पर गांव सौंटी के नजदीक अचानक चलती कार में आग लग गई। आग में जलने के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक प्रबंधक की मौत हो गई। इस दौरान कुछ लोग तमाशबीन बनकर घटना की वीडियो बनाते रहे। लाडवा पुलिस व फायर ब्रिगेड सूचना के बाद पहुंची। जानकारी के अनुसार लाडवा के सेक्टर-5 निवासी देवेंद्र कालड़ा लाडवा के ही सेंट्रल बैंक में सहायक प्रबंधक के तौर पर कार्यरत थे। वह मंगलवार को अपनी कार से बैंक के काम से कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे थे। सौंटी गांव के पास पहुंचते ही कार में अचानक आग लग गई। उन्होंने कार से निकलने का काफी प्रयास किया, लेकिन सेंटर लॉक के कारण खिड़की नहीं खुल पाई। थाना लाडवा प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कार में आग किस कारण से लगी, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बैंक के कैशियर रामकुमार के अनुसार देवेंद्र कालड़ा मंगलवार सुबह बैंक में आए थे। बाद में बैंक के कार्य से कहीं गए थे। बाद में सूचना मिली कि कार में आग लगने से उनकी मौत हो गई।

हीरानगर में पाक ने तीसरे दिन भी दागे मोर्टार शेल

संवाद सहयोगी, हीरानगर : अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना लगातार गोलाबारी कर रहा है। इससे सीमांत गांवों में दहशत का माहौल है। सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे के बाद पाकिस्तानी सेना ने चक चंगा व छन्नटांडा गांवों में गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने दोनों गांवों के रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बना कर मोर्टार तथा मशीनगन से गोलीबारी शुरू की जो मंगलवार सुबह पांच बजे तक रुक-रुक कर जारी रही। इस दौरान दर्जनों मोर्टार शेल घरों, पशुओं के तबेलों व आस पास के खेतों में गिरे। उधर, सीमा सुरक्षा बल के जवान पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल गोलीबारी में किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है।

चकचंगा निवासी रोशन लाल, गुलशन कुमार, सुंदर लाल, मुकेश कुमार, रमेश चंद्र का कहना है कि पाक रेंजर्स तीन दिन से अपने पग्च चक पोस्ट से दोनों गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं। यह क्रम हीरानगर सेक्टर में करीब दो माह से लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि शाम के सात बजते ही गांवों में सन्नाटा छा जाता है। शाम होते ही लोग बंकरों में घुस जाते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे।

अफगानी प्याज से भरा आइसीपी का गोदाम, लौटाए जा रहे हैं ट्रक

जागरण संवाददाता, अमृतसर

प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच आइसीपी अटारी से प्याज से भरे ट्रक लौटाए जा रहे हैं। दरअसल प्याज से इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट का गोदाम भर चुका है। सोमवार को प्याज के 10 ट्रक और ड्राइफ्रूट के सात ट्रकों को वापस वाघा भेजना पड़ा।

वाघा-अटारी के रास्ते रोजाना प्याज के 70 ट्रक और ड्राइफ्रूट के 12 ट्रक भारत पहुंच रहे हैं। इस तरह रोजाना 2,100 टन प्याज और 264 टन ड्राइफ्रूट पहुंचता है। ऐसे में पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान से प्याज से भरे 425 ट्रक, जबकि ड्राइफ्रूट के 168 ट्रक भारत पहुंचे हैं। इस तरह 12 हजार 750 टन प्याज और ड्राइफ्रूट 3 हजार 696 टन आइसीपी पर पहुंचा। हालांकि जिन ट्रकों को वाघा लौटाया जा रहा है, वो अगले दिन फिर अनलोड के लिए आइसीपी पर आते हैं।

व्यापारी समय पर नहीं उठा पाते प्याज और ड्राइफ्रूट : ड्राइफ्रूट एसोसिएशन के प्रधान अनिल मेहरा ने बताया कि दिल्ली के लिए गाड़ियां नहीं मिल पातीं, जिसके चलते दिल्ली के व्यापारी प्याज और ड्राइफ्रूट समय पर नहीं उठा पाते। इंपोर्ट सामान बहुत कीमती होता है तो उन्हें शेड के अंदर ही रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइसीपी पर तैनात अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को भी चाहिए कि उतनी ही गाड़ियां वाघा से इधर मंगवाएं, जितनी शेड (कवर्ड गोदाम) में रखी जा सकें।

कस्टम कमिश्नर दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि गोदामों में स्टाक नहीं रहे, इसके लिए कस्टम विभाग तुरंत औपचारिकताएं पूरी करने के हर संभव प्रयास करता है। इसके बाद माल उठाना व्यापारी की मर्जी पर निर्भर करता है। कई बार गाड़ियां नहीं मिलने के चलते भी ऐसे हालात बन जाते हैं। अधिकारी ट्रेडर्स को भी सामान जल्द से जल्द उठवाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि अफगानिस्तान से रोजाना पहुंचने वाले प्याज और ड्राइफ्रूट के ट्रकों की अनलोडिंग करके ही वापस भिजवाया जाए।

वाघा-अटारी के रास्ते रोजाना प्याज के 70 ट्रक व ड्राइफ्रूट के 12 ट्रक भारत पहुंच रहे हैं। प्रतीकात्मक

आगरा में दुष्कर्म पीड़िता ने दम तोड़ा, आरोपित गिरफ्तार

जासं, आगरा : दुष्कर्म के बाद सिर में ईंट से प्रहार कर घायल की गई पीड़िता 58 घंटे बाद मंगलवार शाम जिंदगी की जंग हार गई। वह सरोजिनी नायडू (एसएन) मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उधर, पुलिस ने आरोपित को भी एटा से गिरफ्तार कर लिया। आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में शनिवार रात को मानसिक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के बाद ईंट मारकर हत्या का प्रयास किया गया था। पुलिस ने उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। मंगलवार शाम 5 बजे पीड़िता ने दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर एत्माद्दौला उदयवीर सिंह मलिक ने बताया कि एटा के सकरौली में नगला उदी से आरोपित सुगर सिंह उर्फ सोझा को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपित सुगर सिंह ने पुलिस को बताया कि आगरा में रहकर मजदूरी करता था। रात को एत्माद्दौला में ही सो जाता था। शनिवार रात को वह नशे में धुत हो लौटा। यमुना ब्रिज स्टेशन रोड पर एक तख्त पर उसे युवती सोती मिल गई। वह उसके साथ घिनौनी हरकत करने के बाद मरणासन्न कर गांव भाग गया।

सियासत

नेकां और पीडीपी ने इसी सप्ताह बैठक कर हालात पर किया मंथन, जम्मू के बाद कांग्रेस ने कश्मीर में भी शुरू की राजनीतिक गतिविधियां

कश्मीर में हालात सामान्य, जमीन तलाशने में जुटे सियासी दल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में जनजीवन पूरी तरह सामान्य होने के साथ ही मुख्यधारा की सियासी गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का विरोध कर रही नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता अब वादी में सक्रिय होने लगे हैं। वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे संगठनों के नेता भी जम्मू-कश्मीर की सियासत को लेकर मुखर होने लगे हैं। अलगाववादी खेमा बेशक खामोश है, लेकिन बदली परिस्थितियों के बीच उसके कई नेता भी अपने लिए नई जमीन तलाशते नजर आ रहे हैं।

पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने से उपजी स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में सभी गैर भाजपा राजनीतिक दलों के सभी प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया था। इसके साथ ही पूरे राज्य में सियासी गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं। हालात में बेहतरी के साथ राज्य के जम्मू संभाग में तो राजनीतिक गतिविधियां सीमित तौर पर शुरू हो गई थीं, लेकिन कश्मीर में सियासी हलचल लगभग थमी हुई थी। नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस समेत सभी राजनीतिक दलों के वह नेता जो हिरासत से बाहर थे, पूरी तरह चुप्पी साधे थे। प्रशासन ने जिन नेताओं को रिहा किया था, वह भी चुप बैठे, क्योंकि रिहाई की शर्त यही थी कि वह सियासी मुद्दों पर नहीं बोलेंगे।

हालांकि, अब बीते दो दिनों से कश्मीर में मुख्यधारा के सियासी दल एक बार फिर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इसी सप्ताह सोमवार को अपने कार्यालयों में अलग बैठकें कीं। इन बैठकों में कश्मीर के मौजूदा हालात, देश की सियासत पर चर्चा हुई। दोनों दलों ने अलग-अलग प्रस्ताव पारित कर सभी राजनीतिक लोगों की रिहाई की मांग की, नागरिकता संशोधन कानून की निंदा की। उन्होंने अपनी अगली सियासी रणनीति तय करने के लिए अपने नेताओं की रिहाई का इंतजार करने का एलान भी किया। पूर्व कृषि मंत्री और डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के अध्यक्ष गुलाम हसन मीर और पूर्व राजस्व मंत्री, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम यासीन भी अपने समर्थकों संग सियासी हालात में बैठक कर रहे हैं।

अलगाववादी खेमा खामोश : अलगाववादी खेमा बेशक पूरी तरह खामोश है, लेकिन कट्टरपंथी सईद अली शाह गिलानी और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक भी लगातार अपने समर्थकों संग संपर्क कर बदले हालात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अलगाववादी खेमे की दूसरी पंक्ति के कई नेता कश्मीर में दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले बुद्धिजीवियों व राजनीतिक प्रतिनिधिमंडलों से मिल रहे हैं। उनसे बातचीत में वह अपने रुख में बदलाव का यकीन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।

सियासी जमीन बचाने के लिए सक्रियता

कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार आसिफ कुरैशी ने कहा कि बेशक नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक और वह खुद भी जानते हैं कि अगर वह ज्यादा देर तक निष्क्रिय रहे तो केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में उनकी सियासी जमीन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए सक्रिय रहना जरूरी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कश्मीर में सियासी गतिविधियां और जोर पकड़ेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार यहां विधानसभा चुनाव कराएगी। इसलिए कश्मीर के सभी परंपरागत दल सक्रिय हो रहे हैं।

पैर दबाने से इन्कार किया तो शौहर ने तीन बार कह दिया तलाक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : जीवन के तकरीबन चार दशक साथ बिताने के बाद एक वृद्ध ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कह दिया। वृद्धा का कसूर केवल इतना था कि उसने पति के पैर दबाने से इन्कार कर दिया। मंगलवार को तीन तलाक पीड़ित वृद्धा ने अफसरों से न्याय की गुहार लगाई।

वाकया, सिखेड़ा थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाली करीब 60 वर्षीय महिला ने मंगलवार को अपनी पुत्रवधुओं को साथ लेकर एसडीएम दरबार में हाजिरी लगाई। अपनी पीड़ा सुनाते हुए महिला ने बताया कि उनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है। गांव में उनका भरा-पूरा परिवार है, जिनमें बेटे और पुत्रवधू, पौत्र-पौत्री भी हैं। पति आए दिन उन्हें प्रताड़ित करता है। बूढ़ी काया को लेकर पहले ही दुखी हैं, ऊपर से पति उन्हें अपनी सेवा करने के लिए दबाव डालता है। उनसे पैर दबाने को कहता है, इन्कार करने पर उन्हें सताता है। वृद्धा का आरोप है कि शनिवार को भी पति ने पैर दबाने के लिए कहा, जिससे इन्कार करने पर उन्हें तत्काल तीन तलाक कह दिया। विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। एसडीएम कुलदीप मीणा से मिलीं पुत्रवधुओं ने भी ससुर के सलूक की शिकायत की, जिसे सुनकर अधिकारी भी हैरत में पड़ गए।

तीन दिन से भटक रही वृद्धा : अपना दर्द सुनाते हुए पीड़ित वृद्धा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि तलाक देने के बाद पति ने उनके घर में घुसने पर रोक लगा दी है। इसके चलते वह पिछले तीन दिन से दर-दर भटक रही हैं।

वृद्ध महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला को पुलिस के पास भेजा गया है। वृद्धा अपनी पुत्रवधुओं के साथ पहुंची थी। सभी की समस्याएं सुनने के बाद पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। –कुलदीप मीणा, एसडीएम जानसठ तहसील।

22 हजार करोड़ के एसआरए घोटाले में बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और ईडी से जवाब तलब किया है। झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास प्रोजेक्ट के नाम पर हुए हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, अभी और गिरेगा पारा

मौसम की मार ▸ लेह में माइनस 16 .7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ज्यादा ठंड

कोहरे के चलते 30 से ज्यादा राजधानी ट्रेन हुईं लेट

जेएनएन, नई दिल्ली

हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले में तापमान शून्य से नीचे जाने के बाद जम गई स्पीति नदी का मंगलवार का एक दृश्य। प्रेट्र

उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप मंगलवार को भी जारी रहा। इसका असर पहाड़ों से लेकर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी दिखाई दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते जहां कश्मीर और लेह में तापमान माइनस 16 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं, हिमाचल में भी कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। हरियाणा के अधिकांश जिलों में रात्रि तापमान में गिरावट की वजह से सर्दी लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को कुछ समय के लिए धूप निकली जरूर, लेकिन सर्द हवाओं के कारण इस दौरान भी कंपकंपी छूटती रही। इस दौरान हिसार प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां का अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नारनौल और रेवाड़ी की रात सबसे ठंडी रही। यहां का रात्रि तापमान क्रमशः 3.7 और चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बुधवार को बादल छाए रहेंगे। आगामी दिनों में न्यूनतम पारा गिरने से ठिठुरन और बढ़ेगी।

कोहरे ने बिगाड़ी राजधानी की चाल : ठंड के बाद कोहरे ने राजधानी व हमसफर जैसी तेज गति से चलने वाली वीआइपी ट्रेनों की भी चाल बिगाड़ दी है। इन ट्रेनों सहित 30 से ज्यादा ट्रेनें मंगलवार को देरी से दिल्ली पहुंचीं। इस वजह से 12 ट्रेनों के समय में बदलाव करना पड़ा, जिसमें तीन राजधानी एक्सप्रेस और चंपारण हमसफर भी शामिल हैं। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि कोहरा ज्यादा होने की वजह से एहतियातन ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ती है, जिससे उन्हें गंतव्य पर पहुंचने में देरी हो रही है।

कश्मीर में गुजरी सबसे ठंडी रात : कश्मीर में पहले से ही जमाव बिंदु से नीचे चल रहे न्यूनतम तापमान के साथ मंगलवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 4.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं, श्री अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम का न्यूनतम तापमान माइनस 10.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं, डल झील सहित वादी के ज्यादातर जलस्रोत आंशिक तौर पर जमे हुए हैं। उधर, -16.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लेह सबसे ठंडा रहा।

हिमाचल में छह स्थानों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे : हिमाचल में तीन दिन से धूप के बावजूद शीतलहर तेज हो गई है। प्रदेश के छह स्थानों केलंग, कल्पा, मनाली, कुफरी, सुंदरनगर व सोलन में तापमान जमाव बिंदु से नीचे है।

11 दिन से बर्फ में फंसे हैं जवान, निकालने में बाधक बना मौसम

संवाद सूत्र, पिथौरागढ़ : मौसम के अनुकूल नहीं होने से रिलकोट पोस्ट में फंसे आइटीबीपी के जवान और पोर्टर्स मंगलवार को भी नहीं निकाले जा सके हैं। रिलकोट में आठ जवान और सात पोर्टर 11 दिन से फंसे हुए हैं। जवानों व पोर्टरों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला जाना है, लेकिन खराब मौसम बाधक बन रहा है।

आइटीबीपी के जवानों को अग्रिम चौकी से नीचे आना था, लेकिन 12 से 14 दिसंबर तक उच्च हिमालय में भारी हिमपात होने के कारण जवान व पोर्टर्स रिलकोट में फंस गए हैं। रिलकोट में छह फीट से अधिक बर्फ होने के कारण जवानों को निकालने के लिए वायुसेना से हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। मंगलवार को जिले में मौसम साफ रहा, लेकिन उच्च हिमालय में ऊंचाई वाले स्थानों में सुबह हिमपात होने की वजह से जवानों को निकालने का अभियान शुरू नहीं हो सका। डीआइजी आइटीबीपी बरेली रेंज एपीएस निंबाडिया के अनुसार, रिलकोट चौकी में फंसे जवानों के पास पर्याप्त खाद्यान्न और पोर्टर्स सुरक्षित हैं। मौसम में सुधार होते ही उन्हें निकाल लिया जाएगा।

फर्जी ट्रांसफर आदेश से रिलीव हुए सीएमओ, विदाई भी दे दी गई

नईदुनिया, अशोकनगर

▸ मध्य प्रदेश में उपसचिव के नाम से चार सीएमओ के किए गए थे तबादले

▸ अशोकनगर के सीएमओ पठान ने रिलीव होने के बाद फिर संभाला पदभार

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपसचिव राजीव निगम के नाम से फर्जी आदेश जारी कर प्रदेश के चार निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) के तबादले कर दिए गए। सोमवार को जारी आदेश में अशोकनगर के प्रभारी नपा सीएमओ शमशाद पठान भी शामिल थे। उनको सोमवार शाम को ही रिलीव कर विदाई भी दे दी गई, लेकिन जब इस आदेश के फर्जी होने की जानकारी मिली तो मंगलवार को उन्होंने फिर से पदभार ग्रहण कर लिया।

सोमवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के नाम से जारी तबादला आदेश में अशोकनगर नपा के प्रभारी सीएमओ पठान का जबलपुर जिले के मझौली तबादला किए जाने का जिक्र था। उनके अलावा आदेश में पीथमपुर, खरगापुर, बेगमगंज के सीएमओ और सहायक ग्रेड दो अधिकारियों के नाम भी थे। यह आदेश मिलने के बाद सोमवार शाम को ही पठान को रिलीव कर दिया गया और उन्हें अशोकनगर के पार्षदों व नपा कर्मियों ने विदाई भी दे दी।

आदेश में कई गलतियों से हुआ शक : उपसचिव राजीव निगम के हस्ताक्षर से तबादला आदेश जारी हुआ था, उसमें कई गलतियां थीं। मसलन, शेख अब्दुल हमीद प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की वर्तमान पदस्थापना नगर परिषद पीथमपुर जिला इंदौर और नवीन पदस्थापना भी नगर परिषद पीथमपुर जिला इंदौर दिखाई गई, जबकि पीथमपुर जिला धार में है। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 2 केएन पारदी का स्थानांतरण नगरपालिका परिषद बेगमगंज जिला दतिया से नगर परिषद लांजी जिला बालाघाट होना बताया गया, जबकि बेगमगंज रायसेन जिले में है। इसी प्रकार सोहल अलवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी का स्थानांतरण खरगापुर जिला टीकमगढ़ से नगर परिषद बीजापुर दिखाया गया, लेकिन बीजापुर किस जिले में है, इसका उल्लेख नहीं किया गया। इससे यह पूरी सूची संदेह के घेरे में आ गई।

मंत्री बोले-कोई तबादला सूची जारी नहीं की गई

अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी को जब तबादला आदेश का पता चला तो उन्होंने प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धनसिंह से बात की। इस पर मंत्री ने उन्हें बताया कि ऐसी कोई तबादला सूची जारी नहीं की गई है। इसके बाद सूची फर्जी होने का पता चला।

न्यूज गैलरी

अमरोहा में मदरसे में संचालक ने किया छात्रा से दुष्कर्म

अमरोहा : उप्र के अमरोहा में निजी मदरसे के छात्रावास में रहकर दीनी तालीम हासिल कर रही छात्रा के साथ मदरसा संचालक हाफिज बहार अली ने दुष्कर्म किया। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी छात्रा ने तीन दिन बाद मिलने पहुंचे माता-पिता को आप बीती सुनाई। पुलिस ने आरोपित हाफिज बहार अली के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित फरार है। आरोपित अमरोहा के एक गांव में निजी मदरसा चलाता है। मदरसे में छात्रावास की भी सुविधा है, जिसमें रहकर छात्राएं दीनी तालीम हासिल करती हैं। आरोप है कि 20 दिसंबर की रात 11 बजे मदरसा संचालक हाफिज सोते समय 12 वर्षीय छात्रा को जगाकर अपने कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने छात्रा को किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी दी। (जासं)

सीमा से चार घुसपैठिए गिरफ्तार

कोलकाता : सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उत्तर 24 पगरना जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम करते हुए चार घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाके में तस्करी को नाकाम करते हुए 25 मवेशियों एवं 350 बोतल फेंसिडिल भी जब्त किया है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की ओर से बताया गया कि सोमवार रात चलाए गए अभियान के दौरान उत्तर 24 परगना के गायघाटा थाना अंतर्गत बीओपी अंग्रेल क्षेत्र से एक बांग्लादेशी और तीन भारतीय मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। (जासं)

मुजफ्फरपुर में दो बदमाशों ने कैश वैन से 24 लाख लूटे

मुजफ्फरपुर : सिर्फ दो बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार को दिनदहाड़े बिहार के मुजफ्फरपुर में कैश वैन के कर्मी से 24 लाख नकदी और गार्ड की बंदूक लूट ली। यह लूट उस समय हुई, जब कर्मी एटीएम में कैश डालने वाले ही थी। कैश का परिवहन करनेवाली संस्था सीएमएस के कैस कस्टोडियन प्रिंस कुमार व नंदन कुमार ने बताया कि घटना को बाइक सवार दो अपराधियों ने अंजाम दिया। आने के साथ बदमाशों ने हथियार के बूते हमें अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कैश वैन के गार्ड की दोनाली बंदूक भी लूट ली। दोनों बदमाश भाग निकले। (जांस)

इंदौर नगर निगम का बर्खास्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निकला करोड़ों का मालिक

नईदुनिया, इंदौर

▸ सात बार निलंबित हुआ फिर भी मिलती रही अहम जिम्मेदारी

▸ पकड़ा गया तो बोला-'मैं गरीब हूं, शाम का चूल्हा कैसे जलेगा पता नहीं'

मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की इंदौर टीम ने नगर निगम के बर्खास्त बेलदार (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) और उसके भाइयों के निवास पर मंगलवार को छापेमारी की। बेलदार के पास करीब एक करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति मिली है, जबकि वेतन-भत्तों के रूप में उसे अब तक मात्र 22 लाख रुपये ही मिले हैं। उसे सात बार निलंबित किया गया, लेकिन हर बार बहाल होकर बिल कलेक्टर जैसी अहम जिम्मेदारी संभालता रहा। शिकायतों के चलते उसे इसी माह बर्खास्त किया गया था। अब पकड़ा गया तो बोला-'मैं गरीब हूं, शाम का चूल्हा कैसे जलेगा, पता नहीं।'

लोकायुक्त इंदौर के एसपी सव्यसाची सराफ के मुताबिक शिकायत मिली थी कि नगर निगम के बेलदार रियाज अंसारी ने बड़ी मात्रा में आय से अधिक संपत्ति एकत्रित कर ली है। इस पर मंगलवार सुबह डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल और टीम ने उसके घर छापेमारी की। टीम सुबह साढ़े पांच बजे स्नेहलतागंज स्थित देवछाया अपार्टमेंट पहुंची। यहां दरवाजा अंसारी ने खोला। इसी समय टीम ने नीचे के फ्लोर पर रहने वाले उसके भाई और मां के फ्लैट पर भी दबिश दी। उसके यहां से 50 हजार रुपये नकद, करीब पांच लाख के सोने-चांदी के जेवर आदि मिले। एसपी बघेल ने बताया कि 2003 में पिता की मौत के बाद रियाज को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। 16 साल की नौकरी में उसे वेतन-भत्तों के रूप में करीब 22 लाख रुपये ही मिले थे। इसकी तुलना में उसके यहां से तीन गुना से ज्यादा की संपत्ति मिली है।

अधिकारियों का चहेता रहा है रियाजः नगर निगम के बेलदार जैसे चतुर्थ श्रेणी पद पर रहते हुए करोड़पति बने रियाज अंसारी अपने राजनीतिक आकाओं के साथ कुछ अधिकारियों का भी चहेता रहा है। बेलदार का मूल काम साफ-सफाई और गड्ढे खोदना होता है, लेकिन उसे बड़ी जवाबदारी मिलती रही। सूत्रों के मुताबिक पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी में लगा रियाज अब तक सात बार निलंबित हो चुका है। रसूखदारों, राजनीतिक आकाओं और कुछ चुनिंदा अफसरों की शह पर वह बहाल होता गया और कमाई वाले पदों पर नियुक्तियां लेता रहा।

छापे में यह जायदाद मिली

- इंदौर के स्नेहलतागंज में दो फ्लैट, एक पेंट हाउस
- खजराना क्षेत्र की पाकीजा लाइफ स्टाइल कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान
- खजराना में बहन के नाम पर मकान
- 50 हजार रुपये नकद
- डस्टर कार और दो पहिया वाहन
- बीमा पॉलिसी और बैंक खाते
- 90 ग्राम सोने के जेवर
- 573 ग्राम चांदी के जेवर

बीएचयू में अब 'भूत विद्या' की भी पढ़ाई, छह माह का होगा कोर्स

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▸ अंधविश्वास दूर करने की दिशा में बड़ी पहल, आयुर्वेद संकाय में जनवरी से शुरू होगी पढ़ाई

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब भूत विद्या की भी पढ़ाई होगी। बीएमएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र ही इस कोर्स को कर सकेंगे। छह माह अध्ययन के बाद छात्र को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस कोर्स के संचालन का मुख्य उद्देश्य गांव-देहात में फैले अंधविश्वास को दूर करना है। भूत विद्या के साथ ही इस विषय की पहचान गृह चिकित्सा के नाम से भी होगी।

चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आयुर्वेद संकाय में इसका संचालन होगा। भूत विद्या पर शोध कर चुके प्रो. वीके द्विवेदी के नेतृत्व में इसका पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। जनवरी माह से इसकी पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इस विषय के अंतर्गत भूत विद्या की अवधारणा व भूत विद्या उपचारात्मक पहलू नामक दो पेपर होंगे। भूत विद्या की अवधारणा में परिभाषा, अनेक अर्थ, ऐतिहासिक महत्व, जनता में सामान्य समझ और आयुर्वेद में भूत विद्या की भूमिका के पाठ पढ़ाए जाएंगे। भूत विद्या उपचारात्मक पहलू के अंतर्गत चिकित्सा के प्रकार, ग्रह की प्रकृति, उपसर्ग की काय चिकित्सा पाठ पढ़ाए जाएंगे। भूत विद्या के अध्ययन के दौरान छात्रों को मानसिक बीमारी के इलाज के तौर तरीके बताए जाएंगे। यदि मरीज भूत-प्रेत बाधा से ग्रसित है तो प्राचीन चिकित्सा पद्धति को विज्ञान से जोड़ते हुए इलाज कर उसे स्वस्थ भी करेंगे। इसके बदले प्रमाणपत्रधारी प्रैक्टिस कर फीस भी ले सकेंगे।

> समाज में फैली भ्रांतियां दूर होंगी। भूत यदि है तो उसकी शांति के लिए मणि मंगल विधान विधि से चिकित्सा की जा सकेगी। उचित कारण का पहचान कर उचित चिकित्सा उपलब्ध कराना ही भूत विद्या का मूल उद्देश्य है। साथ ही समाज में भूत-प्रेत के नाम पर गरीबों को लूटने वालों में कमी आएगी।
>
> **-प्रो. सीएस पांडेय, सिद्धांत दर्शन विभाग, आयुर्वेद संकाय, बीएचयू**

रोजवैली घोटाले में कांग्रेस सांसद तलब

जागरण संवाददाता, कोलकाता : रोजवैली चिटफंड घोटाले में सीबीआइ ने मालदा दक्षिण से कांग्रेस सांसद अबु हासेम खान चौधरी से पूछताछ की। सांसद से चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की गई शिकायत को वापस लिए जाने की वजह जानने के लिए सवाल जवाब किए गए।

सूत्रों के अनुसार वर्ष 2009 में कांग्रेस सांसद अबु हासेम खान चौधरी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र भेजकर बंगाल में चल रही रोजवैली समेत अन्य चिटफंड कंपनियों के खिलाफ गैर कानूनी रूप से लोगों से रुपये एकत्र करने की शिकायत की थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही सांसद ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया था। आरोप है कि रोजवैली मुखिया गौतम कुंडू से सुलह होने के बाद ही सांसद ने शिकायत वापस ली थी। इसके लिए दोनों के बीच कोई लेनदेन हुआ था की नहीं आदि सवालों के जवाब तलाशने के लिए कांग्रेस सांसद को सीबीआइ ने नोटिस भेजकर तलब किया था। मंगलवार को सीजीओ काम्प्लेक्स सीबीआइ कार्यालय पहुंचे सांसद से जांच अधिकारियों ने पूछताछ की।

कैदियों के बच्चों को बाइबल पढ़ाने पर एफआइआर के आदेश

हसीन शाह, गाजियाबाद

▸ राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने छापेमारी कर की थीं 26 बाइबल बरामद

राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने साहिबाबाद में कैदियों के बच्चों को बाइबल पढ़ाने पर आशा दीप फाउंडेशन संस्था के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। तीन नवंबर को आयोग की टीम ने बालिका और बालक हॉस्टल में छापेमारी कर 26 बाइबल बरामद की थीं। यह संस्था जेल जा चुके लोगों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है और बच्चे संस्था के हॉस्टल में ही रहते हैं।

साहिबाबाद के शहीद नगर में आशा दीप फाउंडेशन संस्था जेम्स कांवेंट स्कूल चलाती है। इस स्कूल में नर्सरी से कक्षा दस तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में लगभग 600 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें 100 ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जिनके अभिभावक जेल में हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग को शिकायत मिली थी कि संस्था द्वारा कैदियों के बच्चों को चोरी-छुपे बाइबल पढ़ाई जा रही है। पिछले महीने आयोग की टीम ने दोनों हॉस्टल में औचक छापेमारी की। पूरे हॉस्टल की तलाशी ली गई। बच्चों के स्कूली बैग, बेड आदि सामान की तलाशी लेने पर 26 बाइबल बरामद की गईं। आयोग ने पूरी जांच पड़ताल के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी को संस्था के खिलाफ एफआइआर कराने के आदेश दिए हैं।

पांच जेलों में बंद कैदियों के बच्चे पढ़ते हैं : तिहाड़, डासना, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मंडोली जेल में बंद कैदियों के बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। जेल प्रशासन की अनुमति से इन बच्चों को लाया जाता है। दस साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या ज्यादा है।

> बिना अनुमति के ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की टीम बालिका हॉस्टल में घुस आई। उन्होंने हॉस्टल की तलाशी ली। हॉस्टल में 26 बाइबल मिली। हमारे यहां पर सभी धर्मों के ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। मगर जबरन किसी को धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता। इस संबंध में उनके स्वजनों को भी बता दिया जाता है। 1982 से यह संस्था चल रही है।
>
> **-एसके चेट्टी, डायरेक्टर, आशादीप फाउंडेशन**

बंगाल के दुर्गापुर ओवरब्रिज में फंसा विमान

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर

पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जाने वाले मेनगेट ओवरब्रिज के नीचे सोमवार सुबह ट्रेलर पर लदा परित्यक्त विमान फंस गया। इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। जागरण

शहर के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जाने वाले मेनगेट ओवरब्रिज के नीचे ट्रेलर पर लदा विमान फंस गया। जिसे देखने के लिए सोमवार सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ गई। बारह घंटा तक विमान ब्रिज में फंसा रहा, अंत में काफी प्रयास के बाद उसे सुबह 11 बजे ब्रिज से बाहर निकालने में सफलता मिली। जिससे ब्रिज एवं रास्ते को भी थोड़ी क्षति हुई। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की ओर से परिवहन संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी एवं फाइन वसूल किया जाएगा।

बताया जाता है कि एयर इंडिया का कार्गो विमान भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत था, जिससे पार्सल व अन्य सामग्री भेजी जाती थी। काफी समय से यह विमान इस्तेमाल में नहीं था। जिसे कोलकाता से राजस्थान के जयपुर भेजा जा रहा था। देर रात के समय विमान को ट्रेलर पर लादकर पहले कोलकाता-दिल्ली एनएच-दो के माध्यम से जयपुर भेजा जा रहा था। मेनगेट के पास मुख्य मार्ग पर विमान फंसने का डर था, इस कारण चालक ने सर्विस रोड का इस्तेमाल किया। जहां अचानक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ओवरब्रिज के नीचे विमान फंस गया। विमान के सामने के हिस्से को पर कर लिया, लेकिन बीच का हिस्सा पूरी तरह फंस गया। सुबह से ट्रेलर के मध्य स्थित पहियों का हवा निकालकर विमान को निकालने की कोशिश की गई। लेकिन अंत में सामने के पहियों का हवा निकालकर उसे बाहर निकाला गया। वहीं विमान फंसे होने की खबर शहर में फैल गई, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं सर्विस रोड में विमान फंसने से आवागमन में ज्यादा बाधा नहीं हुई, लेकिन डीएसपी कर्मियों एवं आसपास के लोगों को समस्या हुई। चालक घनश्याम ने बताया कि ट्रेलर जयपुर जा रहा था। वहीं कहा जा रहा है कि परिवहन संस्था की ओर से इतने बड़े विमान को ले जाने की अनुमति एनएचएआइ की ओर से नहीं ली गई थी, इस कारण संस्था को पत्र जारी किया गया है एवं फाइन भी वसूला जाएगा।

बंगाल में घने कोहरे में हादसा, पांच मरे

जागरण संवाददाता, वीरभूम : घने कोहरे में दिखाई नहीं देने पर ट्रैक्टर ट्राली ने झारखंड से प्रसूता को लेकर अस्पताल जा रही टाटा सूमो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सूमो चालक और उसमें सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। ट्राली में सवार 16 लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूत्रों के अनुसार बीते सोमवार देर रात झारखंड के पलसा इलाके में रहने वाला परिवार भाड़े के टाटा सूमो से गर्भवती महिला को लेकर रामपुरहाट मेडिकल कालेज एवं अस्पताल आ रहे थे। रामपुरहाट के विनोदपुर गांव के पास नेशनल हाइवे 60 पर पहुंचते ही घने कोहरे के बीच सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राली को एक अन्य वाहन ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। इससे ट्रैक्टर चालक ने नियंत्रण खोकर सूमो में जोरदार टक्कर मार दी। आमने सामने की भीषण टक्कर में सूमो चालक और प्रसूता के दो भाई और पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सूमो और ट्राली में सवार 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ट्रैक्टर ट्राली में सवार लोग तारापीठ में शव का अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे।

लापरवाही

फेंसिंग टूट जाने से आए दिन घुस जाते हैं जंगली जानवर, सरकारी रिकॉर्ड में न होने के कारण भगवान भरोसे मृगों की सुरक्षा

मौत के 'पिंजरे' में कैद 26 बेजुबान

अजय खंतवाल, पौड़ी गढ़वाल

कोटद्वार(पौड़ी गढ़वाल) के कण्वाश्रम स्थित मालिनी मृग विहार की लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी इलेक्ट्रिक फेंसिंग लाइन (बाएं) और विचरण करता मृग (दाएं)। जागरण

वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर जिन लोगों ने नियम कानून बनाए, उन्होंने ही वन्य जीवों को मौत के पिंजरे में कैद कर रखा है। यह तस्वीर है कोटद्वार से 12 किमी दूर कण्वाश्रम स्थित मालिनी मृग विहार की। यहां 'पिंजरे' में कैद 26 बेजुबानों को आए दिन अपनी जान बचाने के लिए जंगली जानवर गुलदार से जूझना पड़ता है। वन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से संचालित इस मृग विहार में न तो मृगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हैं और न ही उनके भोजन की कोई व्यवस्था है।

लैंसडौन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में 12 हेक्टेयर भूमि में फैले मृग विहार का उद्घाटन वर्ष 1954 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने किया था। वर्ष 1958 में मृग विहार को कोटद्वार अंचल के वन्य जीव प्रतिपालक के सुपुर्द किया गया और बाद में यह कालागढ़ टाइगर रिजर्व के संरक्षण में आ गया। टाइगर रिजर्व द्वारा मृग विहार पर ध्यान न दिए जाने के कारण वर्ष 2011 में यह फिर लैंसडौन वन प्रभाग के अधीन आ गया। इसके बावजूद यहां रहने वाले मृगों के भरण-पोषण व सुरक्षा के लिए धनराशि नहीं दी जाती है।

मिनी जू नहीं बना तो रेस्क्यू सेंटर का भेजा प्रस्ताव : वर्ष 2011-12 में लैंसडौन वन प्रभाग ने मृग विहार को मिनी जू में तब्दील करने का प्रस्ताव जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा था, लेकिन उसने न प्रस्ताव को नकार दिया, बल्कि यहां बिना अनुमति रखे गए मृगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दे दिए। लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ जीसी बेलवाल बताते हैं कि एक बार फिर मृग विहार को रेस्क्यू सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा गया है। इसे स्वीकृति का इंतजार है। मृग विहार खोलने से पूर्व इसके लिए जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अनुमति नहीं ली गई, जिस कारण यह कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं है। हालांकि, लैंसडौन वन प्रभाग विभिन्न मदों से मिलने वाली धनराशि से मृगों के भरण-पोषण व सुरक्षा का प्रबंध करता है। लेकिन, यह पर्याप्त नहीं है। मृग विहार के चारों ओर लगी इलेक्ट्रिक फेंसिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे आए दिन गुलदार घुस जाते हैं।

नौ माह में 15 मृग गायब : मार्च 2019 तक मृग विहार में 41 चीतल व नौ सांभर थे, लेकिन अब मात्र 20 चीतल व छह सांभर बच गए हैं। मृगों को चारे के नाम पर पत्तियां दी जाती हैं, जिसका प्रबंध दैनिक श्रमिक करते हैं।

मप्र के परिवहन मंत्री के ओएसडी पर जान से मारने की धमकी देने का केस

नईदुनिया, भोपाल

▸ सामाजिक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी

मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ओएसडी (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) कमल नागर पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। नागर पर आरोप है कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा को भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

मिश्रा ने बताया कि उन्होंने नागर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी। नागर इस बात से उनसे नाराज थे। 16 सितंबर को नागर ने परिवहन मंत्री के लैंडलाइन फोन से उन्हें मोबाइल पर कॉल कर जान से मारने की धमकी दी थी। नागर ने कहा था कि उसने शिकायत क्यों की। वह उसे जान से मरवा देगा। पूरे प्रदेश का परिवहन विभाग वही चलाता है। इसके बाद मिश्रा ने नागर के खिलाफ टीटी नगर थाने में शिकायत की थी लेकिन, पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो मिश्रा ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित निगम ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्री के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल तलब की थी। इससे यह साबित हुआ कि मंत्री के लैंडलाइन नंबर से मिश्रा के मोबाइल पर कॉल किया गया था। इस आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नागर के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करने के आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं, इस मामले में नागर का कहना है कि वे इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं। वे कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। उनके खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, जिनका वे नाम नहीं लेना चाहते हैं।

दैनिक जागरण

दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ

विभाजन की गलतियां सुधारने की कोशिश

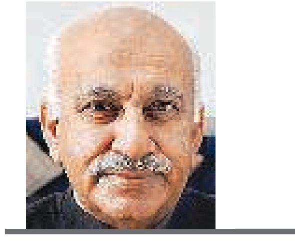

एमजे अकबर

पाकिस्तान भले ही अल्पसंख्यकों के बिना पूरा हो जाए, लेकिन भारत अपने सभी मुस्लिम नागरिकों के साथ ही भारत रह पाएगा

कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है। ऊपरी तौर पर घाव और उनके निशान भले ही भर जाएं, लेकिन उनकी पीड़ा गहरी पैठ बनाए होती है। खासतौर से तब जब उन जख्मों से जुड़ी यातनाएं कई पीढ़ियों ने झेली हों। भारत का विभाजन एक ऐसा ही पड़ाव था। भारतीय इतिहास में विभाजन जैसी त्रासदी की मिसाल शायद मुश्किल से ही मिले। भारतीय सभ्यता पर इस क्रूर आघात के खिलाफ नैतिक एवं राजनीतिक तर्कों के अलावा एक व्यावहारिक दलील यह भी दी जा सकती है कि विभाजन के लिए कोई स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। देश के लगभग प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में आबादी बहुत घुली-मिली हुई थी। खासतौर से पंजाब और बंगाल जैसे उन राज्यों में तो यह मिश्रण बहुत ज्यादा था जिनकी पाकिस्तान की आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी।

वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इसके अनुसार पंजाब में आधी और बंगाल में 40 प्रतिशत सीटें मुस्लिम लीग को देना तय हुआ। उनको मिली यह हिस्सेदारी उनकी वास्तविक संख्या से कहीं अधिक थी। आबादी में यह अनुपात तब भी बहुत ज्यादा नहीं बदला जब आस्था से अधिक राजनीतिक मंशा के साथ मुस्लिम नेता बने मुहम्मद अली जिन्ना ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के साथ मिलकर एकता के ढांचे के खिलाफ विषवमन शुरू कर दिया। 1946 के चुनावों में यह एक बार फिर तब सिद्ध हुआ जब मुस्लिम सीटों के इतने बड़े पैमाने पर आवंटन के बावजूद मुस्लिम लीग को बंगाल और पंजाब में कहीं भी बहुमत नहीं मिला। बहरहाल ऐसे कोई आंकड़े नहीं थे जो बता सकें कि लोग जहां रहते हैं वहां बस्तियों में उनकी बसाहट कैसी थी? वास्तव में विभिन्न मतों के लोगों का शांतिपूर्ण सहजीवन भारतीय मूल्यों से जनित सौहार्द का जीवंत प्रमाण था। तब समय-समय पर लोग विभाजन को लेकर चेता रहे थे। इनमें पंजाब के अंग्रेज गवर्नर ग्लेंसी भी शामिल थे। उन्होंने बार-बार चेतावनी दी कि विभाजन रक्तपात से कुप्रेरित अवधारणा है जो गृहयुद्ध को आमंत्रण है, मगर जिन्ना तो गृहयुद्ध चाहते ही थे। खासतौर से 16 अगस्त, 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जिहाद शुरू करके उन्होंने तेवर साफ कर दिए। उनकी इस घोषणा से कलकत्ता में वीभत्स हत्याओं का भयावह मंजर पैदा हो गया। इस ज्वालामुखी से निकले लावे ने जल्द ही नोआखली और बिहार को भी जद में ले लिया। हजारों लोग मारे गए। जनवरी 1947 में मुस्लिम लीग ने पंजाब में आगजनी शुरू की। इसका मकसद संघीय सरकार को नुकसान पहुंचाना था जो एक दशक से साबित कर रही थी कि पंजाब और भारत का शासन सहमति के साथ भी चलाया जा सकता है।

भारत में अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो वहां के हालात सुनकर वह सिहर उठे। दस्तावेजों में दर्ज ब्योरे में जो वर्णन है उससे किसी का भी मानवता में विश्वास हिल सकता है। गांधी जी ने अगस्त 1947 के पहले हफ्ते में पंजाब का दौरा किया। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके मुख से बरबस निकला, 'इतनी बर्बरता', 'इतनी पाशविकता।' गांधी जी को अपनी सहयोगी डॉ. सुशीला नैयर को एक शरणार्थी शिविर में रखना पड़ा ताकि भारत में शरणार्थियों के प्रवेश तक उन पर कोई हमला न हो। यही गांधीवादी तरीका है।

विभाजन के पीड़ितों के लिए केवल भारत ही स्वाभाविक शरणगाह था। पाकिस्तान निर्माण की मुहिम से जुड़कर अपने सपनों के देश में कूच करने वाले तमाम भारतीय मुसलमानों का जल्द ही उससे मोहभंग हो गया, लेकिन वह एक अलग कहानी है। अकाट्य सत्य यही है कि भारी तादाद में भारतीय मुसलमान अपनी मातृभूमि में ही रह गए। ऐसे तल्ख माहौल में भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए छह दिन की वार्ता के पश्चात 8 अप्रैल, 1950 को एक समझौता किया। इसे नेहरू-लियाकत समझौते का नाम दिया गया। इसका क्या हासिल हुआ वह इसके अगले कुछ दशकों के हैरतअंगेज आंकड़ों से मालूम पड़ सकता है। इस दौरान पाक में अल्पसंख्यकों की आबादी 25 प्रतिशत से घटकर महज दो प्रतिशत रह गई जबकि भारत में मुस्लिम आबादी की संख्या बढ़ती गई। यही एक लोकतंत्र और धर्मांध देश में अंतर है।

अवधेश राजपूत

ऐसा नहीं था कि विभाजन के सूत्रधारों को इसके विरोधाभासों या दुष्परिणामों का अंदाजा नहीं था। असल में वे संवेदनहीन बने हुए थे। जिन्ना के साथ अपनी वकालत की शुरुआत करने वाले एमसी छागला, जो बाद में इंदिरा गांधी सरकार में विदेश मंत्री भी बने, ने अपनी आत्मकथा 'रोजेज इन दिसंबर' में लिखा कि एक बार उन्होंने जिन्ना से पूछा कि अगर पाकिस्तान बना तो उत्तर प्रदेश और बिहार के भारतीय मुस्लिमों का क्या होगा? इस पर जिन्ना ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी परवाह नहीं।

वास्तव में जिन्ना को परवाह तो बंगालियों की भी नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान के अपने इकलौते दौरे पर ढाका में उन्होंने दो-टूक कहा कि उन्हें बंगाली भूलकर उर्दू को अपनी मातृभाषा बनाना होगा। शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने संघर्ष छेड़कर 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के धर्मांध ठप्पे को छुड़ाने वाली भाषिक परंपराओं के साथ अपने देश की नए सिरे से नींव डाली। हालांकि 1975 में शेख मुजीब की त्रासदपूर्ण हत्या से इस प्रक्रिया में कुछ गतिरोध आया, लेकिन सकारात्मक सामाजिक शक्तियों ने उसे पलट दिया। उनकी बेटी शेख हसीना ने अपने पिता की विरासत को और समृद्ध किया।

विभाजन बहुत नृशंस कवायद थी और किसी शरणार्थी से बेहतर इसे और कौन समझ सकता है? डॉ. मनमोहन सिंह भी ऐसे ही एक शरणार्थी रहे। यही कारण है कि उन्होंने 2003 में राज्यसभा में शरणार्थियों के लिए नागरिकता का मुद्दा उठाया। संयोग देखिए कि तब गृहमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी भी शरणार्थी रहे थे। नियति और भाग्य ने मनमोहन सिंह को 2004 में देश का प्रधानमंत्री बनाया जिस पद पर वह दस साल तक काबिज रहे। इस दौरान उन्होंने उस मांग को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं कि जिसे कभी उन्होंने ही उठाया था, लेकिन उनके बाद की सरकार ने अवश्य इस दिशा में कुछ किया।

हंगामे के इस दौर में जब अफवाहें और गुमराह करने वाली राजनीति की जा रही है तब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि इससे किसी भी धर्म या वर्ग के भारतीय नागरिक का कोई अधिकार नहीं छिनने जा रहा। यह सिर्फ विभाजन के समय की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया कदम है। इससे फिलहाल और भविष्य में भी किसी भारतीय मुसलमान के किसी अधिकार पर कोई आघात नहीं होगा। हमें यह याद रखना होगा कि पाकिस्तान भले ही अल्पसंख्यकों के बिना रह ले, लेकिन भारत अपने सभी भारतीय मुस्लिम नागरिकों के साथ ही भारत रह पाएगा।

(लेखक राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

एनपीआर की तैयारी

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर तैयार करने का फैसला करके उसी काम को ही आगे बढ़ाया है जिसे मनमोहन सरकार ने 2010 में किया था। यह भी ध्यान रहे कि इस काम की नींव तभी पड़ गई थी जब 2004 में मनमोहन सरकार ने ही नागरिकता कानून में संशोधन कर एनपीआर तैयार करने संबंधी प्रावधान जोड़ा था। इन तथ्यों के बाद राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले विपक्षी दलों के साथ-साथ आम जनता के समक्ष भी यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मोदी सरकार कोई नया काम करने नहीं जा रही है। यह समझा जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि एनपीआर तैयार करने की घोषणा होते ही यह दुष्प्रचार शुरू हो गया है कि यह तो पिछले दरवाजे से एनआरसी यानी नागरिकता रजिस्टर तैयार करने की कोशिश हो रही है। दुष्प्रचार के इस दौर में यह भी समझने की जरूरत है कि एनआरसी तैयार करना भी कोई गैर जरूरी या फिर गैर कानूनी काम नहीं। दुनिया के हर जिम्मेदार देश ने यह काम किया है। इनमें से कुछ वे भी हैं जो भारत से कहीं पीछे हैं। समझना कठिन है कि नागरिकों का रजिस्टर तैयार करने में हर्ज क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर कुछ लोग इस फालतू बात पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर ले रहे हैं कि एनआरसी तैयार करने का मकसद समुदाय विशेष को तंग करना है? आखिर जो काम पहले भी हो चुका है उसे लेकर हल्ला मचाने का क्या मतलब?

चूंकि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर लोगों को गुमराह करने का काम अभी भी चालू है इसलिए इसकी प्रबल आशंका है कि एनपीआर को लेकर भी ऐसा ही किया जाएगा। सरकार को इसकी काट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि एनपीआर तैयार करने का कैबिनेट का फैसला आते ही गृहमंत्री अमित शाह ने उन कई सवालों के जवाब दिए जो उठने शुरू हो गए थे, लेकिन बेहतर होगा कि सरकार आगे भी यह सिलसिला कायम रखे ताकि विपक्षी दल अपने दुष्प्रचार से लोगों को भ्रमित न करने पाएं। यह सतर्कता बरतनी इसलिए और आवश्यक है, क्योंकि कई राज्य सरकारें एनपीआर से पीछे हटने का शोर मचा सकती हैं। यह संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाली राजनीति के अलावा और कुछ नहीं होगा। सच तो यह है कि यह गरीब विरोधी राजनीति होगी, क्योंकि यदि एनपीआर सही तरह तैयार नहीं होता तो इससे सबसे अधिक नुकसान निर्धन तबके का ही होगा। जो राजनीतिक दल पहले से ही नागरिकता कानून, एनआरसी और अब एनपीआर पर लोगों को भड़का रहे हैं वे यह समझें तो बेहतर कि राजनीतिक क्षुद्रता की भी एक सीमा होती है।

राज्यपाल का विरोध

ऐसा लग रहा है कि बंगाल के विश्वविद्यालय और खासकर जादवपुर यूनिवर्सिटी (जेयू) राजनीति का अखाड़ा बन गया है। अक्सर ही जेयू कभी प्रबंधन व छात्रों के बीच विवाद तो कभी नारे व अन्य गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहता है। यहां ऐसा लगने लगा है कि पढ़ाई से अधिक छात्र-छात्राएं सियासी गतिविधियां व झंडा उठाने के साथ-साथ नारे बुलंद करने में लगे हैं। इस समय जेयू में जो हो रहा है उसको उचित नहीं कहा जा सकता। क्या बिना कुलाधिपति के किसी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो सकता है? परंतु ऐसा हुआ है। वह भी छात्रों के विरोध की वजह से बंगाल के राज्यपाल व कुलाधिपति जगदीप धनखड़ को एक बार फिर जेयू से लौटना पड़ा। मंगलवार सुबह जब वह जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचे तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने उनके काफिले को रोक लिया। इस दौरान हंगामे की वजह से अफरातफरी मची रही। गवर्नर का विरोध कर रहे छात्रों ने उन्हें कार से उतरने तक नहीं दिया। सुरक्षा बलों ने किसी तरह छात्रों को हटाने की कोशिश की। आज ही यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह प्रस्तावित था जिसमें उन्हें भाग लेना था। क्या सिर्फ इसीलिए कुलाधिपति व राज्यपाल का विरोध हो सकता है कि वह संसद व राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून का समर्थन कर रहे हैं? कुलाधिपति होने के साथ-साथ बंगाल के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते धनखड़ को हर विश्वविद्यालय में जाने का अधिकार है। जो छात्र उन्हें काला झंडा दिखा रहे थे और गो बैक के नारे लगा कर हंगामा बरपा रहे थे क्या यह उनका सही कदम है? छात्रों के इस कदम से विश्वविद्यालय का नाम रोशन नहीं हो रहा है, बल्कि बदनामी हो रही है। अगर छात्रों की कोई मांग है और उन्हें कुछ कहना है तो शांतिपूर्वक बिना किसी नारेबाजी व हंगामे के राज्यपाल तक बात पहुंचा सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले सोमवार को भी राज्यपाल से जेयू में छात्रों ने दो बार धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए थे। राज्यपाल धनखड़ ने अपने साथ हुए बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर इशारों में वार किया। उन्होंने कहा, एक चांसलर और गवर्नर के रूप में मेरे लिए यह बहुत दर्दनाक समय है। हमारे छात्र कन्वोकेशन में डिग्री पाने का इंतजार कर रहे हैं। वह उनके कठिन परिश्रम का फल है। प्रबंधन को चाहिए कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और छात्रों के साथ बैठकर ऐसी हालत फिर न बने यह सुनिश्चित करना चाहिए।

क्या बिना कुलाधिपति के किसी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो सकता है? परंतु, ऐसा हुआ है

असहमत नागरिकों का आचरण

राजीव सचान

असहमत नागरिकों के अतार्किक आचरण पर हैरानी नहीं, क्योंकि विवेक तब भी मर जाता है जब उन्माद की अति हो जाए

नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी के विरोध के नाम पर उपजा उन्माद कुछ शांत होता तो दिख रहा है, लेकिन दुष्प्रचार का सिलसिला अभी भी कायम है। इसका कारण केवल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सरीखे दलों की यह रट नहीं है कि नागरिकता कानून संविधान विरोधी है और एनआरसी का असल मकसद मुसलमानों को परेशान करना एवं उन्हें घुसपैठिया करार देना है, बल्कि कुछ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अन्य अनेक लोगों की ओर से किया जाना भी है। जो यह सब प्रचारित कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं वे संवैधानिक या कानूनी मसलों की सही-सटीक समझ न रखने वाले कोई आम नागरिक या फिर अनपढ़ लोग नहीं। वे तो अपने-अपने क्षेत्र के जाने-माने लोग यानी विशिष्ट नागरिक हैं। इनमें कई सेलेब्रिटी और बुद्धिजीवी कहे-बताए जाने वाले तो हैं ही, मीडिया के जाने-पहचाने चेहरे भी हैं। ये सब नागरिकता संशोधन विधेयक के कानून बन जाने पर सरकार एवं संसद के फैसले से असहमत भी हैं और आगबबूला भी-इस कदर कि उन करीब 60 याचिकाओं की सुनवाई का इंतजार करने को भी तैयार नहीं जो इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। वे संविधान की शपथ भी ले रहे हैं और सड़क पर निकलकर संसद से पारित कानून को खारिज किए जाने की जिद भी कर रहे हैं।

इस दुष्प्रचार अभियान में आतंकी को हेडमास्टर का बेटा समझने वाले लोग, 90 प्रतिशत भारतीयों को मूर्ख समझने वाले जज, अपने शो के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता तय करने और फिर भी कागज नहीं दिखाएंगे का स्वांग रचने वाले कलाकार, धारा 144 को आपातकाल का साफ संकेत समझने वाले फिल्मकार और वंदे मातरम पर बिदकने, किंतु ताज उछाले जाएंगे को आदर्श तराना समझने वाले विद्वान भी हैं। इनकी कोशिश केवल इतनी ही नहीं कि जो चुपचाप हैं वे भी सड़कों पर निकलें, ये तो उन सबको भाजपाई-संघी अथवा डरपोक होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर रहे जो उनकी हां में हां नहीं मिला रहे या फिर इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे कि भारत अब बस हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है। ये विशिष्ट नागरिक फर्जी सूचनाओं का सहारा लेने के साथ यह भी बताने में जुटे हैं कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जहां-जहां आगजनी और तोड़फोड़ भरी हिंसा हुई वह वास्तव में पुलिस या सरकार अथवा उसके एजेंटों ने उन्हें बदनाम करने के लिए की। इनकी मानें तो

दिल्ली, अहमदाबाद के साथ उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कई शहरों में पुलिस ने ही पुलिस पर पत्थर बरसाए, पेट्रोल बम फेंके और मौका पाकर सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों को आग लगाने का काम भी किया।

असहमत नागरिकों के अतार्किक आचरण पर हैरानी नहीं, क्योंकि विवेक तब भी मर जाता है जब उन्माद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। इसी उन्माद के कारण यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि अव्वल तो देश में कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही और यदि कहीं हो भी रही तो उसका हमारे स्वघोषित अहिंसावादी प्रदर्शनकारियों से कोई लेना-देना देना नहीं। रेलवे की 90 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई, दर्जनों वाहन जला दिए गए और सैकड़ों पुलिसकर्मी जख्मी किए गए और फिर भी रट यही कि हमारा विरोध प्रदर्शन तो गांधी-आंबेडकर के हिसाब से चल रहा है। शांति का छद्म पाठ करने की ऐसी सनक सवार है कि उत्तेजक नारों की भी अनदेखी की जा रही।

इससे इन्कार नहीं कि हिंसा के विरोध के बहाने कुछ भाजपा नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर बेतुकी और उत्तेजक टिप्पणियां कीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि देश खुली हिंसा को देखकर भी अनदेखा कर दे। विशिष्ट जन यही चाह रहे। वे यह समझने को तैयार नहीं कि आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं देश की बदनामी करा रहीं, क्योंकि दुनिया देख रही कि भारत में जगह-जगह गांधी के पोस्टर भी लहराए जा रहे और जमकर पत्थरबाजी-आगजनी भी की जा रही। शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में पागलपन भरी हिंसा से भी शर्मनाक था उन लोगों की ओर से उसकी अनदेखी जो संविधान की दुहाई देने में लगे हुए थे। यह और कुछ नहीं देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ही थी। सरकार को केवल यही नहीं सुनिश्चित करना होगा कि अराजकता फैलाने वाले दंड के भागीदार बनें, यह भी देखना होगा कि आखिर लोगों को भड़काने का काम किसने किया? उसे पुलिस सुधार पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ जगह पुलिस की अनावश्यक सख्ती की शिकायतें आईं तो कई जगह वह अराजक तत्वों के समक्ष संसाधनहीन और असहाय सी दिखी। सरकार और खासकर मोदी सरकार को यह भी समझना होगा कि एनआरसी को लेकर इतनी अस्पष्टता क्यों उपजी कि उसका फायदा विरोध की आड़ में अराजकता फैलाने वालों ने उठा लिया?

निःसंदेह एनआरसी ने भ्रम पैदा किया, लेकिन आखिर भ्रम निवारण का काम समय रहते क्यों नहीं किया गया और वह भी तब जब यह साफ दिख रहा था कि लोगों को भ्रमित ही नहीं, भयभीत करने का सुनियोजित अभियान छिड़ा है? नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध के नाम मुस्लिम समाज के लोगों को खास तौर पर सड़कों पर उतारने वाले अपने सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान की सफलता पर खुश हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने इस समाज की बड़ी ही कुसेवा की है। मुस्लिम समाज को यह आभास हो तो बेहतर कि अपने शातिर एजेंडे को पूरा करने के लिए उसे सड़क पर उतारने वालों ने उसे बदनाम करने का ही काम किया। क्या वह मिसाल फीकी नहीं पड़ी जो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समाज ने शांति और संयम का परिचय देकर कायम की थी? यदि कोई तथाकथित मुस्लिम हितैषी सपने में भी यह सोच रहा है कि आज के इस युग में कोई देश अपने यहां के करोड़ों नागरिकों को गैर-नागरिक घोषित कर सकता है तो वह या तो चीन में रह रहा है या फिर अंध विरोध से इस कदर ग्रस्त हो गया है कि अपनी तर्कशक्ति पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते-न अपना और न ही उनका जिनके हितैषी बनने का दम भर रहे हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आनंद के रास्ते

इस धरती पर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपने ईश्वर से यह मांगता हो कि हमें अपार कष्ट दे दीजिए, शरीर रोगग्रस्त हो, धन की कमी हो और हमें सुकून की नींद न मिले, बल्कि हर व्यक्ति अपने इष्टदेव से आनंद और उत्तम जीवन ही मांगता है। जो खुद को नास्तिक कहते हैं तथा ईश्वरीय शक्ति को नकारते हैं, वे भी अंतर्मन से परमानंद की सत्ता को स्वीकार कर आनंद ही चाहते हैं। ऐसी कामना के बावजूद अधिकांश लोग यत्र-तत्र दुखी होने का रोना रोते दिख जाते हैं। दरअसल आनंद के कई रास्ते हैं। व्यक्ति पंचमुखी चौराहे पर खड़ा होकर यदि सभी रास्तों की जानकारी नहीं करेगा तो वह एक ही रास्ते पर चलता रहेगा। ये पंचमुखी रास्ते हैं पंच ज्ञानेंद्रियां। अब कोई व्यक्ति केवल स्वाद के लिए जिएगा तो संसार के अद्भुत दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श से वंचित हो जाएगा। सभी ज्ञानेंद्रियों से आह्लाद व्यक्ति ले तो वह एकांगी नहीं होगा। व्यक्ति को श्रवण के लिए सत्संग में प्रवचन, संगीत, मंत्रों के पाठ को सुनना चाहिए। इससे भी मन को सुकून मिलता है। दृश्य के लिए प्रकृति को भरपूर देखना चाहिए।

सूर्योदय के वक्त प्रकृति अपना अद्भुत शृंगार इसीलिए करती है कि लोग इससे लाभान्वित हों। गंध-सुगंध के लिए पेड़-पौधों के आसपास कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। स्पर्श सुख के तहत माता-पिता, गुरुजनों के चरण-स्पर्श, छोटे बच्चों को गोद लेने तथा खेलने से भी ऊर्जा मिलती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण जब हो रहा था तो उसके संस्थापक पं. मदनमोहन मालवीय रात में जाकर मजदूरों द्वारा बनाई गई दीवारों को पुत्रवत स्पर्श कर आह्लादित होते थे। इन सभी उपायों से वैविध्यपूर्ण शरीर में आनंद के रसायनों का जो निर्माण होगा, वह व्यक्ति को दुखी नहीं होने देगा। वर्तमान भौतिक दौर में व्यक्ति सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए यदि उतावला रहेगा तो उसका जीवन एक ही रस पाएगा जो आगे चलकर नीरसता उत्पन्न करेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त पंचज्ञानेंद्रियों का हमेशा सदुपयोग करे।

सलिल पांडेय

भरोसा बढ़ाने वाला फैसला

डॉ. मोनिका शर्मा

उन्नाव केस में आया फैसला समाज के हर परिवार को अपराध के खिलाफ लड़ने और डटे रहने की हिम्मत देने वाला है

कुटिल साजिशों, भयावह दुर्घटनाओं, अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या तक के मामले वाले उन्नाव केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायालय ने उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर एक जनप्रतिनिधि था, मगर उसने लोगों का विश्वास तोड़ा। गौरतलब है कि 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में जेल में रहते हुए भी पीड़िता एवं उसके परिजनों को प्रताड़ित किया। 2019 में पीड़िता के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क हादसा हुआ। उसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई। लड़की के पिता की हिरासत में मौत का तकलीफदेह मामला सामने आया। फिर उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करा दिए गए। यहां तक कि देश के प्रधान न्यायाधीश को भी उसका लिखा पत्र देरी से मिला। विवशता की हद देखिए कि न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़िता और उसकी मां द्वारा मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास भी किया गया। बावजूद इसके हर तरह से आतंकित किए गए इस परिवार ने रसूखदार विधायक के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। हमारी व्यवस्था की खामियों से जूझने की हिम्मत दिखाई। यकीनन यह पीड़िता और उसके परिवार का साहस ही है कि वे नाउम्मीदी और असुरक्षा के हालातों में भी न्याय पाने के लिए संघर्ष करते रहे।

इस मामले से जुड़े जितने भी पक्ष सामने आए, वे सभी हमारी व्यवस्था की खामियों और निराश करने वाली स्थितियों को उजागर करने वाले रहे। यह घटनाक्रम एक ताकतवर नेता के आगे समाज के आम परिवार की बेबसी को बयान करने वाला था। जिसमें एक बेटी का मान ही नहीं लूटा गया, बल्कि आवाज उठाने पर उसकी और उसके अपनों की जान तक लेने की साजिश रची गई। सिलसिलेवार ढंग से हुई घटनाओं ने इस परिवार को बेहद पीड़ादायी हालातों तक पहुंचा दिया।

दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि यह देश का एक अकेला मामला भी नहीं है। हमारे यहां जनता का विश्वास जीतकर प्रतिनिधि बने कई चेहरे ऐसे अपराधों के लिए कठघरे में हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक दशक में सांसदों पर महिला अपराध के दर्ज मामलों में 850 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है। मौजूदा समय में 18 सांसद और 58 विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं।

समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे लंबित मामलों में पीड़ित हर परिवार किन हालातों से जूझता होगा? ऐसे अधिकतर मामलों में आवाज उठाने वाले परिवारों का धन और बल के दम पर जीना दुश्वार कर दिया जाता है। ऐसे में उन्नाव केस में आया यह फैसला न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने वाला है। समाज के हर परिवार को अपराध के खिलाफ लड़ने और डटे रहने की हिम्मत देने वाला है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मोदी पर निर्भर भाजपा

झारखंड में खुद से हारी भाजपा शीर्षक से लिखे लेख में अवधेश कुमार ने झारखंड विधानसभा में भाजपा को मिली हार का कारण वहां के इसके स्थानीय नेताओं की गलतियों को माना है। लोकतंत्र में हर चुनाव में ऊंट किस करवट बैठ जाए यह कोई नहीं जान सकता। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है। वह हर चुनाव को अलग-अलग नजरिये से देखते हुए अपने कीमती वोट का प्रयोग करता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व का अतिविश्वास हर चुनाव में उस पर भारी पड़ सकता है। वर्ष 2019 में भाजपा के लिए मोदी का नेतृत्व लोकसभा चुनाव में तो शानदार रहा, लेकिन इस वर्ष कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसे निराशा भी हाथ लगी। हरियाणा और अब झारखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बिखरता नजर आया। भाजपा के बहुत से नेता वोट तो पीएम मोदी के नाम पर मांगते हैं, लेकिन आमजन के लिए काम मोदी की नीयत से नहीं करते हैं। इसका नकारात्मक असर चुनावों में जरूर पड़ता है। भले ही भाजपा के लोग इस बात को नकार दें, लेकिन यह हकीकत है। भाजपा हाईकमान को अपने उन नेताओं के प्रति सख्ती दिखानी चाहिए जो आम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में आनाकानी करते हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

गो-एयर को लगी लताड़

जब एक व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा करता है तो उसे ये पता नहीं होता कि क्रू मेंबर्स या पायलट कितने दिनों से लगातार ड्यूटी कर रहा है। कहीं ये लोग थके हारे तो नहीं हैं। मजबूरी में ड्यूटी कर ये सबकी जान तो जोखिम में नहीं डाल रहे। हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलटों और क्रू को तय समय से ज्यादा काम कराने के लिए गो-एयर को लताड़ लगाई है। एयरलाइन ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते इसके क्रू को लगातार चार रातों तक उड़ान भरनी पड़ी। एफडीटीएल गाइडलाइंस बनाने का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि ये लोग थकान का शिकार न हों और उड़ानें भी सुरक्षित रहें।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

अब कुछ करना होगा

कांग्रेस मुक्त भारत के स्थान पर भाजपा को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा ही शोभा देता है, पर अफसोस कि वह ये सब तो कर नहीं पाई दुर्भाग्य से कुछ कार्यों के कारण उलटे अब उसे ही ग्रहण लग गया। उसकी लोकप्रियता भी अब निरंतर घटती जा रही है। अब हालत ऐसी है कि उसे जनवादी समस्याओं को लेकर बहुत पारदर्शी होकर चलना होगा। भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस को भी उसका घमंड ले बैठा। आज देश के सामने अनियंत्रित जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, नाजुक अर्थव्यवस्था जैसी समस्याएं हैं। अराजकता, दुष्कर्म और हत्या, लचर कानून ने पूरे शासन को ही हिलाकर रख दिया है। भाजपा को यदि अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उसे क्रांतिकारी पार्टी के रूप में उभरना होगा। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना होगा। एक सौ तीस करोड़ जनता पर शासन का गर्व तो सभी करते हैं, मगर उस जनता के लिए वे क्या करते हैं यह बात किसी से छुपी नहीं है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय सरकार उलटा रोजगार को खत्म ही कर रही है।

वेद मामूरपुर, नरेला

जनता सिखाएगी सबक

नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी के संबंध में विचार विमर्श एक साथ ही आमजन तक पहुंचा। नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा व राज्यसभा से पास होकर व एनआरसी लागू किए जाने की सरकार की भावी योजना है। मोटे तौर पर पहले में प्रावधान है कि तीन देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई व बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक समुदाय को देश की नागरिकता दे दी जाए और दूसरे में प्रावधान है कि देश से घुसपैठिये को बाहर कर दिया जाए। लेकिन मोदी विरोध व भाजपा विरोध में कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं ने इसे देश की जनता खासकर मुस्लिमों के समक्ष इसे इस तरह पेश किया जैसे सरकार कि मंशा मुस्लिमों को देश से बाहर निकालना है।

मनोज कुमार, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

54,013 के करीब मुकदमे लंबित हैं देश की सर्वोच्च अदालत में। वहीं 3.32 करोड़ मामले देश की निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। इसमें 2.85 करोड़ से भी ज्यादा मुकदमे निचली अदालतों में लंबित हैं।

झारखंड

इस पराजय को टाल सकती थी भाजपा

चंदन कर्ण
राजकीय अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय, गोपीकांदर, झारखंड

यह सही है कि भाजपा की सरकार ने झारखंड में निवेश को बढ़ाने तथा इसके द्वारा रोजगार के नए अवसरों के सृजन के उद्देश्य से सीएनटी-एसपीटी एक्ट में कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया था, लेकिन इस पर आदिवासी समाज की आपत्ति को देखते हुए उसने अपने कदम पीछे भी खींच लिए थे। इसके बाद भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर आदिवासियों को भड़काने का काम जारी रखा, जो विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि सफल भी रहा

झारखंड में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रघुवर दास। फाइल फोटो

झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों की कई तरह से व्याख्या की जा रही है। कुछ जानकार इस सवाल का जवाब ढूंढ़ रहे हैं कि जिस भाजपा को अभी कुछ महीने पहले ही आम चुनाव में झोली भर-भर के वोट मिले थे, उसकी ऐसी निर्णायक हार कैसे हुई। इसके कुछ कारण गिनाए जा रहे हैं तथा कुछ गढ़े भी जा रहे हैं, जैसे कि नागरिकता संशोधन कानून को झारखंड की जनता ने नकार दिया अथवा एक गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री का भाजपा का दांव उल्टा पड़ गया आदि। बताया यह भी जा रहा है कि झारखंड बेशक छोटा राज्य है, लेकिन इस जनादेश का राष्ट्रीय संकेत काफी महत्वपूर्ण है। यह भी कहा जा रहा है कि बीते पौने दो साल में देश का राजनीतिक नक्शा जिस तरह से बदला है और जिस तरह से एक-एक कर पांच महत्वपूर्ण राज्य भाजपा के हाथ से फिसल गए हैं, वह उसके सिकुड़ते जनाधार को दर्शाता है।

मेरा मानना है कि सत्य सदैव सहज होता है और उसे ढूंढ़ने के लिए बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह संभव है कि नागरिकता कानून के बाद एक वर्ग विशेष में कुछ हद तक गोलबंदी हुई हो तथा विपक्ष विशेषकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी कार्ड का भी कुछ असर रहा हो, लेकिन झारखंड की राजनीति को जानने वाले इस तथ्य से अवगत हैं कि ये वे तबके हैं जो कभी भाजपा के जनाधार वाले वर्गों में शामिल नहीं रहे। हालांकि यह भी सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाया है और उसने आदिवासियों की एकमात्र पार्टी की छवि रखने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटों में सफलतापूर्वक सेंध लगाई है। इससे चिंतित झामुमो तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने सूबे की कुल आबादी में 26 प्रतिशत का हिस्सा रखने वाले आदिवासियों को प्रस्तावित सीएनटी-एसपीटी संशोधन कानून की आड़ में खूब भड़काया। कहा गया कि भाजपा की सरकार आदिवासियों की जमीन छिनना चाहती है, एक गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री रहते आदिवासी समाज का कभी भला नहीं हो सकता आदि-आदि।

यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ाने तथा इसके द्वारा रोजगार के नए अवसरों के सृजन के उद्देश्य से सीएनटी-एसपीटी एक्ट में कुछ संशोधन का प्रस्ताव किया था, लेकिन इस पर आदिवासी समाज की आपत्ति को देखते हुए उसने अपने कदम पीछे भी खींच लिए थे। तब भी विपक्ष द्वारा आदिवासी कार्ड का दुष्प्रचार जारी रहा, जो चुनाव के परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि सफल भी रहा। दूसरी तरफ एक सच यह भी है कि भाजपा सरकार ने अपने शासन में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन तथा सभ्यता-संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे कि आदिवासी युवतियों को बहकाकर और उनसे शादी कर उनकी जमीनों पर कब्जा करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए विशेष कानून लाया गया। कोई भी आदिवासी बहुल गांवों का भ्रमण कर इस स्थिति से भली-भांति अवगत हो सकता है कि उनकी जमीनों पर कितनी बड़ी मात्रा में इस तरीके से कब्जा किया गया है। आरोप है कि इस तरह कब्जा करने वालों में बड़ी संख्या अवैध घुसपैठियों की है। इसके अलावा आदिवासियों को लोभ-लालच देकर उनका धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानून बनाया गया, ताकि उनकी सभ्यतागत विशिष्टताओं की रक्षा की जा सके। अफसोस कि आदिवासियों के हित में उठाए गए इन महत्वपूर्ण कदमों के संदेश उस समाज तक ठीक तरह से नहीं पहुंचाए जा सके। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा के पास आदिवासी नेताओं का अभाव है, लेकिन कहा जा रहा है कि राज्य के शीर्ष नेतृत्व में असुरक्षा की भावना थी और इस वजह से ही इन महत्वपूर्ण चेहरों का सहयोग लेना उचित नहीं समझा गया। इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा।

इस चुनाव में जिन बातों ने भाजपा की संभावनाओं पर सबसे बुरा असर डाला, उनमें से पहला तो यह है कि गठबंधन के इस दौर में भाजपा लगभग अकेले चुनाव लड़ रही थी और विरोधी लगभग एकजुट थे। दूसरी बात यह कि भाजपा के भीतर का असंतोष और बगावत भी बहुत स्पष्ट था। चुनाव में पड़े मतों की समीक्षा करें तो पाएंगे कि करीब 20 सीटों के नतीजे बदल सकते थे, यदि केवल उक्त दोनों समस्याओं का समाधान कर लिया गया होता। उदाहरण के लिए सिर्फ आजसू पार्टी से यदि गठबंधन को बरकरार रख लिया जाता तो डुमरी, जुगसलाई, ईचागढ़, लोहरदग्गा, नाला, जामा, रामगढ़, बड़कागांव, खिजरी, चक्रधरपुर, मधुपुर, घाटशिला जैसी सीटें आसानी से इस गठबंधन की झोली में आ सकती थीं। इनके अलावा सरायकेला, जरमुंडी, मनोहरपुर तथा सिमडेगा जैसी सीटों पर भी दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे को निर्णायक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया। भाजपा ने जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम की दो सीटें केवल सरयू राय की बगावत की वजह से गंवा दी। इस स्थिति को टाला जाना चाहिए था। सवाल यह है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के लिए आगे की राह क्या हो?

निःसंदेह यह उसके मनोबल को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता है, लेकिन नतीजों में उसके लिए कुछ सबक भी हैं। पहली बात तो यह कि जिन तात्कालिक कारकों जैसे-सहयोगी दलों से गठबंधन न हो पाना अथवा पार्टी के अंदर की बगावत ने पार्टी की संभावनाओं पर सबसे ज्यादा असर डाला, उसे सकारात्मक कदम उठाकर आसानी से दुरुस्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भले ही उसे संथाल क्षेत्र की 18 सीटों पर आशानुरूप सफलता न मिली हो, किंतु हारी हुई कई सीटों पर उसने हार का अंतर पिछले विधानसभा चुनाव से कम किया है। जाहिर है कि जिस तरह से वह पिछले कुछ समय से झामुमो के आदिवासियों की एकमात्र पार्टी होने के दावों को चुनौती देती आई है, वह चुनौती तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद आज भी कायम है। यही वह जगह है, जहां से भाजपा को अब आगे बढ़ना है।

भाजपा नेतृत्व की गलतियां

रिजवान अंसारी

देखा जाए तो भाजपा की इस हार की पटकथा पांच साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 2014 में भाजपा ने जब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में सत्ता हासिल की तो उसने परंपरा से हटकर कुछ जोखिम भरे फैसले लिए थे। महाराष्ट्र में गैर-मराठा, हरियाणा में गैर-जाट और झारखंड में गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री को गद्दी पर बिठाया। नतीजा यह हुआ है कि अगले चुनाव में महाराष्ट्र में कम सीटें पाकर भाजपा कमजोर हुई, हरियाणा में भी कम हुई और जजपा के सहारे सत्ता की जुगत हो सकी और झारखंड में भी वह अपनी हार बचा नहीं सकी। पार्टी के इस कदम ने वहां कि बहुसंख्यक आबादी को सशंकित किया। कई ऐसी खबरें आईं जब रघुवर दास पर आदिवासियों के खिलाफ काम करने के आरोप लगे। आदिवासियों की जमीन को मनामाने तरीके अधिग्रहित करने के भी आरोप रघुवर दास पर लगते रहे। लिहाजा जड़, जमीन और जंगल प्रेमी आदिवासी एक गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री को संदेह की नजरों से देखने लगे।

दूसरी बड़ी वजह रही भ्रष्टाचार पर रघुवर सरकार का ढुलमुल रवैया। जिसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा को अपनी ही पार्टी के सरयू राय से दो-दो हाथ करने पड़े। लिहाजा भाजपा का पूरा खेल ही बिगड़ गया। सरयू राय वह शख्स हैं जिन्होंने बिहार के चारा घोटाला को उजागर किया, बाबूलाल मरांडी की सरकार में 8000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया। यहां पर भी भाजपा ने कई गलतियां की जिससे पूरे सूबे में गलत संदेश गया। इतना हीं नहीं, 130 करोड़ रुपये के दवा घोटाले के आरोपी भानु प्रताप शाही को पार्टी ने टिकट दिया और सरयू राय को टिकट देने से इन्कार कर दिया, जबकि वह मंत्री थे और भाजपा के वरिष्ठ सदस्य भी। नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ ही सरयू राय खड़े हुए और चुनाव जीत भी गए। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ा मिथक थोड़ा अजीब है। झारखंड के अब तक के सभी पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं। इस मिथक को तोड़ने की चुनौती रघुवर दास के कंधों पर थी, लेकिन वह भी नाकाम रहे।

तीसरी वजह की बात करें तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड की स्थानीय समस्या को पहचानने में गलती की। इसमें कोई दो राय नहीं कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। वहां की अपनी समस्याएं हैं। खनन, भूमि, भुखमरी झारखंड की पुरानी समस्याएं रही हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व वहां अनुच्छेद-370, 35ए, नागरिकता संशोधन कानून जैसे राष्ट्रीय मुद्दे गिनाता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि आदिवासी बहुल इलाके वाले 28 सीटों में से भाजपा को 26 पर हार देखनी पड़ी। यकीनन जनता ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर उनकी समस्याओं पर बात नहीं होगी तो वह किसी भी पार्टी को नकार सकती है।

चौथी वजह, एकला चलो वाली भाजपा की नीति भी उसके खिलाफ गई। साथी आजसू पार्टी को अलग कर चुनाव लड़ने के फैसले ने भी पार्टी को कमजोर किया। 2014 में आजसू की 5 सीटों के सहार ही भाजपा सरकार में आ सकी थी, लेकिन इस दफा पार्टी के अलग चुनाव लड़ने के फैसले से कई सीटों पर आजसू ने नुकसान पहुंचाया। इससे इतर मुख्यमंत्री रघुवर दास के कामकाज के तरीके भी सरकार के खिलाफ गए। पिछले पांच वर्षों में कई ऐसे मौके आए जब रघुवर दास के व्यवहार पर सवाल उठाए गए। सरयू राय द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रघुवर दास को कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देना चाहिए था। इससे पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से अच्छा संदेश जाता, लेकिन बजाय इसके सरयू राय को पार्टी से दरकिनार किया गया।

गौर करें तो ये वे कारण हैं जिन पर भाजपा पूरे जज्बे के साथ काम कर सकती थी और अपनी हार टाल सकती थी, लेकिन पार्टी के अति-आत्मविश्वास ने विपक्षियों को सत्ता की चाबी थमा दी। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों पर सियासी दल एक-दूसरे को घेरते हैं उन बिंदुओं पर कम-से-कम इन्हें खुद को पाक साफ साबित करना ही होगा। अन्यथा जनता इन्हें कभी भी धूल चटा सकती है।

खरी-खरी

अपने-अपने चश्मे, अपना-अपना नजरिया

विजी श्रीवास्तव

मन और प्राणों में तो तुम पहले से ही हो। आओ, अब हमारे घर-आंगन में बस जाओ। परदेसी दुख-दर्दों को किरायेदारी छोड़कर जमीन का पट्टा देते हुए हुकूमत ने कहा। बांध टूटते ही बाढ़ आएगी, यह अंदेशा पहले से ही था। इसलिए कुछ लोग झंडे, डंडे, तख्ती-पोस्टर, पत्थर के इंतजाम करने दौड़े तो प्रवक्ताओं ने फटाफट कुर्ते, अचकन, कोट-टाई पहनकर टीवी स्टूडियो की ओर जुबानी-जंग लड़ने के लिए दौड़ लगाई। एक सुरमई आवाज उठी-भाई जान! माना वहां दुख बहुत हैं। पर हमारे यहां कब कम हैं, जो यहां-वहां से इम्पोर्ट कर रहे हो? इनके पति का एक्सपोर्ट का बिजनेस था। प्रवक्ता दवा उद्योग से जुड़े होंगे, बोले-उनके और इनके दुख-दर्द में कितना जमीनी फर्क है, यह तो देखो। वे घाव करते हैं और उनकी फैक्ट्रियों में इनके लिए मरहम नहीं बनता। तो इनके रंजो-गम यहां कैसे कम कर लोगे। वो छोड़ो, वहां घुट-घुट दुखी रहने से अच्छा है कि इधर खुलकर दुखी हो। यहां कंधा देने के लिए बेकाम सहारे और गमगीन माहौल बनाने वाले भी खूब हैं। पर आप अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करें, यह ठीक नहीं। दुखों का कोई मजहब होता है क्या? आप भेदभाव कर रहे हैं। आप हमेशा राष्ट्रीय समस्याओं को तिरछे एंगल से ही देखते हो। इनकी आंख में तिरछापन था।

आप कुछ नहीं समझते। हम समस्याओं के मूल तक जाकर चाणक्य की तरह उन्हें सिरे से उखाड़ फेंकते हैं। प्रवक्ता पुश्तैनी किसान थे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं भी तो हैं। इनका लड़का बेरोजगार है। हम ऋषि विचारधारा के पोषक हैं। हमारी प्राथमिकता धर्म, अर्थ और काम यानी रोजगार है। अभी धर्म के काम निबटा लें, फिर बाकी भी देख लेंगे। आप दुख नहीं, धर्म बांट रहे हो। हिंसा बांट रहे हो। देश बांट रहे हो। नहीं। हम ममताबांट रहे। आप अपना चश्मा साफ करें। आप भारत की सॉवरनिटी को कमजोर कर रहे हो।

आपका सीएबी केवल पीएबी यानी पाक-अफगान-बांग्ला क्यों है? और भी तो देश हैं? तभी उन्होंने इशारा किया कि आपकी सीआइबी जांच अभी प्रोसेस में है। प्रश्नकर्ता वॉकआउट कर चुके थे। उन्हें डॉक्टर ने शाम को घूमने की सलाह दी है।

ट्वीट-ट्वीट

कैबिनेट ने जैसे ही एनपीआर के लिए बजट को मंजूरी दी, उसके खिलाफ भी अभियान शुरू हो गया। लगता है अब जल्दी ही काका, छी-छी, एनआरसी, छी-छी की सूची में एनपीआर, छी-छी भी जोड़ लिया जाएगा। सवाल है क्या जनगणना का भी विरोध होगा और लोग खुद को गिनाने से इन्कार कर देंगे? अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

सीएए विरोधी प्रदर्शन में पीड़ितों से मुलाकात के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मेरठ जाने से रोक दिया गया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। भारत को विपक्षी दलों पर ऐसे अंकुश की नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों को सुकून पहुंचाने की जरूरत है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह@capt_amarinder

शिवसेना नहीं सुधरेगी। मुंबई के हीरामणि तिवारी ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर पोस्ट लिखा कि जामिया और जलियांवाला बाग की तुलना ठीक नहीं है। शिवसैनिकों ने तिवारी की पिटाई की और उनका सिर मुंडवा दिया।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

मध्यांतर

सियासत को आदत है यू-टर्न लेने की

मनीष तिवारी
manishtiwari@nda.jagran.com

नागरिकता संशोधन बिल (सीएए) की हाल की संक्षिप्त कहानी यह है कि इससे संबंधित संशोधन विधेयक संसद सदस्यों की एक साझा प्रवर समिति के लंबे विचार-विमर्श के बाद इस साल पेश किया गया था। बहुमत से इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और दोनों सदनों के पटल पर इसे रखा गया, लेकिन तभी लोकसभा चुनाव आ गए और इसका नतीजा यह हुआ कि इस पर बहस टल गई। आखिरकार दिसंबर में इसे फिर से पेश किया गया और यह दोनों सदनों से पारित हुआ। बदले कानून पर बवाल जारी है, अलग-अलग याचिकाएं अदालतों में हैं, पक्ष-विपक्ष में तलवारें खिंची हैं, तोड़-फोड़ के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है, उत्पातियों की धरपकड़ की जा रही है, अलग-अलग कनेक्शन निकल रहे हैं। इसी बीच इस प्रसंग की पड़ताल जरूरी है और वह भी पाला बदलने वाली सियासत के एक नए एपिसोड के साथ।

सवाल यह है कि यह बिल क्यों जरूरी है। इससे किसे लाभ हो रहा है और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इससे नुकसान में कौन है? तीसरे सवाल का जवाब है कि देश का कोई भी नागरिक नुकसान में नहीं है। किसी के अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पिछले दस दिनों में इसे स्पष्ट कर चुके हैं। बिल क्यों जरूरी है, इस सवाल के जवाब के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सरीखे इस्लामिक देशों के चरित्र को समझना होगा। 1947 के बाद से इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हुई बर्बरता के किस्से इतिहास में दर्ज हैं। जिस सेक्युलरिज्म का अपने देश में नारा बुलंद किया जाता है उसका एक अंश भी इन देशों में नहीं है। नतीजा यह है कि इन तीनों देशों में गैर-मुस्लिम देशों की आबादी तेजी से घटती जा रही है। शासन द्वारा समर्थित-संरक्षित और पोषित बर्बरता से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि जबरन धर्मांतरण की कोशिशों के आगे सिर झुका दिया जाए। कोई उत्पीड़ित अल्पसंख्यक बड़ी कठिनाई से इन देशों से निकल पाता है, ताकि उसे भारत में शरण मिल सके। ऐसे अल्पसंख्यकों में हिंदू भी शामिल हैं, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी भी।

भारत के पड़ोसी देशों में दमन और उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों की दशा-दिशा पर राजनीतिक दल चिंता तो जता रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनकी भलाई के लिए शायद ही कभी कुछ ठोस किया हो। दरअसल जरूरत घुसपैठियों और शरणार्थियों में फर्क करने की थी, लेकिन इस वर्गीकरण से कथित सेक्युलर दलों ने हमेशा परहेज किया। नागरिकता संशोधन कानून पर सबसे अधिक चौंकाने वाला रवैया कांग्रेस का है। आज इस कानून के खिलाफ कभी धरना दे रही, कभी जामिया के उत्पाती छात्रों के अधिकारों की वकालत कर रही तो कभी कानून को संविधान और सेक्युलरिज्म के खिलाफ बता रही कांग्रेस इस तथ्य पर हरसंभव तरीके से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है कि 2003 में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनमोहन सिंह ने सीएए जैसे कानून की वकालत की थी। पिछले दिनों भाजपा ने जब मनमोहन सिंह का वही वीडियो जारी किया तो कांग्रेस को जवाब देते नहीं बना। तब मनमोहन सिंह ने सदन के भीतर कहा था-बांग्लादेश सरीखे देशों में अल्पसंख्यकों ने दमन-उत्पीड़न झेला है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर परिस्थितियां इन लोगों को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर करें तो हमारा दृष्टिकोण उन्हें देश में नागरिकता देने का होना चाहिए। मनमोहन सिंह अकेले कांग्रेस नेता नहीं हैं जिन्होंने नागरिकता कानून जैसी व्यवस्था की मांग की थी। 2014 में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी लगभग ऐसे ही शब्दों के साथ सीएए की मांग की थी।

सवाल यह है कि अब कांग्रेस को सीएए पर आपत्ति क्या है? वामपंथी दल अथवा कथित मानवाधिकारवादी संगठन अगर सीएए का विरोध कर रहे हैं तो यह समझा जा सकता है कि उन्हें भाजपा, आरएसएस अथवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी कदम कभी रास नहीं आता, लेकिन एक राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस को तो जमीनी हकीकत का अहसास होना चाहिए। आखिर कांग्रेस से ज्यादा किस अन्य दल को विभाजन की परिस्थितियों की जानकारी होगी। बांग्लादेश का गठन कैसे और क्यों हुआ था, यह कांग्रेस सबसे ज्यादा जानती है। यह कांग्रेस की कार्यसमिति ही थी जिसने 25 नवंबर, 1947 को पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जताई थी। तब कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि उन सभी गैर मुस्लिमों को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए जो पाकिस्तान से भारत आए हैं अथवा अपना जीवन और सम्मान बचाने के लिए आने वाले हैं।

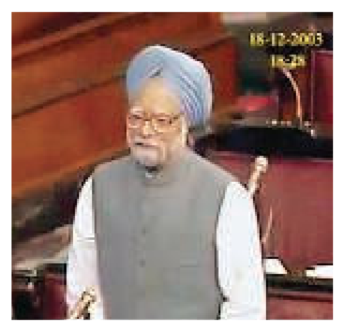

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

अच्छा होगा कि अगर आज सीएए के विरोध पर आमादा कांग्रेस उस प्रस्ताव को फिर से निकाल कर पढ़े। भाजपा का विरोध करना एक बात है, एक विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस को इसका पूरा अधिकार है कि वह सरकार की आलोचना करे और अपनी वापसी की जमीन की तलाश में जुटे, लेकिन इस क्रम में उसे एकतरफा सोच के जाल में फंसने से बचना होगा। उससे अपेक्षा यही है कि नीति के मामले पर वह नीर-क्षीर ढंग से बर्ताव करे। अगर कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी नजर आएगी जो विरोध के नाम पर बसें-ट्रेनें फूंक रहे हैं, पुलिस चौकियों पर हमले कर रहे हैं तो उसकी राह और मुश्किल ही होगी।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या झारखंड में मिली जीत से विपक्ष का मनोबल बढ़ेगा?

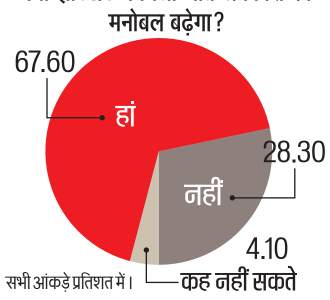

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन से सैन्य बलों में समन्वय बेहतर होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

थाली के बैंगन गिरे गिरे बड़े सरकार,
ठोकर लगने की जिन्हें थी थोड़ी दरकार।
थी थोड़ी दरकार पड़ेगा जरा संभलना,
वरना फिर से हाथ बैठ दिल्ली में मलना।
सबक सीखिए बंधु मिलेगी ना खुशहाली,
यदि औरों को बांट दिए अपनों की थाली।
– ओमप्रकाश तिवारी

जल प्रबंधन

कृषि संकट से निपटने का कारगर तरीका

प्रो. मान सिंह
वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

किसानों को सालभर सिंचाई के लिए निरंतर जल मुहैया कराकर उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है, इससे कृषि उपज कम से कम दो गुनी बढ़ जाएगी, साथ ही फसलों की संख्या में भी बढ़ोतरी संभव हो सकेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बार इस बात को रेखांकित किया है कि खेत और शरीर एक जैसे हैं। जैसे शरीर की कमियों की जांच के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं का सहारा लिया जाता है, वैसे ही खेतों की मिट्टी की जांच के लिए भी समुचित संख्या में प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक खेत का हेल्थ कार्ड बन सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह धारणा गलत है कि खेत में लबालब पानी होगा तभी अच्छी खेती हो सकेगी। सिंचाई के बारे में एक सच यह है कि गुणवत्ता की दृष्टि से पानी कितना भी अच्छा क्यों न हो यह अपने साथ कम या अधिक मात्रा में नमक यानी साल्ट अवश्य लाता है। विभिन्न क्षेत्रों में दशकों से सिंचाई कार्य हो रहे हैं ऐसे में उन खेतों में नमक की अधिकता की समस्या अवश्य होगी। इसके फलस्वरूप उस खेत की मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आई होगी। जाहिर है यदि उसे स्वस्थ बनाए रखना है तो उसकी मिट्टी से गैरजरूरी नमक बाहर निकालने होंगे। इसके लिए जल एवं उप सतही जलनिकासी प्रौद्योगिकी कारगर साबित हो सकती है।

मिट्टी में नमक की समस्या कैसे पनपती है? इसे तटीय क्षेत्रों का भी एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। पूर्वी समुद्र तट के राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृषि उत्पादकता कम होने का एक प्रमुख कारण वहां खारे पानी की अधिकता, फलस्वरूप भूमि में नमक की मात्रा बढ़ना तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था का न होना है। गत दिनों डॉ. पीके मिश्रा ने अपने लेख 'आपदाओं का असर घटाने की पहल' में विश्व बैंक सहायता प्राप्त चक्रवात जोखिम कार्यक्रम का जिक्र किया था। प्राकृतिक आपदाओं से सतह पर दिखाई देने वाले नुकसान को सभी देख लेते हैं, परंतु इसका वहां की कृषि योग्य भूमि के अंदरूनी स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कोई देख नहीं पाता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से आगामी वर्षों में आपदाओं में बढ़ोतरी की संभावना है।

दरअसल अच्छी उपज के लिए मिट्टी में 4.5 डेसीसीमेंस प्रति मीटर नमक का होना ठीक-ठाक माना जाता है। पूर्वी तट पर जब हर दूसरे या तीसरे वर्ष छोटे, मझोले या बड़े चक्रवात या सुनामी के चलते समुद्र का पानी कृषि भूमि पर गिरता रहता है। ऐसे में भूमि में नमक की कितनी अधिकता होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी के पानी में नमक की मात्रा 48 से 50 डेसीसीमेंस प्रति मीटर होती है जो भूमि में वांछित मात्रा से 10-12 गुना अधिक है। पूर्व में सुनामी के बाद तमिलनाडु के दो जिले कडलोर और नागापट्टिनम का उदाहरण सभी के सामने है। वहां सुनामी से एक ही रात में पूरी भूमि ऊसर में तब्दील हो गई और उस पर कोई फसल लेना असंभव हो गया।

प्रतीकात्मक

बात स्पष्ट है कि ज्यादा नमक फसल की जड़ों को पनपने नहीं देता है। इस समस्या का निदान सिर्फ उप सतही जल निकासी प्रौद्योगिकी है। यह प्रौद्योगिकी सतह से 80 से 100 सेंटीमीटर नीचे की मोटी परत में स्थित नमक को बाहर कर देती है। इसके लिए पूर्वी समुद्री तट के प्रभावित क्षेत्रों के खेतों में उप सतही जलनिकासी प्रौद्योगिकी स्थापित की जानी चाहिए। इससे वहां की मिट्टी का स्वास्थ्य सदैव बना रहेगा, कृषि उपज कम से कम दो गुनी बढ़ जाएगी। वहां दो से बढ़कर तीन फसल की संभावना भी बढ़ जाएगी।

यह प्रौद्योगिकी शहरों में भी जलापूर्ति और जल निकासी समस्या का समाधान कर सकती है। इससे जल संकट का समाधान हो सकता है। उप सतही जलनिकासी प्रौद्योगिकी आर्टरी-वेन मॉडल पर आधारित है। इसे संक्षेप में ए-वी मॉडल कहा जाता है। मानव शरीर में विद्यमान धमनियों एवं नसों के मॉडल पर आधारित है। आर्टरी जलापूर्ति की लाइन है और वेन जल निकासी की लाइन है। यह मॉडल सड़कों, रेलवे लाइनों, विद्युतीकरण और ढेर सारे मोबाइल नेटवर्कों के संजाल से प्रेरित है। इसकी सार्थकता को देश में बहने वाली सभी नदियों को आपस में जोड़कर हासिल किया जा सकता है। नदियों को आपस में जोड़कर 'हर खेत को जल' तथा 'हर घर को नल से जल' का समाधान भी पाया जा सकता है।

हालांकि इसके लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा खड़ा करना होगा। सभी खेत और सभी घर के लिए जलापूर्ति एवं जलनिकासी संजाल जैसी आधारभूत ढांचा के विकास के लिए सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। यह समय की मांग है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में विद्यमान प्रत्येक कोशिका को नपा-तुला पोषक तत्वों से मिश्रित रक्त मिलता है, उसी तर्ज पर सभी लघु, मझोले एवं बड़े किसानों को निरंतर पूरे वर्ष सिंचाई के लिए जल मुहैया हो जाए तो इसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि किसान पूरे साल अपने खेतों में कोई न कोई फसल उगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

फलस्वरूप हम भविष्य में कृषि विकास की दर बढ़ाकर गरीब किसानों को खुशहाली प्रदान कर सकते हैं और भारत को सशक्त राष्ट्र की सूची में शामिल कर सकते हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति से देश में अगले 25 से 30 वर्षों में इसका ढांचा बनाया जा सकता है। इस तकनीकी को जमीन पर उतारने में देरी भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक साबित हो रही है।

19 जनवरी से भारतीय रेलवे की दूसरी निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। देश की पहली निजी ट्रेन (तेजस एक्सप्रेस) दिल्ली से लखनऊ के बीच चल रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 25 दिसंबर 2019

झारखंड

सामंजस्य से खुलेगी विकास की राह

प्राकृतिक संपदा से भरपूर है अपना झारखंड। वनों के अनुपात में यह प्रदेश देश का अग्रणी राज्य माना जाता है। यह प्रदेश वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी मशहूर है। झारखंड विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। द्रविड़, आर्य एवं आस्ट्रो-एशियाई तत्वों के सम्मिश्रण का इससे अच्छा कोई क्षेत्र भारत में शायद ही दिखता है। इसके बावजूद यह प्रदेश गरीबी से जूझ रहा है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के वादे के बल पर महागठबंधन ने जनादेश तो पा लिया, अब उसके सामने प्रदेश को विकास की राह पर सतत गति से ले जाने की बड़ी चुनौती है। जनता भी नई सरकार से काफी उम्मीदें संजोए है। महागठबंधन ने पूरे चुनाव में हेमंत सोरेन को ही बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हेमंत और गठबंधन को शानदार जीत के लिए बधाई दी है। हेमंत भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। वे जानते हैं कि राज्य को विकास की राह पर शिद्दत के साथ ले जाना है तो केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने जीत की खुशी के बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी को न केवल शुभकामना के लिए धन्यवाद दिया, बल्कि यह गुजारिश भी कर दी कि झारखंड की गरीब जनता के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने जता दिया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के लोगों की जिंदगी में समृद्धि के दीपक जलाएंगे।

राज्य को यदि विकास की राह पर शिद्दत के साथ ले जाना है, तो केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण साबित होगी

दरअसल झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं, जहां आज भी शुद्ध पेयजल मिलना नसीब नहीं होता। संताल के सुदूर पहाड़ों पर तो लोग झरनों का पानी पीने को विवश हैं। सड़कों का हाल तो और खराब है। कई गांवों तक जाने के लिए सड़क नहीं, सिर्फ पगडंडी का ही सहारा है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल और भी खराब है। प्रदेश में चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों की बड़ी कमी है। संताल के कई इलाकों में लोगों को छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी बंगाल तक की दौड़ लगानी पड़ती है। राज्य में कुल 80 लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है। झारखंड में गरीबी और कुपोषण भी एक बड़ी समस्या बन कर उभरी है। तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य के कई जिले आज भी कुपोषण की चपेट में हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे गुमला और पश्चिम सिंहभूम में हैं। जाहिर है विकास की कसौटी पर अब तक सूबे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इसके चलते साथ ही अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों से झारखंड पिछड़ गया है।

इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा जहां विकास, केंद्रीय योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता के बीच गई थी, वहीं महागठबंधन ने ऐसी ही स्थानीय समस्याओं को उठाकर स्वयं को जनता से सीधे जोड़ पाने में सफलता पाई। अब बड़ी चुनौती यह है कि कैसे इन समस्याओं का निदान कर राज्य को विकास के पथ पर तेजी से ले जाया जाए। जनता उम्मीदें संजोए है और उसे नई सुबह का इंतजार है।

जम्मू-कश्मीर

ब्लड बैंक से मिलेगी राहत

जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों में स्थित अस्पतालों में ब्लड बैंक स्थापित करने का फैसला सराहनीय है। निःसंदेह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के फैसले से मरीजों को भविष्य में राहत मिलेगी और उन्हें रक्त के लिए दरबदर नहीं होना पड़ेगा। इस समय जम्मू संभाग में मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल, गांधीनगर अस्पताल, सरवाल अस्पताल के अलावा ऊधमपुर, राजौरी, कठुआ और पुंछ जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक हैं। नए बने जिलों में अभी भी ब्लड बैंक स्थापित नहीं हैं। इसी तरह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी ब्लड स्टोरेज यूनिट ही है।

जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र अधिक होने के कारण आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। इससे हर समय अस्पतालों में मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ती है। अभी तक सभी जिला अस्पतालों में भी ब्लड बैंक न होने के कारण अधिकांश मरीज राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं सहायक अस्पतालों में स्थित ब्लड बैंक पर निर्भर हैं। कई बार मरीजों को तत्काल रक्त की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के कई मामले हुए हैं जहां पर अधिक रक्त बहने के कारण मरीज की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। अगर निकट के अस्पताल में ही यह सुविधा हो तो इससे न सिर्फ मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी।

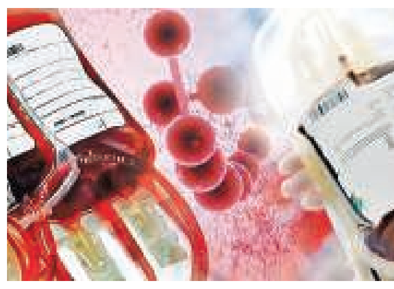

कई जगहों पर युवा रक्तदान करना चाहते हैं, लेकिन निकट में सुविधा न होने और जागरूकता के अभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यह अच्छी बात है कि अब आतंकवाद प्रभावित शोपियां तथा पहाड़ी क्षेत्र रियासी एवं अन्य अस्पतालों में ब्लड बैंक स्थापित हो जाएंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को चाहिए कि इन अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा जल्द उपलब्ध कराए, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। साथ ही विभाग को चाहिए कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करे।

देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड बैंक नहीं होना एक राष्ट्रीय समस्या है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से पता चलता है कि तेलंगाना के 13 जिलों में ब्लड बैंक हैं ही नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 जिले, मणिपुर और झारखंड में 9-9 जिले, यूपी के चार जिले ऐसे हैं, जहां ब्लड बैंक का कोई अता-पता ही नहीं है। इसके अलावा नगालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक के प्रत्येक तीन जिलों में ब्लड बैंक की कोई सुविधा ही नहीं है। सिक्किम के दो जिलों और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक-एक जिले में ब्लड बैंक उपलब्ध नहीं हैं। वहीं बिहार, असम और मेघालय में से प्रत्येक राज्य के पांच जिलों में ब्लड बैंक नहीं हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुसार किसी भी देश में किसी भी स्थिति में उसकी जनसंख्या का कम से कम एक प्रतिशत रक्त आरक्षित होना ही चाहिए। उक्त मानक के अनुसार हमारे देश में कम से कम एक करोड़ 30 लाख यूनिट रक्त का हर समय आरक्षित भंडार होना चाहिए, लेकिन पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास प्रतिवर्ष रक्त की औसतन 90 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाती है। प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 प्रतिशत रक्त की कमी रह जाती है। चिंताजनक यह भी है कि भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिशत आबादी भी रक्तदान नहीं करती है। जबकि थाईलैंड में 95 फीसद, इंडोनेशिया में 77 फीसद और म्यांमार में 60 फीसद हिस्सा रक्तदान से पूरा होता है। भारत में मात्र 46 लाख लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। इनमें महिलाएं मात्र छह से 10 प्रतिशत हैं। जाहिर है देश में पर्याप्त मात्रा में ब्लड बैंक स्थापित करने की जरूरत है।

बिहार

सड़कों को भी लंबी 'उम्र' चाहिए

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में ही यह संकल्प लिया था कि सूबे के किसी भी हिस्से से छह घंटे में पटना पहुंचा जा सके, ऐसी व्यवस्था वे बनाएंगे। निश्चय ही इस दिशा में बेहतर काम हुआ। अभी-अभी भारतीय रोड कांग्रेस का 80वां अधिवेशन बिहार में संपन्न हुआ। सड़कों के निर्माण को लेकर नए संकल्प गढ़े गए। लेकिन इसी क्रम में बिहार की सड़कों के रख-रखाव पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान भी आकृष्ट कराया गया। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन के मंच से ही राज्य से गुजरने वाले करीब पांच हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव को और बेहतर बनाने की बात उठाई। यह वाजिब बात है। बाढ़ प्रवण बिहार में सड़कों को लंबी उम्र देनी ही होगी। केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) की राशि में राज्यों की हिस्सेदारी की भी मांग की गई। पहले यह राशि सड़क महकमे को आती थी।

पेट्रोल एवं डीजल सेस से मिलने वाली रकम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़कों का निर्माण करता था और राज्यों को भी वह राशि मिलती थी। लेकिन अब इसे वित्त मंत्रालय को दिया जाने लगा है। बिहार सरकार की यह मांग जायज है। बिहार जैसे राज्य जहां आर्थिकी के आंतरिक स्रोत बहुत ज्यादा नहीं हैं, वहां के लिए ऐसी राशि का बहुत महत्व है। बिहार की सड़कों की दशा पर हाल में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। पटना-गया-डोभी जैसी सड़क का बार-बार जिक्र होता है। कुछ सड़कें ऐसी हैं, जिन्हें एजेंसियां अधूरी छोड़कर भाग गई हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर एक दिक्कत है कि कई भागों में रख-रखाव का काम कुछ वर्षों से अधूरा पड़ा है। गुजरने वाले लगातार व्यवस्था को कोसते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सड़कों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सड़क, पानी और बिजली का ही नंबर आता है। अच्छी सड़कें विकास की निशानी होती हैं। बेहतर सड़कें समृद्धि और विकास का मूल आधार होती हैं, क्योंकि इससे आवाजाही आसान होती है।

राज्य सरकार और मंत्रालय, दोनों को मिलकर सड़क के लिए कोई 'रास्ता' निकालना होगा। पहली प्राथमिकता राजमार्ग की मरम्मत का है। लेकिन इसके साथ-साथ वैकल्पिक सड़क के विकल्प भी ढूंढ़ने ही होंगे

बहरहाल अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ताजा प्रकरण में अपने प्रावधान की दुहाई दे रहा है कि जिन घनी आबादी और बाजार से राजमार्ग गुजर रहे हैं, वहां बाईपास बनें। प्राधिकरण ऐसे हिस्से में अपने द्वारा निर्मित सड़क की एक साल से ज्यादा मरम्मत नहीं करेगा। वैकल्पिक बाईपास के लिए जमीन का हर जगह संकट है। मंत्रालय को कोई रास्ता निकालना चाहिए। प्रावधान बदलकर भी बिहार की सड़कों की चिंता करनी चाहिए। राज्य सरकार और मंत्रालय, दोनों को मिलकर सड़क के लिए कोई 'रास्ता' निकालना होगा। पहली प्राथमिकता राजमार्ग की मरम्मत का है। लेकिन इसके साथ-साथ वैकल्पिक सड़क के विकल्प भी ढूंढ़ने ही होंगे।

हरियाणा

इस बारे में भी सोचिए

उत्तर भारत सहित हरियाणा सर्दी से सिहर रहा है। प्रदेश भर में रैनबसेरों की व्यवस्था तो है, लेकिन वहां सर्दी से बचने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। इसलिए वहां जाने से लोग परहेज करते हैं। जो जाते हैं, वे सर्दी से ठिठुरते रहते हैं। दरअसल लाखों रुपये की लागत से प्रदेश में जगह-जगह बने रैन बसेरे सुविधाओं के अभाव में राहगीरों का सहारा नहीं बन पा रहे हैं। रैन बसेरों में सुविधाओं का अभाव होने के कारण राहगीर या मुसाफिर खुले आसमान के नीचे या रेलवे स्टेशन सोने को मजबूर हैं। रेन बसेरों में पर्याप्त कंबल, बिस्तर, खाने-पीने की सुविधा, साइन बोर्ड का नहीं होना एवं अंदर जाने-आने का रास्ता नहीं होने के कारण खाली पड़ा रहता है। कई जगहों पर तो मुसाफिरों के लिए डिस्पेंसरी की सुविधा भी नहीं है।

वैसे तो प्रदेश सरकार को हर महीने रैनबसेरों की पड़ताल करनी चाहिए कि वहां व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है या नहीं। लेकिन सर्दी शुरू होने से पहले तो यह अति आवश्यक है। इसके लिए किसी एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जिला उपायुक्त इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उन्हें यह देखना चाहिए कि संवेदनशीलता और विवेकधर्मिता की दृष्टि से किस अधिकारी को रैनबसेरों की स्थिति को दुरुस्त करने का दायित्व दिया जाए। यह अधिकारियों का प्रशासनिक दायित्व तो है ही, नैतिक दायित्व भी है। इसके लिए वे सरकार से पर्याप्त फंड की व्यवस्था तो कराए हीं, स्वयं भी समाज के अग्रणी लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से सर्दी से निर्धनों को बचाने का अनुरोध करें। यदि वे ऐसा करने के लिए आगे आएंगे तो रैनबसेरों की स्थिति बदलेगी और फुटपाथ पर सोने वाले निर्धन भी राहत महसूस करेंगे। इसके साथ-साथ बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी अस्पतालों में कंबल रखवाए जा सकते हैं। लोग इस्तेमाल करें और फिर वापस कर दें। इसके अतिरिक्त शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों और गांवों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी गर्म कपड़े सामान्य जन की सहायता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। विधायक और सरपंच-पंच शासकीय सहायता से उन्हें कंबल की व्यवस्था कराने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सबकुछ सरकार के और जनप्रतिनिधियों के भरोसे ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक नागरिक के रूप में सबको इस दिशा में आगे आना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी थोड़ी सी मदद किसी गरीब के लिए कितने काम की हो सकती है। यह भी रेखांकित करने वाली बात है कि इससे आपको भी सुख मिलेगा। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, उसे तो खुशी मिलती है, लेकिन आपको सुख मिलता है। खुशी मानसिक होती है, सुख आत्मिक होता है।

डाटागीरी

असम की नदियों में 962 और उप्र में 1,275 हैं गंगा डॉल्फिन

डॉल्फिन की खास प्रजाति गंगा डॉल्फिन विलुप्त होने के खतरे से जूझ रही है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। मुख्यत: मीठे पानी में रहने वाले इस जीव को 2009 में केंद्र सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था।

कई कारणों से डॉल्फिन की इस प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। फाइल

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

नदियों में बढ़ते प्रदूषण, बांधों के निर्माण व शिकार के कारण मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन की प्रजाति गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पांच अक्टूबर, 2009 को केंद्र सरकार ने इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बीते दिनों संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री इनकी संख्या के बारे में जानकारी दी। अंतिम गणना में उत्तर प्रदेश व असम की नदियों में इनकी संख्या क्रमशः 1,275 व 962 पाई गई थी।

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश में गंगा डॉल्फिन की आबादी और निवास क्षेत्रों का आकलन किया, जिसके जवाब में सुप्रियो ने कहा था कि इस तरह के आकलन राज्य वन विभागों द्वारा किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रालय में इस तरह का डाटा एकत्र नहीं किया जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और असम की राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी को पटल पर रखा। इसमें बताया गया कि गंगा डॉल्फिन की गणना असम सरकार ने 2018 में जनवरी से मार्च माह के बीच की थी। वहीं, उत्तर प्रदेश में 2015 में इनकी संख्या 1,272 थी, जबकि 2012 में इनकी गणना 671 की गई थी।

असम में गंगा डॉल्फिन की गणना तीन नदियों में की गई थी। ब्रह्मपुत्र में इनकी संख्या 877 पाई गई थी। वहीं, राज्य में इनकी कुल संख्या 962 थी। इसके संरक्षण के लिए असम सरकार ने भी इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया है। राज्य में इनकी आबादी को कम होने से बचाने के लिए नदियों से सिल्टिंग और रेत उठाने से रोक दी गई है।

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गंगा डॉल्फिन को भारत में एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के मुताबिक, गंगा डॉल्फिन के लिए मुख्य खतरा बांधों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण है। मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन के संरक्षण की कार्य योजना 2010-2020 के बारे में बताया कि इस जीव के खतरों की पहचान की गई है, जो सिंचाई नहरों का निर्माण, शिकार और नदियों का यातायात है।

2018 में असम की नदियों में गंगा डॉल्फिन

ब्रह्मपुत्र नदी	877
सुबनसिरी नदी	48
कुलसी नदी	37
कुल	962

गंगा डॉल्फिन की खासियत

गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है, जिसके सूंघने की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। इसकी प्रजाति पर खतरे का एक बड़ा कारण इसका शिकार किया जाना है। इसका शिकार मुख्यत: तेल के लिए किया जाता है, जिसे अन्य मछलियों को पकड़ने के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिहार व उत्तर प्रदेश में इसे 'सोंस', जबकि असामी भाषा में 'शिहू' के नाम से जाना जाता है।

बाहर ही नहीं, घर में भी बच्चों की जान ले रहा प्रदूषण

सीएसई की हाउस पत्रिका 'डाउन टू अर्थ' ने प्रकाशित की ग्लोबल बर्डन डिजीज स्टडी रिपोर्ट, बढ़ रही है समस्या

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

वायु प्रदूषण का काला साया अब बच्चों को भी तेजी से गिरफ्त में ले रहा है। 14 वर्ष तक के बच्चे फेफडों के संक्रमण से न केवल अल्पायु में ही विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बल्कि काल का ग्रास भी बन रहे हैं। चिंताजनक यह है कि प्रदूषण की मार से बच्चे घर के बाहर ही नहीं, भीतर भी सुरक्षित नहीं हैं। ग्लोबल बर्डन डिजीज स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रदूषक तत्व पीएम 2.5 (पार्टीकुलेट मैटर) के महीन कण श्वांस के जरिये शरीर में प्रवेश कर सीधे निचले फेफड़ों पर असर डालते हैं। यह प्रदूषक तत्व बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआइ) और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक एंड इवोल्यूशन (आइएमएमई) के सहयोग से तैयार रिपोर्ट में 2017 तक के आंकड़े दिए गए हैं। इसी के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने भी अपनी हाउस पत्रिका डाउन टू अर्थ में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक मनुष्य के सिर के एक बाल का व्यास 50 से 70 माइक्रोन होता है, जबकि पीएम 2.5 के कण इससे भी कहीं महीन होते हैं। 24 घंटों के आधार पर पीएम 2.5 का सामान्य स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है, जबकि इसका स्तर सालभर के ज्यादातर दिनों में इससे कहीं ज्यादा रहता है। इसका मुख्य स्रोत वाहनों का धुआं, जैविक घटक और धातु हैं। जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक शोध ने भी हवा में मौजूद महीन पीएम 2.5 को वैश्विक रोगों के लिए जिम्मेदार माना है।

2017 में वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों को लेकर जारी द लैंसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम 2.5 के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष प्रदूषित देशों की सूची में नेपाल, नाइजीरिया, कतर के बाद चौथे स्थान पर है। 2017 में भारत का सालाना औसत पीएम 2.5 स्तर 89.8 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रिकॉर्ड किया गया, जो अपने सालाना सामान्य स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा है। पीएम 2.5 के सालाना स्तर और विभिन्न राज्यों में वायु प्रदूषण जनित निचले फेफेड़ों के संक्रमण से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत से जुड़े आंकड़ों को इसमें देखा जा सकता है।

14 वर्ष तक के बच्चों पर पड़ रहा बुरा असर। प्रतीकात्मक

भारत में जहरीली हवा के कारण पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। यह बेहद चिंताजनक है। घर के भीतर और बाहर दोनों ही जगह बच्चे ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है। हालांकि, सुधार के लिए प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन वह अभी ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं।
– अनुमिता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, सीएसई

उत्तर प्रदेश में यह स्थिति कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहां घर के भीतर ठोस ईंधन के धुएं से एक लाख बच्चों की आबादी में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 39.62 फीसद है। बिहार में यह आंकड़ा 46.63 है। इसी तरह दिल्ली में 0.19, पंजाब में 9.41 और हरियाणा में 16.3 बच्चे घर के भीतर के प्रदूषण से दम तोड़ रहे हैं।

ग्लोबल बर्डन डिजीज रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का जीवन सर्वाधिक जोखिम में है। वर्ष 2017 में इसी आयु वर्ग में देश भर में 10.35 लाख बच्चों की मौत हुई हैं। इनमें से 1.85 लाख मौतें निचले फेफड़ों के संक्रमण से ही हुई हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि निचले फेफड़ों के संक्रमण की सबसे बड़ी वजह वायु प्रदूषण ही होती है।

किस राज्य में किस आयु वर्ग के कितने बच्चे हो रहे प्रदूषण के शिकार

राज्य	0 से 5 साल के बच्चे	5 से 14 साल के बच्चे	भीतरी प्रदूषण से हुई मौतें	बाहरी प्रदूषण से हुई मौतें
दिल्ली	41.81 फीसद	1.23	0.19	41.62
जम्मू कश्मीर	59.9	1.43	25.17	34.73
हरियाणा	56.44	0.99	16.3	40.44
हिमाचल प्रदेश	36.35	0.81	18.7	17.65
पंजाब	39.55	0.63	9.41	30.14
उत्तराखंड	46.28	1.07	14.47	29.82
उत्तर प्रदेश	111.58	2.59	39.22	72.66
राजस्थान	126.04	2.17	67.47	58.56
बिहार	105.95	3.46	46.63	59.32
मध्य प्रदेश	85.51	2.42	49.9	35.6

नोट: आंकड़े फीसद में। प्रति एक लाख की आबादी पर।

जनगणना और एनपीआर के बारे में वह सब जो आपके लिए जानना जरूरी है

नई दिल्ली, प्रेट्र : मोदी सरकार अगले साल और दो बड़े काम करने जा रही है। देश भर में जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का विवरण होगा। जनगणना और एनपीआर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आइए समझते हैं दोनों की विशेषताएं, मकसद और अंतर क्या है और किस कानून के तहत ये प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं।

एनपीआर देश के सभी सामान्य निवासियों का रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमों, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय (गांव/मोहल्ला/वार्ड/कस्बा), तहसील (उप-जिला), जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है।

कौन है सामान्य निवासी?

कोई भी निवासी जो छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है या छह महीने या उससे अधिक समय तक वहां रहने का इरादा रखता है, वह सामान्य निवासी है। कानून के मुताबिक हर सामान्य निवासी को एनपीआर में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होता है और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान भी है।

कब शुरू होगी एनपीआर की प्रक्रिया ?

असम के अलावा पूरे देश में जनगणना के लिए घर-घर गणना के साथ एक अप्रैल 2020 से एनपीआर की प्रक्रिया शुरू होगी। असम को इससे इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि वहां पहले से ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू है। 30 सितंबर 2020 तक चलने वाली एनपीआर की प्रक्रिया में स्थानीय रजिस्ट्रार के दायरे में रहने वाले सभी निवासियों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।

एनपीआर का क्या है मकसद ?

एनपीआर का मकसद देश में रहने वाले सभी सामान्य लोगों के बारे में पहचान के साथ पूरी जानकारी जुटाना है। इस डाटाबेस में जनसांख्यिकीय विवरण लिए जाएंगे।

- **देश के सामान्य निवासियों का दस्तावेज है एनपीआर**
- **जनगणना में होता है देश के लोगों का लेखा-जोखा और प्रगति की जानकारी**

एनपीआर में क्या होगा विवरण?

एनपीआर में सामान्य निवासी का नाम, घर के स्वामी के साथ उसका संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम (विवाहित होने पर), लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता (घोषित), स्थायी और अस्थायी पता, अस्थायी पता पर निवास की अवधि, पेशा और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी होगी।

क्या है जनगणना ?

जनगणना में भी देश के लोगों के बारे में विभिन्न जानकारियां एकत्र की जाती हैं। एक निश्चित अंतराल पर चलने वाली यह प्रक्रिया लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इकलौता सबसे वृहद स्रोत है। यह प्रक्रिया जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत पूरी की जाती है।

जनगणना में क्या जानकारी होती है?

जनगणना में देश की जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास और आवासीय सुविधाओं, शहरीकरण, जन्म और मृत्यु दर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, पलायन, दिव्यांगता इत्यादि के बारे में विस्तृत और सटीक जुटाई जाती है। इसके आधार पर ही सरकारी योजनाएं लागू की जाती हैं। इसी के आधार पर पिछले दस साल में देश की प्रगति का पता चलता है और आगामी सरकारी योजनाओं का खाका तैयार किया जाता है। जनगणना-2021 दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर-घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे। वहीं दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की काम नौ फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच पूरा होगा। संशोधन की प्रक्रिया एक मार्च से पांच मार्च, 2021 के बीच होगी। जनगणना का संदर्भ दिन एक मार्च, 2021 की मध्य रात्रि होगी। जिन राज्यों में बर्फबारी होती है, जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में जनगणना का संदर्भ दिन एक अक्टूबर, 2020 होगा।

पहली जनगणना कब हुई ?

जनगणना का इतिहास सौ साल से भी ज्यादा पुराना है। देश के अलग-अलग हिस्सों में पहली बार 1872 में जनगणना कराई गई थी। हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। 1949 के बाद से यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसमें व्यवस्थित रूप से देश के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृहमंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त की है।

50 फीट ऊंची और 17 हजार किलोग्राम वजन की कांसे की प्रतिमा स्थापित की जाएगी अहमदाबाद के वैष्णोदेवी सर्कल के पास तैयार हो रहे सरदार धाम में। इस प्रतिमा को विख्यात शिल्पकार पद्मभूषण राम सुथार ने तैयार किया है। तीन जनवरी को इसका अनावरण होगा।

महामना का अमृतसर से था गहरा लगाव

- जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में बनाई थी कमेटी
- नरसंहार में मारे गए लोगों की जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे थे अमृतसर
- 1300 लोगों के शहीद होने का जुटाया था आंकड़ा

जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अमृतसर पहुंचे पं. मदन मोहन मालवीय जी घटना के बारे में लोगों से बात करते हुए। सौजन्य : मालवीय मिशन वेबसाइट

नितिन धीमान, अमृतसर

जयंती पर विशेष

महामना मदन मोहन मालवीय जी की बुधवार को जयंती है। देश को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) जैसा विश्वस्तरीय संस्थान देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय का अमृतसर से गहरा लगाव रहा। 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर यूनिट ने मदन मोहन मालवीय कमेटी का गठन किया था। नरसंहार में मारे गए लोगों का आंकड़ा जुटाने के लिए मालवीय जी को अमृतसर भेजा गया। उन्होंने घर-घर जाकर बातचीत की। शहीद स्थली में हुए नरसंहार के बाद लोगों से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हासिल कर रिपोर्ट तैयार की। ब्रिटिश हुकूमत ने नरसंहार में जान गंवाने वालों की संख्या 379 बताई थी, जबकि अमृतसर में रह रहे इतिहासकार नरेश जौहर के मुताबिक महामना ने 1300 लोगों के शहीद होने का आंकड़ा जुटाया था।

महामना ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ श्री दुर्ग्याणा मंदिर, अमृतसर का नींव पत्थर भी रखा था। छह अक्टूबर, 1925 को वह अमृतसर पहुंचे थे और श्री दुर्ग्याणा मंदिर का सात अक्टूबर को नींव पत्थर रखा था। हवन यज्ञ में भी शामिल हुए थे। ऐसा माना जाता है कि श्री दुर्ग्याणा तीर्थ के सरोवर में पानी ठहरता नहीं था। जितना पानी भरा जाता वह सूख जाता। इस समस्या का निराकरण करने के लिए मालवीय जी ने यहां हवन यज्ञ करने को कहा था। उनकी सलाह के अनुसार सरोवर के बीच हवन यज्ञ करवाया गया। इसके बाद सरोवर का जल कभी सूखा नहीं। महामना ने श्री दुर्ग्याणा तीर्थ के निर्माण के लिए देश के कई भागों से चंदा भी एकत्रित किया। उल्लेखनीय है कि बीएचयू की स्थापना भी उन्होंने देश के कोने-कोने से चंदा इकट्ठा करके की थी।

1925 में अमृतसर सेवा समिति की स्थापना की : इतिहासकार नरेश जौहर बताते हैं कि मालवीय जी ने 1925 में चंदे से अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए पानी का प्रबंध किया था। उनकी इस प्रेरणा से अमृतसर में कई स्थानों पर छबीलें यानी प्याऊ लगाए गए। महामना ने अमृतसर में एक चेरीटेबल अस्पताल का नींव पत्थर रखा, जिसका नाम अमृतसर सेवा समिति रखा गया। यहां मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई। आजादी के बाद अमृतसर में लगातार सेवा समिति के अस्पताल खोले गए। आज 20 अस्पताल हैं, जहां मरीजों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों एवं वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा निःस्वार्थ सेवा प्रदान की जा रही है। नरेश जौहर कहते हैं कि महामना की जीवनी से आज जन-जन को परिचित करवाना सरकार का ही जिम्मा है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई कार्यक्रम नहीं करवाया जाता। महामना अमृतसर कई बार आए थे, लेकिन उनसे जुड़ी निशानियों का भी पंजाब सरकार संरक्षण नहीं कर पाई।

अमृतसर में है मालवीय रोड : 25 दिसंबर, 1861 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में जन्मे मालवीय जी के नाम पर अमृतसर में एक सड़क भी है। कंपनी बाग से सटी इस सड़क का नाम आजादी के बाद म्यूनिसिपल कमेटी ने मालवीय जी के नाम पर मदन मोहन मालवीय रोड रखा। मालवीय जी द्वारा गुरु नगरी में किए गए महान कार्यों को देखते हुए ही इस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया।

नए कश्मीर में मिलजुल कर बना रहे तरक्की की राह

जागरण विशेष ▶ श्रीनगर के उपायुक्त युवा आइएएस डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने चंद दिनों में कर दिखाए नामुमकिन काम

2008 में जम्मू से आइएएस बनने वाले पहले मुस्लिम युवा के कायल आम कश्मीरी ही नहीं, नौकरशाह भी

नवीन नवाज, श्रीनगर

श्रीनगर-बारामुला राजमार्ग के आड़े आ रहे पुराने गुरुद्वारे और झेलम पर पुल की राह में पड़ रही मस्जिद को लेकर दोनों समुदायों के लोगों ने अड़ियल रुख छोड़ दिया। यह दोनों प्रोजेक्ट सालों से अटके हुए थे। अब लोगों ने मिलजुलकर और सूझबूझ से तरक्की की राह खोल दी। श्रीनगर के उपायुक्त डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई, जिसकी तारीफ हो रही है।

नए कश्मीर में युवा आइएएस अफसर शाहिद इकबाल की प्रशासनिक कार्यकुशलता के न केवल प्रशासक बल्कि आम कश्मीरी भी कायल हैं। उन्होंने चंद दिनों में ऐसे नामुमकिन काम कर दिखाए, जो देश-दुनिया में मिसाल बन गए हैं। वह सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। दो दिन पहले ही श्रीनगर से आई इस खबर ने सुर्खियां बटोरीं कि स्थानीय लोग 40 वर्ष पुरानी उस मस्जिद को हटाने के लिए राजी हो गए, जो झेलम पर बन रहे पुल की राह में आ रही थी। मस्जिद के हटाने के फैसले के साथ ही श्रीनगर के कमरवारी और नूरबाग के बीच 166 मीटर लंबे दो-लेन वाले पुल का रास्ता साफ हो गया। यह प्रोजेक्ट 2002 से लंबित पड़ा हुआ था।

यही नहीं, शाहिद के कार्यकाल में, पांच अगस्त के बाद से, श्रीनगर में न कोई बड़ा हिंसक प्रदर्शन हुआ और न कोई बड़ा विकास कार्य रुका है। अगर कहीं कोई काम रुका था तो उसने गति पकड़ी। इसमें शाहिद ने प्रशासक की अपनी भूमिका से कहीं आगे निकल निजी प्रयास किए। दैनिक जागरण से उन्होंने कहा, दरअसल, प्रशासन कागजी विषय नहीं, बल्कि समाज को गहराई से समझने की कला है...।

जम्मू संभाग के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पिछड़े गांव रेहान के रहने वाले डॉ. शाहिद मुस्लिम (गुज्जर) समुदाय से आइएएस बने पहले युवक हैं। 2009 बैच के आइएएस डॉ. शाहिद अपनी तमाम उपलब्धियों का श्रेय खुदा और परिजनों को देते हुए कहते हैं- मैं तो बस जरिया हूं। मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। मैं आम लोगों तक पहुंच बनाकर उन्हें कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने से लेकर विकास योजनाओं में उन्हें भागीदार ही नहीं जिम्मेदार बनाने में यकीन रखता हूं। इसलिए सभी काम आसान हो जाते हैं। कठिन काम करने के लिए गहराई तक जाना पड़ता है...। श्रीनगर प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिख समुदाय या मुस्लिम समुदाय के साथ पहले इन मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई। पहले भी संबंधित पक्षों से कई बार बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। यह डॉ. इकबाल की सूझबूझ का नतीजा है कि दो प्रमुख योजनाएं जिनके पूरे होने की उम्मीद कल तक समाप्त हो चुकी थी, आज हकीकत बनने जा रही हैं।

पिछले दिनों दमदमा साहिब गुरुद्वारे को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में लोगों से बात करते डॉ. शाहिद इकबाल (बाएं)। फाइल फोटो (सौ. ट्विटर)

> मेरा काम प्रशासनिक मदद करना है, वह मैं नियमों के मुताबिक करता हूं, लेकिन पूरा ध्यान रखता हूं कि कागज और किताबों के फेर में कोई सामाजिक अहित न हो...।
> **– डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी, उपायुक्त, श्रीनगर**

सूचना विभाग के अधिकारी आफाक अहमद बताते हैं, डॉ. शाहिद जमीन से जुड़े हुए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने जिस गांव में जिंदगी बिताई है, वहां की मुश्किलों को उन्होंने खुद झेला और महसूस किया है, इसलिए वह जानते हैं कि जनहित योजनाओं में देरी के क्या मायने होते हैं।

आतंक और अलगाववाद को कड़ा जवाब होगा 'मीरास' : कश्मीर में पिछले पांच माह में पहली बार कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। 11 जनवरी को श्रीनगर के टैगोर हॉल में होने जा मीरास कार्यक्रम आतंक और अलगाववाद को भी एक कड़ा जवाब होगा। कश्मीर घाटी में लगातार बदल रही फिजा के बीच अब स्थानीय युवा अपनी लोक संस्कृति के रंग बिखेरने व सहेजने में जुटे हैं। इन कलाकारों में अधिकांश किशोर हैं, जिन्हें अलगाववादी और आतंकी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। अब वे अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका तलाश रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन श्रीनगर जिला प्रशासन की ओर से करवाया जा रहा है। मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान ने कहा कि मीरास का मतलब है विरासत, इसमें कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का कोई रंग नहीं छूटेगा। आयोजन से जुड़े एंजल्स कल्चरल अकादमी के अध्यक्ष तारिक अहमद शेरा ने कहा कि कश्मीरी युवा खुद को पत्थरबाजी या आजादी के नारों से जोड़ने को तैयार नहीं है, वह दुनिया को हकीकत से रूबरू कराना चाहता है और यही मीरास में दिखेगा। आतंकियों व अलगाववादियों द्वारा कश्मीर में सिनेमा, गीत, संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताए जाने पर कश्मीर के वरिष्ठ साहित्यकार हसरत गड्डा ने कहा कि अब यहां इस तरह के फरमान नहीं चलेंगे। कश्मीरियों को अपनी लोक विरासत बहुत अजीज है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

प्रीति ने बदली रीत, बधाई की जगह सिखा रहीं शिक्षा के गीत

थर्ड जेंडर बच्चों का भविष्य संवारने में जुटीं किन्नर डेरे की प्रमुख, स्कूल में सामान्य बच्चों संग पढ़ रहे किन्नर डेरों के बच्चे

पंजाब में संगरूर के किन्नर डेरे की प्रमुख प्रीति महंत। जागरण

मनदीप कुमार, संगरूर

- संगरूर सहित पंजाब के अन्य शहरों में बदल रही किन्नर डेरे के बच्चों की जिंदगी
- कहती हैं, इन बच्चों की जिंदगी नाचने-गाने और बधाई मांगने तक ही सीमित न रहे यही है ध्येय

सुशिक्षित समाज

संगरूर, पंजाब के किन्नर डेरे की प्रमुख प्रीति महंत थर्ड जेंडर बच्चों का भविष्य संवारने में जुटी हैं। डेरे की शरण में आए थर्ड जेंडर बच्चे स्कूल में सामान्य बच्चों संग पढ़ रहे हैं। अपनी इस दूरदर्शी सोच के कारण प्रीति महंत आम किन्नरों से कहीं अलग नजर आती हैं। वह नहीं चाहतीं कि डेरे में छोड़ दिए गए अनेक थर्ड जेंडर बच्चे केवल इसलिए दुरूह जीवन जिएं कि वे थर्ड जेंडर हैं, जिसमें उनका कोई कुसूर तक नहीं। प्रीति कहती हैं, इन बच्चों की जिंदगी बधाई मांगने तक ही सीमित न रहे, यही ध्येय है।

प्रीति आधा दर्जन से अधिक किन्नर डेरों में रहने वाले थर्ड जेंडर बच्चों को स्कूल भेज कर शिक्षित करने का काम कर रही हैं। कहती हैं, कुछ वर्ष पहले मैंने नवजात थर्ड जेंडर विश्वनूर को गोद लिया था। वह उस समय मात्र सात दिन की थी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो डेरे के बाहर से रोजाना गुजरने वाली स्कूल वैन के पीछे भागती। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि इसे आम बच्चों की भांति शिक्षित बनाऊंगी। मैंने उसे स्कूल में दाखिल करवाया। फिर यहीं से यह सिलसिला शुरू हो गया। प्रीति चाहती हैं कि विश्वनूर उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक काबिल आइपीएस अफसर बने। यही नहीं, वह इस बारे में भी सोच रही हैं कि विश्वनूर का ऑपरेशन कराएंगी ताकि उसे एक सामान्य महिला बनाया जा सके। स्कूल अध्यापिका अंजलि वर्मा कहती हैं कि प्रीति की यह पहल बेहद सराहनीय है। शिक्षा पर सबका बराबर का हक है। विश्वनूर पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वह हर चीज आम बच्चों की भांति ही सीखती है।

> भले ही अब हमें थर्ड जेंडर कहा जाने लगा है, लेकिन समाज में किन्नरों की जिंदगी बेहद बदतर बनी हुई है। किसी प्रकार की सुविधा उन्हें नहीं दी जाती है। अपने हकों के लिए भी वे जागरूक नहीं हैं। हमारी नई पीढ़ी यदि सुशिक्षित होगी तो ही इस दुर्दशा से उबर सकेगी।
> **– प्रीति महंत, किन्नर डेरा प्रमुख, पंजाब**

प्रीति कहती हैं, मेरा बचपन से जवानी तक का समय शहर की गलियों और शादियों में नाचते-गाते हुए गुजर गया। कोई नौकरी और कोई रोजगार नहीं। समाज ने भी हाशिये पर धकेलकर रखा। पढ़ने का शौक तो बहुत था, लेकिन मौका नहीं मिला। जिंदगी में हासिल तो काफी कुछ किया, लेकिन शिक्षा का अरमान दिल में ही रह गया। अब आगे किसी के साथ ऐसा न होगा। हमारी नई पीढ़ी को स्कूल-कॉलेज जाने का मौका मिले और वे आसान जीवन जी सकें। जीवन सड़कों पर नाचने-गाने और बधाई पर निर्भर न रहे। उच्च शिक्षा हासिल कर और अपने पैरों पर खड़े होकर वह समाज को दिखा देंगे कि वह भी समाज का एक अंग हैं...।

प्रीति के प्रयास से अलग-अलग शहरों में ऐसे बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। वहां उन्हें अन्य बच्चों के साथ ही शिक्षा मिल रही है। प्रीति बताती हैं कि कई स्कूल उन्हें दाखिला देने से मना कर देते हैं, लेकिन कुछ मान भी जाते हैं। आज भी लोगों की सोच किन्नरों के प्रति बदली नहीं है। कहती हैं, मैं इस सोच को बदलना चाहती हूं। मेरे परिवार ने भी किन्नर होने के कारण मुझे किन्नर डेरे में छोड़ दिया था। वह वक्त बेहद दुखदाई था, लेकिन इस जिंदगी को स्वीकार करना पड़ा। अब मैं महंतों के डेरे का संचालन कर रही हूं, तो सोचती हूं कि अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सकूं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

सालभर में 25 हजार चूहे खाने वाली खलिहान उल्लू प्रजाति का जोड़ा मध्य प्रदेश में मिला

अबरार खान, भोपाल

- भोपाल के वन विहार में चल रहा पक्षी जोड़े का उपचार, मप्र के दो युवकों ने बचाई पक्षी की जान

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे ग्राम फंदा के अमरोदा में एक किसान के घर बार्न आउल (खलिहान उल्लू) का एक जोड़ा घायल अवस्था में मिला। उसे तत्काल किसान की मदद से वन विहार पहुंचाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इसकी खासियत है कि यह जोड़ा एक साल में 25 हजार चूहे खा लेता है।

घटना गत शनिवार की है। अमरोदा निवासी किसान सोनू मेवाड़ा के पुराने घर की दीवार गिर गई थी। वह उसे ठीक करवाने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दीं। पहले तो वह डर गए, लेकिन अंदर जाने पर देखा तो वहां बार्न आउल का एक घायल जोड़ा था। इस पर सोनू ने जागरूकता दिखाते हुए इन पक्षियों को बचाने की ठानी और बिना कुछ सोचे समझे उनका इलाज करवाने में जुट गया। पहले तो उसने ग्रामीणों की मदद से ऐसे लोगों से संपर्क किया जो टोने-टोटके करते हैं, लेकिन उसे सफलता नहीं मिला। दरअसल, ग्रामीणों में उल्लू को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। नाखून, दांत,

भोपाल में एक किसान के घर की दीवार गिरने से घायल बार्न आउल (खलिहान उल्लू) के जोड़े का वनविहार के रेस्क्यु सेंटर में चल रहा है उपचार। मुहम्मद अबरार खान

हड्डियां तक टोने-टोटके में इस्तेमाल कर कई तांत्रिक ग्रामीणों से मोटी रकम ऐंठते हैं। इसके बाद सोनू मेवाड़ा ने फंदा ग्राम के किसान सफर अली को जानकारी दी। सफर भोपाल में वन्यजीव संरक्षण का कार्य करने वाले डॉ. जफर को जानते थे। उन्होंने तत्काल उन्हें यह सूचना दी। डॉ. जफर रविवार को वहां पहुंचे और इस जोड़े को लाकर वन विहार पहुंचाया, जहां डॉ. अतुल गुप्ता की निगरानी में उनका इलाज हो रहा है। जल्द ही यह बार्न आउल जोड़ा उड़ान भरेगा।

कई देशों में इन्हें पालने के लिए दी जाती है प्रोत्साहन राशि : भोपाल वन विहार के पूर्व सहायक संचालक डॉ. सुदेश वाघमारे ने बताया कि इस प्रजाति का जोड़ा एक साल में 25 हजार चूहे खा सकता है। कई देशों में चूहे एवं सांप आदि रेंगने वाले जीवों को कंट्रोल करने के लिए वहां की सरकारें नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देकर इन्हें पालने के लिए जागरूक करती हैं।

मुंह होता है दिल के आकार का : खलिहान उल्लू का मुंह देखने में पान के आकार या दिल के आकार का दिखाई देता है। यह तकरीबन पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ज्ञात हो कि उल्लू पक्षी की दुनिया भर में 216 प्रजातियां हैं। इनमें 16 बार्न आउल होते हैं। यह अपना घर नहीं बनाता। इंसानों द्वारा बनाई गई संरचनाओं, टॉवरों या पुराने घरों में अपने अंडे देता है। किसानों के सबसे बड़े मित्र हैं, लेकिन कीटनाशक के उपयोग ने इनके जीवन को संकट में डाल दिया है।

वन्यजीव सुरक्षा के मद्देनजर चीन-नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी

केदार दत्त, देहरादून : क्रिसमस से लेकर पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत को होने वाले जश्न ने वन्यजीव महकमे की नींद उड़ा दी है। लिहाजा, खतरनाक माने जाने वाले इस वक्त में वन्यजीव सुरक्षा के मद्देनजर चीन और नेपाल की सीमा से लगे संरक्षित क्षेत्रों में चौकसी कड़ी कर दी गई है। साथ ही प्रदेशभर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और अंतरराज्यीय सीमा पर विशेष निगहबानी की जा रही है। यह किसी से छिपा नहीं है कि उत्तराखंड के वन्यजीव शिकारियों और तस्करों के निशाने पर हैं। इनके तार सीमा पार से जुड़े होने की बातें भी कई मर्तबा सामने आई हैं। अब जबकि क्रिसमस से लेकर न्यू इयर ईव तक चलने वाले जश्न की तैयारियां चल रही हैं तो वन्यजीव महकमे की चिंता बढ़ गई है। जश्न के माहौल के दौरान शिकारियों व तस्करों के सक्रिय होने की आशंका रहती है। यही कारण भी है कि क्रिसमस से लेकर पांच जनवरी तक के वक्त को विभाग की भाषा में 'खतरनाक वक्त' कहा जाता है। पूर्व में इस अवधि में शिकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं। खतरनाक वक्त में वन्यजीवों पर कोई आंच न आए, इसके मद्देनजर महकमे ने सुरक्षा को लेकर खास ताना-बाना बुना है।

प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास हैं बिहार के रिक्शाचालक शंभू पासवान

अमित झा, खगड़िया

2015 में पत्नी के बीमार पड़ने पर पहली बार प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र, वह भी देते हैं हर चिट्ठी का जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के खगड़िया के एक रिक्शाचालक का कनेक्शन लोगों में चर्चा का विषय है। रिक्शाचालक शंभू पासवान ने पीएम को जन्मदिन पर बधाई दी तो उन्होंने भी पत्र भेज आभार जताया। ऐसा नहीं कि खगड़िया के गोगरी जमालपुर निवासी शंभू पासवान को पीएम ने पहली बार पत्र भेजा है। मोदी इनके हर एक पत्र का जवाब पहले भी देते रहे हैं। पहली बार शंभू ने अपनी पत्नी के इलाज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा था। पीएम ने संज्ञान भी लिया। उनके निर्देश पर उनकी पत्नी का इलाज हुआ। तबसे लगातार शंभू पीएम से पत्राचार कर रहे हैं।

2015 में शंभू पासवान की पत्नी की तबियत खराब हो गई। इलाज के दौरान गोगरी अस्पताल में दवा नहीं मिली। फिर क्या था, उन्होंने सीधे इसकी शिकायत प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से कर दी। पीएम ने इस पर फौरन संज्ञान लिया। इसके बाद डीएम और सिविल सर्जन सक्रिय हुए तथा उन्हें सदर अस्पताल से दवा मुहैया कराई गई।

जानें शंभू रिक्शावाले को

शंभू की उम्र 55 वर्ष है। उनके परिवार में पत्नी लीला देवी, चार पुत्र और तीन पुत्री हैं। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। दो पुत्र मजदूरी करते हैं और दो पढ़ाई कर रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी का पत्र दिखाते शंभू पासवान। जागरण

हर खास अवसर पर शंभू भेजते हैं पीएम को पत्र : शंभू पासवान पीएम मोदी को हर खास अवसर पर पत्र भेजते हैं। यह सिलसिला 2015 से जारी है। पीएम मोदी भी उनके पत्र का जवाब देने से नहीं चूकते। हाल में ही शंभू ने पीएम मोदी को उनके 69वें जन्मदिन पर पत्र भेजा। पीएम ने जन्मदिन की शुभकामना को लेकर उनका आभार पत्र भेजकर प्रकट किया। पीएम मोदी का यह पत्र शंभू को नवंबर में मिला। इसमें मोदी ने उनके व उनके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य व सुखद भविष्य की कामना की है। अब शंभू पासवान पीएम को नववर्ष 2020 की शुभकामना के लिए पत्र भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

रंग लाया प्रयास

एक शिक्षक की जिद से ढहती इमारत का परचम बुलंद

आजादी से पहले बने स्कूल को मुख्याध्यापक ने दिया नया रूप, शहर के लोगों से आर्थिक मदद व अपने वेतन से तीन कमरे बनवाए

नितिन शर्मा, यमुनानगर

शिक्षक का धर्म बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। इस बात को चरितार्थ करते हैं हरियाणा के यमुनानगर के शिक्षक जिले सिंह। इसके पीछे उनके वे कार्य हैं, जिनके कारण उनका नाम शिक्षा विभाग में अब मिसाल के तौर पर लिया जाता है। जिस सरकारी स्कूल के भवन को सरकार ने असुरक्षित घोषित कर था, उसी स्कूल में बने कमरों और वहां की दरो-दीवार की खूबसूरती दूसरों के लिए प्रेरणा का सबब बन गई है। इस लक्ष्य को पाने के लिए जिले सिंह ने दूसरों से मदद मांगने में संकोच नहीं किया तो साथ ही खुद के वेतन की भी परवाह नहीं की।

यमुनानगर में रेलवे स्टेशन चौक के नजदीक राजकीय मिडिल स्कूल का भवन आजादी से पहले वर्ष 1943 में बना। हालांकि, वक्त के साथ इसकी दीवारें खराब स्थिति में पहुंच चुकी थीं। कभी बच्चों से गुलजार रहने वाले इस स्कूल में छात्रों की संख्या भी महज 17 ही बची थी।

हरियाणा के यमुनानगर में विद्यालय नं. 1 की पुरानी इमारत की तस्वीर दिखाते हेडमास्टर जिले सिंह व उनके पीछे नया भवन। जागरण

प्लाइवुड संचालक से सहयोग ले बनवा दिए डेस्क

स्कूल में बच्चों के बैठने की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। यहां के बच्चे पहले नीचे फर्श पर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। यहां टाट-पट्टी का भी अभाव था। जिले सिंह ने ठान लिया था कि बच्चों को डेस्क मुहैया करानी है। इसके लिए प्लाइवुड संचालक से प्लाई के कट पीस का सहयोग लिया। अपने खर्च पर ही डेस्क और बेंच बनवाए।

बच्चों के लिए घर-घर गए

स्कूल बंद न हो जाए इसके लिए जिले सिंह आसपास के घरों में गए। अभिभावकों से वादा किया कि उनके बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे। इसका नतीजा है कि इस समय स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे हैं। यह स्कूल पहले सिर्फ प्राइमरी तक था। जिले सिंह ने प्रयास कर मिडिल कराया।

इसी बीच साढ़े तीन साल पहले महेंद्रगढ़ जिले के जिले सिंह ने बतौर मुख्याध्यापक यहां का कार्यभार संभाला। आते ही स्कूल को संजीवनी दे दी। इमारत के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने शहर के लोगों से आर्थिक मदद ली, साथ ही अपने वेतन के पैसे साथ मिलाए। करीब दस लाख रुपये खर्चकर स्कूल में तीन नए कमरों का निर्माण कराया। इसके बाद दो कमरे सरकार ने बनवाए। सरकार ने इस स्कूल के भवन को असुरक्षित घोषित किया था। इसके बाद भी यहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। भवन के निर्माण की मांग लेकर मुख्य अध्यापक जिले सिंह ने विभाग के उच्चाधिकारियों को कई बार पत्र लिखे, मगर इस पर कोई संतोषजनक कार्यवाही विभाग की ओर से नहीं हुई। बार-बार के प्रयास के बाद भी निराशा ही हाथ लगी।

फिर खुद निकले संपर्क करने : कोई सफलता नहीं मिली तो जिले सिंह खुद ही शहर में निकले। सबसे पहले आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात की। उनकी ओर से दो लाख रुपये की मदद मिली तो उनका हौसला बढ़ा। इन्हीं पैसों में खुद के वेतन से भी कुछ रुपये मिलाए। इसके बाद जर्जर दीवारों को नया रूप दिया।

जापान और कनाडा की ट्रेनों पर भी सजेगी मिथिला पेंटिंग

जागरण संवाददाता, पटना

- दोनों देशों ने रेलवे बोर्ड से इस संबंध में मांगी जानकारी

बिहार की मशहूर मिथिला पेंटिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। पूर्व-मध्य रेल की ओर से इन पेंटिंग से मधुबनी स्टेशन एवं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को सजाया क्या गया कि इन्हें दूर देशों में पहचान मिलने लगी। यूनाइटेड नेशंस के भारतीय कार्यालय ने ट्विटर के माध्यम से दोनों ट्रेनों की सजावट को सराहा है। जापान व कनाडा जैसे देश ने भी अपने यहां की ट्रेनों और स्टेशनों को मिथिला पेंटिंग्स से सजाने की कवायद शुरू कर दी है। दोनों देशों ने रेलवे बोर्ड से जानकारी मांगी है। रेल मंत्रालय की ओर से दोनों देशों को इसकी पूरी जानकारी भेजी जा रही है।

राजेंद्रनगर टर्मिनल से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की रैक को मिथिला पेंटिंग के कारण अलग से पहचाना जा सकता है। इस संबंध में पूर्व-मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि रेल प्रबंधन की ओर से बिहार की मशहूर मिथिला पेंटिंग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की गई है। पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र स्टेशन, मधुबनी स्टेशन, राजेंद्रनगर टर्मिनल के साथ ही राजधानी और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। इससे इस कला से जुड़े कलाकारों को दूसरे देशों की ट्रेनों व स्टेशनों को सजाने का ऑफर मिलने लगा है।

ट्रेन की रौनक बढ़ाती मिथिला पेंटिंग। फाइल

मुकेश अंबानी की संपत्ति एक लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली, आइएएनएस : रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में इस साल एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी को दुनिया का 12वां सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष मुकेश अंबानी की संपत्ति 16.5 बिलियन डॉलर (करीब 1,15,500 करोड़ रुपये) बढ़कर 60.8 बिलियन डॉलर (करीब 4,25,600 करोड़ रुपये) पहुंच गई।

चीन से समझौता हो गया है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात में हम इस पर हस्ताक्षर करेंगे। यह जल्द होगा। दोनों देश ऐसा चाहते हैं।
— डोनाल्ड ट्रंप
राष्ट्रपति, अमेरिका

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
41,461.26	12,214.55	₹ 39,239	₹ 47,146	₹ 71.27	$ 67.12
▼ 181.40	▼ 48.20	▲ ₹ 191	▲ ₹ 943	▲ ₹ 0.09	

जरूरी कदम ▸ आर्थिक सुस्ती को चिंताजनक बताते हुए आइएमएफ ने दिए कई सुझाव

आइएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष खड़ी चुनौतियां गिनाईं

विकास दर को पटरी पर लाने के लिए कर्ज और सस्ता करने की सलाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ राजकोषीय नीति को लेकर अनिश्चितता दूर करना भी वक्त की जरूरत

▸ दबाव में चल रहे फाइनेंशियल सेक्टर को सबसे ज्यादा सुधार की दरकार

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर रिपोर्ट जारी की है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर पेश करते हुए आइएमएफ ने साफ तौर पर कहा है कि आर्थिक सुस्ती के दौर से निपटने के लिए राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और वित्तीय सुधार से जुड़ी नीतियों को लेकर कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। आइएमएफ ने सोमवार देर रात अमेरिका में भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट आइएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ के भारत दौरे के दो दिन बाद ही जारी की गई है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आइएमएफ की बात मानती हैं तो बजट में कम से कम आधा दर्जन बड़े नीतिगत फैसले करने होंगे। भारत की संभावित आर्थिक विकास दर को लेकर आइएमएफ अगले महीने एक और रिपोर्ट भी जारी करेगा।

आइएमएफ के एशिया विभाग के उप निदेशक रानिल सल्डागो के मुताबिक, 'भारत बड़ी आर्थिक मंदी की गिरफ्त में है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर घटकर महज 4.5 फीसद रह गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि निजी निवेश में सिर्फ एक फीसद की वृद्धि हुई है। मंदी की यह स्थिति दिसंबर में भी बने रहने के संकेत हैं।' इस हालात के लिए जो वजहें बताई गई हैं उनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की स्थिति खराब होने और दूसरे स्रोतों से कर्ज बांटने की रफ्तार एकदम कम होना सबसे ऊपर है। वैसे तो पूरे देश में निजी खपत की रफ्तार बेहद कम हो गई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह से जीएसटी को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को भी मौजूदा दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खपत कम होते जाना भी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण। प्रतीकात्मक फोटो

उठाने होंगे कई कदम

आइएमएफ ने कहा है कि महंगाई में तेजी है लेकिन समय आर्थिक सुस्ती से उबरने के कदम को तवज्जो देने का है, इसलिए ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है। राजकोषीय स्तर पर सरकार के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि वह व्यय को बढ़ावा दे। आइएमएफ ने परोक्ष तौर पर सलाह दी है कि सरकार को विकास दर की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। घरेलू स्तर पर राजस्व को बढ़ाने के जरूरी उपायों के साथ ही सब्सिडी कटौती फिलहाल वक्त की जरूरत है। आइएमएफ ने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर की खराब स्थिति पर ध्यान देने की सलाह सरकार को दी है। भारत के समूचे वित्तीय सेक्टर सरकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की माली हालात सुधारने के लिए सोची समझी रणनीति की सलाह दी गई है। आइएमएफ ने कहा है कि ढांचागत सुधार की जरूरत अभी पहले से भी ज्यादा है। भूमि, श्रम, गवर्नेंस सुधार जैसे मुद्दे लंबी अवधि में विकास दर को तेज करेंगे।

कच्चे माल और तैयार उत्पादों पर ड्यूटी के फर्क से बढ़ रहा बोझ

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

▸ सरकार का अनुमान, हर साल रिफंड के खाते में देने होंगे 20000 करोड़ रुपये

▸ करीब दो दर्जन वस्तुओं के लिए कच्चे माल पर तैयार उत्पाद से ज्यादा है ड्यूटी

▸ जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस अंतर को खत्म करने पर विचार संभव

दरों को एक जैसा करना समय की जरूरत। प्रतीकात्मक फोटो

कच्चा माल और उससे तैयार होने वाले उत्पाद में ड्यूटी की दर में फर्क के चलते सरकार को हर साल 20000 करोड़ रुपये का रिफंड देना होगा। ऐसी करीब दो दर्जन वस्तुएं हैं जिनके कच्चे माल पर जीएसटी की दर अधिक है जबकि तैयार माल पर ड्यूटी की दर कम है। जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में इस असंतुलन को दूर करने के संबंध में काउंसिल अपनी अगली बैठक में विचार कर सकता है।

इस तरह के ड्यूटी स्ट्रक्चर को इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (आइडीएस) का नाम दिया गया है। 18 दिसंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक के लिए तैयार एक नोट के मुताबिक 'सरकार का अनुमान है कि इस पर सालाना 20000 करोड़ रुपये का रिफंड देना होगा।' इस तरह की सबसे ज्यादा दिक्कत मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में जीएसटी की पांच और 12 परसेंट के दायरे में आने वाले उत्पादों पर आ रही है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस तरह के रिफंड की मांग सर्विस और कैपिटल गुड्स क्षेत्र से भी उठ सकती है। ऐसा होता है तो विवादों और कानूनी मामलों की संख्या में वृद्धि होगी। सूत्र बताते हैं कि आम बजट के बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका समाधान तलाशने पर विचार हो सकता है।

काउंसिल के नोट में ऐसे करीब दो दर्जन उत्पादों का जिक्र है जिनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी की ऊंची दर है जबकि तैयार माल पर टैक्स की दर कम है। इनमें मोबाइल फोन, फुटवियर, फैब्रिक्स, मैन मेड यार्न, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्टिलाइजर, रिन्यूवल इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, फार्मा, जेनरेटर समेत कई उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग में कंपनियों को कच्चे माल पर जीएसटी की ऊंची दर से भुगतान करना पड़ता है। लेकिन कंपनियां जब तैयार माल को बाजार में बेचती हैं तो उन पर ड्यूटी की दर कम होती है।

कच्चे माल और तैयार माल पर लागू जीएसटी की दर के अंतर की भरपाई के लिए जीएसटी में प्रावधान है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत साल के अंत में जीएसटी में पंजीकृत कंपनी या व्यक्ति इस अंतर की वजह से बचे रह गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट कंपनी डेलॉय इंडिया के पार्टनर एमएस मणि का मानना है कि इस समस्या के निदान के लिए सभी तरह की वस्तुओं के लिए टैक्स की एक दर का प्रावधान करना होगा। अंतरिम राहत केवल यही हो सकती है कि इसके रिफंड के सिस्टम में तेजी लाई जाए ताकि कंपनियों की कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) का प्रवाह बना रह सके।

आइबीसी में संशोधन के लिए आएगा अध्यादेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कैबिनेट का फैसला

▸ पुराने प्रमोटरों के आपराधिक मामले नए प्रमोटरों पर नहीं होंगे लागू

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) में कुछ संशोधनों को शामिल करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून में प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाएंगे।

सरकार ने कानून में बदलाव कर आइबीसी के तहत किसी कंपनी का अधिग्रहण करने वाले प्रमोटरों को राहत दी है। इसके तहत दिवालिया होने वाली कंपनियों के नए प्रमोटर पर पुरानी कंपनी या उसके प्रमोटरों पर चल रहे आपराधिक मामले जारी नहीं रहेंगे। उन्हें इन सभी मामलों से मुक्त रखा जाएगा।

सरकार ने इस आशय का विधेयक 12 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। लेकिन यह संसद से पारित नहीं हो पाया। इसी वजह से सरकार को इस आशय का अध्यादेश लाना पड़ा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर ने सदन में पेश इस विधेयक को वित्त पर संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है।

आइबीसी में इस आशय का बदलाव करने की उद्योग जगत लंबे अरसे से मांग कर रहा था। सरकार के इस प्रस्ताव का उद्देश्य दिवालिया कंपनियों के मामले निपटाने में आ रही दिक्कतों को दूर करना है। कानून में यह बदलाव कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी के प्रस्तावों के निपटारे में आ रही दिक्कतों को दूर करेगा। जानकारों के मुताबिक दिवालिया कानून के तहत जिन कंपनियों की बिक्री का प्रस्ताव किया जाता है उनमें नए प्रमोटर इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि पुरानी कंपनी और प्रमोटरों पर चल रहे आपराधिक मामलों की जिम्मेदारी भी अन्य देनदारियों के साथ उन पर आ जाती है। इसलिए उद्योग इस नियम में बदलाव की लगातार मांग कर रहा था।

आर्थिक सुस्ती की चिंता में टूटे बाजार

▸ आर्थिक सुस्ती को लेकर आइएमएफ के बयान का दिखा असर

▸ आरआइएल, एचडीएफसी और एचसीएल के स्टॉक्स लुढ़के

▸ सेंसेक्स में 181 अंक और निफ्टी में 48 अंकों की गिरावट दर्ज की गई

एशियाई बाजारों में रहा मिलाजुला रुख। प्रतीकात्मक फोटो

मुंबई, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था में नरमी के बयान का असर मंगलवार को प्रमुख शेयर बाजारों पर दिखा। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 181.40 अंक फिसलकर 41,461.26 के स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान कुछ बड़े स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 48.20 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यह 12,214.55 के स्तर पर बंद हुआ।

जानकारों के मुताबिक सरकार द्वारा विनिवेश लक्ष्य में चूक की आशंका के चलते निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ। इसके अलावा भारतीय इकोनॉमी को लेकर आइएमएफ के बयान से भी बाजारों में नकारात्मक संदेश गया। गौरतलब है कि आइएमएफ ने भारत में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई है। साथ ही कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। इस स्थिति से उबरने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। आइएमएफ के इस बयान का असर निवेशकों की धारणा पर दिखा। आर्थिक सुस्ती की चिंता में निवेशकों ने बिकवाली की राह पकड़ ली। सेंसेक्स पैक में एचसीएल के शेयरों में सबसे ज्यादा 1.80 परसेंट की गिरावट आई। इसके साथ ही आरआइएल, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। हालांकि इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प और एनटीपीसी के शेयरों में तेजी देखी गई।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) द्वारा खाद्य कीमतों में फेरबदल की सूचना के बाद कंपनी के शेयरों में 2.6 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। बीएसई में एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, आइटी और टेक कंपनियों के शेयरों में 1.21 परसेंट तक की गिरावट आई।

मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में नौ पैसे की गिरावट आई। इस दौरान एक डॉलर की कीमत 71.27 रुपये दर्ज की गई। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई और टोक्यो के शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। वहीं हांगकांग और सियोल के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई।

अक्टूबर में 12.44 लाख लोगों को मिला रोजगार

▸ सितंबर, 2017 से अक्टूबर, 2019 के बीच 3.22 करोड़ लोग ईएसआइसी स्कीम से जुड़े

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस साल सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में ज्यादा लोग रोजगार हासिल करने में सफल रहे हैं। एंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआइसी) के पेरोल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में 12.44 लाख लोगों को रोजगार मिला। सितंबर में यह संख्या 12.23 लाख रही थी। एनएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 1.49 करोड़ लोग ईएसआइसी से जुड़े।

एनएसओ की यह रिपोर्ट कई सामाजिक सुरक्षा स्कीमों से लिए गए आंकड़ों की मदद से बनाई गई है। इसमें ईएसआइसी, ईपीएफओ, पीएफआरडीए से नए जुड़े लोगों के आंकड़े लिए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर, 2017 से अक्टूबर, 2019 के बीच कुल 3.22 करोड़ लोग ईएसआइसी स्कीम से जुड़े। इन तीन निकायों के आंकड़े एनएसओ पिछले वर्ष अप्रैल से जारी कर रहा है। इसमें शुरुआती आंकड़े सितंबर, 2017 से लिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अक्टूबर में ईपीएफओ के साथ 7.39 लाख नए खाताधारक जुड़े। सितंबर में यह संख्या 9.48 लाख थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 61.12 लाख नए लोग ईपीएफओ से जुड़े। सितंबर, 2017 से अक्टूबर, 2019 के बीच करीब 2.93 करोड़ नए लोग ईपीएफओ से जुड़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंकड़े अलग-अलग स्रोत से लिए गए हैं, इसलिए इनमें दोहराव संभव है। यह संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति बताते हैं, लेकिन समग्र तौर पर रोजगार की संख्या को मापने में सक्षम नहीं हैं।

एक बार सीएनजी भरने पर हजार किमी दौड़ेगी बस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में किया अनावरण, स्वच्छ ईंधन की दिशा में बढ़ा अहम कदम

सामान्य सीएनजी गैस सिलेंडर से करीब 70 फीसद हल्के सिलेंडरों से लैस भारत की पहली लंबी दूरी तय करने वाली बस का अनावरण मंगलवार को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) के एक कार्यक्रम में किया। सिलेंडर हल्के होने से इनमें अधिक सीएनजी भरी जा सकती है, जिससे सभी सिलेंडर फुल होने पर बस एक बार में 800 से एक हजार किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी।

इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्वच्छ ईंधन के रूप में गैस आधारित ईंधन की दिशा में तेजी से कदम बढ़े हैं। दिल्ली-एनसीआर में इस समय 500 से अधिक सीएनजी स्टेशन हैं। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे शहरों तक जाने वाली सीएनजी बसों में इस बदलाव से स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम बढ़ेंगे। इससे वायु प्रदूषण कम होगा और वातावरण बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को कम कीमत पर स्वच्छ ईंधन मिले। सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही है। जैविक ईंधन नीति किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने में मदद करेगी। देश के विभिन्न हिस्सों में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। सरकार ने बीएस-4 से सीधे बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू करने का फैसला लिया है। पहली अप्रैल, 2020 से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बीएस-6 वाहनों से ईंधन की खपत के बाद सल्फर उत्सर्जन 50 पीपीएम के बजाय 10 पीपीएम रह जाएगा। इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

हल्के सिलेंडरों से लैस देश की पहली बस का अनावरण करने के बाद आइजीएल के अधिकारियों के साथ पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बाएं से तीसरे)। आइजीएल

चीन से आने वाले रसायनों पर डंपिंग आरोपों की जांच शुरू

▸ घरेलू कारोबारियों ने चीन पर लगाया है डंपिंग का आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने चीन से आने वाले रसायनों को लेकर डंपिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू कंपनियों की शिकायत है कि डाई और फार्मा कारोबार में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की चीन द्वारा डंपिंग की जा रही है। प्राइमा केमिकल्स ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज (डीजीटीआर) के पास इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है।

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डीजीटीआर इस मामले में चीनी कंपनियों द्वारा रसायनों की डंपिंग और इससे घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की जांच कर रहा है। अगर जांच में डंपिंग की बात सच साबित होती है, तो डीजीटीआर घरेलू कारोबार को सस्ते आयात से बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश कर सकता है। डीजीटीआर अप्रैल, 2018 से जून, 2019 के बीच चीन से हुए रसायनों के आयात की जांच करेगा। इस दौरान 2015-18 के बीच हुए रसायन आयात पर भी एंटी डंपिंग जांच हो सकती है। यह जांच उन मामलों में की जाती है, जहां किसी वस्तु के सस्ते आयात के चलते उसके घरेलू कारोबार के समक्ष खतरा पैदा हो जाता है। इससे बचाव के लिए डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित नियमों के दायरे में रहकर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। भारत ने पहले ही चीन समेत कई देशों के विभिन्न उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है।

घरेलू क्रूड ऑयल पर लगने वाले सेस में हो सकती है कटौती

नई दिल्ली, आइएएनएस : मेक इन इंडिया के तहत ऑयल एंड गैस की खोज को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगामी बजट में घरेलू क्रूड ऑयल पर लगने वाले सेस में कटौती कर सकती है। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा तेल और गैस भंडारों की खोज संबंधी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

इस समय घरेलू क्रूड ऑयल पर सेस चार्ज 20 परसेंट है, जो 10 होने की उम्मीद है। हालांकि सेस में कटौती से राजस्व नुकसान की आशंका भी है। ओएनजीसी अकेले इस मद में करीब 10,000 करोड़ रुपये सालाना देता है। सेस में कटौती से कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि आयात किए जाने वाले क्रूड ऑयल पर सेस नहीं लगता है।

आरबीआइ की रिपोर्ट

आइबीसी से 42 फीसद तक हो रही फंसे कर्ज की वसूली

बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या अब आ सकती है काबू में, दो साल में एनपीए का स्तर 11.2 फीसद से 9.1 फीसद पर आया, वसूली के चलते हर तरह के एनपीए में आ रही है कमी

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

तकरीबन सात वर्ष बाद अब ऐसा लगने लगा है कि देश का बैंकिंग सिस्टम एनपीए यानी फंसे कर्जे की फांस से बाहर आने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन्सॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) यानी नया दिवालिया कानून है जिसकी वजह से 42.5 फीसद तक एनपीए की वसूली संभव हो पा रही है। फंसे कर्ज की वसूली की पुरानी व्यवस्थाओं (लोक अदालत, डीआरटी, सरफाएसी कानून) से महज 3.5 से 14 फीसद तक ही फंसे कर्जे की वसूली हो पा रही थी। यही नहीं आइबीसी में मामले को सलटाने में वक्त भी कम लग रहा है। अब जबकि सरकार ने इस कानून में नए संशोधन कर दिए हैं तो पुराने कर्ज वसूलने का यह तरीका और ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को देश के बैंकिंग सेक्टर के ट्रेंड व प्रोग्रेस पर अपनी ताजा रिपोर्ट पेश की है जो बताती है कि सितंबर, 2019 में बैंकों की तरफ से दिए गए कुल कर्ज का 9.1 फीसद ग्रॉस एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स-ग्राहकों के पास फंसा कर्ज) है। पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में भी इसका स्तर 9.1 फीसद रहा था। वहीं 2017-18 में एनपीए 11.2 फीसद था। इस तरह देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में एनपीए का स्तर स्थिर बना हुआ है। आरबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक सात वर्ष बाद एनपीए के अनुपात में लगातार कमी हुई है। अगर शुद्ध एनपीए की बात करें तो यह भी इस दौरान छह फीसद से घटकर 3.7 फीसद हो गया है। आरबीआइ की रिपोर्ट ने इसे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक शुभ संकेत करार दिया है और माना है कि एनपीए को पहचान करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब एनपीए की वसूली की प्रक्रिया जारी है।

वसूली प्रक्रिया में सबसे अच्छे नतीजे आइबीसी की वजह से आए हैं। वर्ष 2018-19 में आइबीसी में 1.666 लाख करोड़ रुपये के 1135 मामले गए थे और इनमें 70,819 करोड़ रुपये की राशि वसूली जा सकी, जो तकरीबन 42.5 फीसद है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी काम के लिए गठित लोक अदालतों से महज 5.3 फीसद, ऋण वसूली प्राधिकरणों से 3.5 फीसद और सरफाएसी कानून से 14.5 फीसद एनपीए की ही वसूली हो पाती थी। असलियत में हर तरह के एनपीए का अनुपात पहले से कम हुआ है।

प्रतीकात्मक फोटो

बाकी हैं कई चुनौतियां

क्या एनपीए के स्तर में कमी आने को देश के बैंकिंग सेक्टर को मजबूत माना जा सकता है? इस सवाल का जवाब अगर आरबीआइ की रिपोर्ट में खोजने की कोशिश की जाए तो सीधा सा उत्तर है नहीं। एनपीए में कमी आने के बावजूद संचालन लागत का ज्यादा होना, वैश्विक हालात, आर्थिक मंदी, तकनीकी के स्तर पर आने वाली चुनौतियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, शहरी सहकारी बैंकों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है और सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर इन्हें सुधारने के लिए अभी लगातार कोशिश करनी होगी।

बैंकों का विलय सही कदम

आरबीआइ ने सरकारी बैंकों में हो रहे विलय को सही माना है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अभी हमारा कोई भी बैंक दुनिया के टॉप-50 बैंकों में शामिल नहीं है। विलय के जरिये बड़े और विश्वस्तरीय बैंक गठन का रास्ता खुलेगा। केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग सेक्टर को विभिन्न तकनीकी कंपनियों की तरफ से मिल रही चुनौती पर भी नजर रखने को कहा है।

बैंक फ्रॉड के मामले बढ़े

आरबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकों में 71,543 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सामने आए। इससे पिछले वित्त वर्ष के 41,167 करोड़ रुपये की तुलना में यह 74 फीसद ज्यादा है। संख्या के हिसाब से देखें तो 2018-19 में कुल 6,801 मामले सामने आए, जबकि सालभर पहले ऐसे 5,916 मामले आए थे। संख्या के हिसाब से धोखाधड़ी के 55.4 फीसद मामले सरकारी बैंकों में सामने आए। राशि के हिसाब से सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 90.2 फीसद रही।

सीआरआइ पंप्स को पांचवीं बार नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड

नई दिल्ली, (वि.) : ऊर्जा दक्षता के मामले में अग्रणी कंपनी सीआरआइ पंप्स को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, 2019 से सम्मानित किया गया है। बीईई के फाइव स्टार रेटिंग वाले पंप बनाने वाली सीआरआइ को पंप कैटेगरी में लगातार तीसरी बार और कुल पांचवीं बार यह पुरस्कार मिला है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से पुरस्कार ग्रहण करने के बाद सीआरआइ ग्रुप के संयुक्त प्रबंधन निदेशक जी. सेल्वराज ने भारत सरकार की तरफ मिले इस पुरस्कार को कंपनी के लिए बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर दुनिया बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता से ही लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार पाना संभव हुआ है। सीआरआइ देशभर में अब तक 14 लाख से ज्यादा पंप लगा चुकी है।

8 दिसम्बर 1985 को हुई थी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना। इस संगठन में दक्षिण एशिया के आठ देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

एफएटीएफ ने काली सूची में डाला तो कंगाल हो जाएगा पाक

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने आशंका जताई है कि अगर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को काली सूची में डाला तो देश में धन का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत से जूझ रहा है। इससे उबरने के लिए उसने आइएमएफ के अलावा सऊदी अरब और चीन से बड़ा कर्ज ले रखा है। आइएमएफ ने कहा है कि एफएटीएफ के सख्त कदम से आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की स्थिति और डांवाडोल हो सकती है।

दुनियाभर में आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग के मामलों पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने फरवरी, 2020 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उसने 27 सवालों की सूची में से शेष 22 बिंदुओं का पालन नहीं किया तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। पाक ने छह दिसंबर को 22 सवालों के जवाब के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट एफएटीएफ को दी थी। आइएमएफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है, एफएटीएफ

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। फाइल

द्वारा पाकिस्तान को काली सूची में डालने से न केवल पूंजी का प्रवाह प्रभावित होगा बल्कि देश में होने वाले निवेश में भी कमी आएगी। पाकिस्तान में आइएमएफ के कार्यक्रम के समक्ष घरेलू और बाहरी दोनों ही तरह के खतरे हैं। मनी लांड्रिंग मामले पर एफएटीएफ के एशिया-प्रशांत क्षेत्र समूह ने भी पाकिस्तान की मूल्यांकन रिपोर्ट पर चर्चा की है। उसका मानना है कि खतरों के मद्देनजर पाकिस्तान द्वारा आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे उपाय नाकाफी हैं।

बहरीन के शाही परिवार को दी दुर्लभ पक्षी के शिकार की इजाजत

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान ने कतर के बाद बहरीन के शाही परिवार को भी विलुप्तप्राय पक्षी होउबारा बस्टर्ड के शिकार की इजाजत दे दी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बहरीन के किंग शेख हमद सलमान अल खलीफा समेत शाही परिवार के छह सदस्यों को संरक्षित बस्टर्ड के शिकार का विशेष परमिट दिया है। इन लोगों को पाकिस्तान में 31 जनवरी तक 100 बस्टर्ड पक्षियों को मारने की इजाजत होगी।

ठंड के मौसम में मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाए जाने वाले होउबारा बस्टर्ड हर साल पाकिस्तान की ओर पलायन करते हैं। लगातार घटती संख्या के कारण बस्टर्ड ना केवल अंतराष्ट्रीय संधियों के तहत संरक्षित पक्षी है, बल्कि पाकिस्तान में भी स्थानीय वन्यजीव कानून के तहत इसके शिकार पर प्रतिबंध है। लेकिन खाड़ी देशों से अपने हित साधने के लिए पाक इसके शिकार की अनुमति देता रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने पिछले हफ्ते इसी तरह की विशेष छूट कतर के शाही परिवार के सदस्यों को भी दी थी।

पाकिस्तान के शीर्ष वैज्ञानिक ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

- मौलिक अधिकारों की बहाली के साथ स्वतंत्र आवाजाही की मांग की
- अब्दुल कादिर खान को किसी से मिलने की नहीं है इजाजत

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कादिर खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करने की मांग की है। इसमें पूरे देश में स्वतंत्र आवाजाही की मांग भी शामिल है। परमाणु प्रसार में कथित भूमिका के कारण खान को वर्ष 2004 में तत्कालीन सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने दरकिनार कर दिया था। इसके बाद से वह भारी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद में रह रहे हैं और उन्हें किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है।

खान की ओर से वकील जुबैर अफजल राणा ने गत 25 सितंबर के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें दिए गए विशेष सुरक्षा उपायों के तहत यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। डॉन अखबार के मुताबिक खान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि किसी की पसंद या नापसंद पर मनमाने तरीके से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।

याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या सरकारी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के दोस्तों और परिजनों से मिलने से रोकने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने की अनुमति दी जा सकती है? याचिका में कहा गया है कि खान को सुरक्षा अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बिना देश में स्वतंत्र रूप से आने-जाने और शैक्षणिक कार्यों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। एक तरह से यह स्थिति उन्हें कैद में रखने जैसी है। बता दें कि पाकिस्तान में मौलिक अधिकारों के हनन की खबरें सामने आती रहती हैं।

बांग्लादेश बोला, पाक की हरकतों के कारण सार्क में आया ठहराव

- विदेश मंत्री ने बिम्सटेक और बीबीआइएन जैसे क्षेत्रीय पहल के बेहतर करने की उम्मीद जताई
- कहा -भारत के साथ पाकिस्तान के दुश्मनी वाले व्यवहार के कारण फलफूल नहीं रहा संगठन

ढाका, प्रेट्र : पाकिस्तान की भारत के साथ दुश्मनी की प्रवृत्ति ही वह कारण है जिससे सार्क की गतिविधियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसी वजह से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यह संगठन फलफूल नहीं पा रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने उक्त बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बिम्सटेक और बीबीआइएन जैसे अन्य क्षेत्रीय पहलों के बेहतर करने की उम्मीद जाहिर की।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने के बाद की है। नवंबर में दोनों देशों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय की कमी का आरोप एक दूसरे पर मढ़ा था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की मेजबानी में आयोजित 'विजिट नेपाल-बांग्लादेश प्रोग्राम 2019' के समापन समारोह में विदेशी पत्रकारों के साथ बातचीत में मोमेन ने कहा कि भारत के साथ दुश्मनी साधने में जुटे पाकिस्तान के कारण सार्क का विकास ठहर गया है। उन्होंने कहा, 'आप जान लें कि सार्क क्यों फलफूल नहीं रहा। उसका मुख्य कारण भारत के साथ पाकिस्तान का दुश्मनी वाला व्यवहार है।'

बांग्लादेश के विदेश मंत्री की सार्क पर टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद आई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सार्क देशों के बीच भारत के व्यापक सहयोग के प्रयास को बार-बार आतंकवादी कार्रवाई और खतरे से चुनौती दी जाती रही है। सार्क सचिवालय को स्थापना दिवस के संबंध में लिखे गए एक पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा था, 'क्षेत्र के सभी देश आतंकवाद को पराजित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और सब इसका समर्थन करें।' उनका सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रयास मजबूत सार्क बनाने के लिए व्यापक भरोसा और आत्मविश्वास पैदा करेगा।

पिछले तीन साल से भारत सार्क से दूरी बनाए हुए है। इसके लिए नई दिल्ली ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा चुनौती को कारण बताया है। पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य है।

पिछला सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था जिसमें मोदी ने भाग लिया था। 2016 का सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था, लेकिन जम्मू एवं कश्मीर में उड़ी में सेना के शिविर

एके अब्दुल मोमेन। फाइल

पर उसी वर्ष 18 सितंबर को हुए हमले के बाद भारत ने भाग लेने में असमर्थता जताई थी। बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी भाग लेने से इन्कार कर दिया था। सार्क शिखर सम्मेलन हर दो साल बाद आयोजित किया जाता है। वर्णक्रम के अनुसार सदस्य देश मेजबान बनते हैं। मेजबान सदस्य देश सम्मेलन की अध्यक्षता करता है।

सार्क क्या है: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर की थी। संघ के 14 वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान में इसमें शामिल हुआ था।

संगठन के उद्देश्य : दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के साथ-साथ सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करना। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना। आपसी विश्वास, एक दूसरे समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाना। आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना।

न्यूज गैलरी

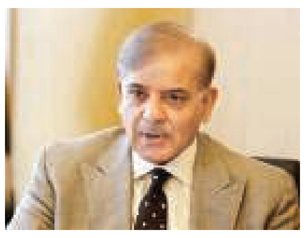
शरबाज शरीफ। फाइल

शहबाज को सात जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

इस्लामाबाद : हाउसिंग प्रोजेक्ट में अनियमितता के मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के मुख्य विपक्षी दल पीएमएल-एन के प्रमुख शहबाज शरीफ को हाजिर होने का अंतिम मौका दिया है। अनुपस्थित चल रहे शहबाज शरीफ को जवाबदेही ब्यूरो की एक अदालत ने अगले सात जनवरी को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश सुनाया। वह फिलहाल अपने बड़े भाई व पूर्व पीएम नवाज शरीफ के इलाज के लिए लंदन में हैं। (एएनआइ)

रूस की हिरासत से जापानी मछुआरे हुए रिहा

टोक्यो : जापान के प्रधान कैबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा ने मंगलवार को बताया कि रूस ने अपने कब्जे से पांच नावों सहित 24 जापानी मछुआरों को रिहा कर दिया है। उन्होंने बताया कि सभी लोग सही-सलामत हैं। पिछले हफ्ते रूस ने अपने कब्जे वाले कुरील द्वीपों के पास मछली पकड़ने आए जापान के मछुआरों को हिरासत में ले लिया था। जापान इन द्वीप समूहों पर अपने अधिकार की बात कहता है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच काफी समय से मतभेद हैं। (रायटर)

रूस का लड़ाकू विमान सुखोई-57 दुर्घटनाग्रस्त

मॉस्को : रूस के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को परीक्षण के दौरान उनका एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई-57 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना से पहले हालांकि पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। दुर्घटना के कारणों का अभी कोई पता नहीं चला है। सुखोई-57 रूस का सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन है, जिसकी तुलना अमेरिका के एफ-22 रैप्टर लड़ाकू विमान से की जाती है। (एपी)

इंडोनेशिया में खाई में गिरी बस, 26 की मौत

बैंकॉक : इंडोनेशिया के दक्षिण सुमात्रा में सोमवार देर रात एक बस 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसमें सवार 26 लोगों की मौत हो गई। घटना में 13 घायल बताए गए हैं। दुर्घटना के वक्त बस बेंगकुलु से पालेमबांग जा रही थी। रास्ते में मोड़ पर एक तरफ टक्कर खाने के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। (आइएएनएस)

'महाभियोग मामले में गवाहों को बुलाने से इन्कार नहीं'

रखी बात ▶ मैककोनेल ने नई गवाही लेने की जल्दी नहीं होने के दिए संकेत

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैककोनेल ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया की सुनवाई के दौरान गवाहों को बुलाने से इन्कार नहीं किया है। मैककोनेल ने हालांकि संकेत दिया कि उन्हें नई गवाही लेने की कोई जल्दी नहीं है। संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने हाल में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पास किया है। वह अमेरिकी इतिहास में तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई है।

प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने सीनेट को महाभियोग से जुड़े दस्तावेज सौंपने के बारे में सोमवार को कहा, 'सदन महाभियोग से जुड़े प्रबंधकों को तब तक नहीं चुन सकता जब तक हमें यह नहीं पता हो कि सीनेट किस तरह की सुनवाई करना चाहता है।' इस पर केंटकी से रिपब्लिकन सांसद मैककोनेल ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, पेलोसी का यह बयान स्पष्ट रूप से हमें यह बताने की कोशिश है कि

अमेरिका में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैककोनेल की फाइल फोटो। रायटर

महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाए? फिलहाल इस पूरे मामले में गतिरोध है। हम तब तक इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष हमें कागजात नहीं सौंप देतीं।

राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ में बिडेन की बढ़त बरकरार

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बनने के लिए मैदान में उतरे नेताओं में जो बिडेन की बढ़त बरकरार है। डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों के बीच कराए गए हालिया सर्वे में पूर्व उप राष्ट्रपति बिडेन 31 फीसद मत के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। यह दिसंबर के पहले सप्ताह में कराए गए सर्वे से दो अंक अधिक है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से अब भी एक दर्जन से ज्यादा नेता उम्मीदवारी की होड़ में हैं। बिडेन के बाद 21 फीसद मतों के साथ सीनेटर बर्नी सैंडर्स दूसरे स्थान पर हैं। इस रेस में तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः सीनेटर एलिजाबेथ वारेन व मेयर पीट बुटीग हैं।

सीरिया की समस्या पर बात करेंगे रूस और तुर्की

अंकारा, रायटर : सीरिया में असद सरकार और उसकी सहयोगी रूसी सेना के हमलों से उपजे हालात पर चर्चा के लिए तुर्की का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को रूस पहुंचा। सीरिया से बड़े पैमाने पर पलायन का मुद्दा इस वार्ता के मुख्य एजेंडे में शामिल है।

असद सरकार ने रूसी सेना की मदद से सीरिया के इदलिब प्रांत में विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर तुर्की की ओर जा रहे हैं। इससे चिंतित तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने बीते रविवार को कहा था कि उनका देश अब और शरणार्थियों को जगह देने में सक्षम नहीं है।

युद्ध के चलते सीरिया से भागे 37 लाख लोगों ने पहले ही तुर्की में शरण ले रखी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी है। तुर्की स्थित मानवाधिकार संगठन ने सोमवार को कहा कि ताजा हालात के कारण सीरिया से करीब एक लाख बीस हजार लोग तुर्की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। बता दें कि इदलिब प्रांत में विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाकों में रूसी सेना के हमलों के बाद हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। अब तक हजारों लोगों ने तुर्की में शरण ली है, लेकिन तुर्की लोगों को शरण देने में असमर्थता जता रहा है।

फ्लोरिडा में तूफान का कहर

फ्लोरिडा में आए भीषण तूफान और 12 इंच से ज्यादा बारिश के बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोग नावों के जरिये अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं। तूफान के कारण हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोमवार को उड़ानों का संचालन भी बंद करना पड़ा। एएफपी

'पुलवामा' के बाद की थी भारत-पाक तनाव दूर करने की कोशिश : चीन

- चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पर्दे की पीछे निभाई भूमिका को किया उजागर

बीजिंग, प्रेट्र : पुलवामा आतंकी हमले के बाद चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता के जरिये तनाव और मतभेद कम करने के प्रयासों में मदद की थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अब अपने देश की पर्दे के पीछे से निभाई गई इस भूमिका को उजागर किया है।

चीन में सत्तारूढ़ कम्यूनिस्ट पार्टी के आधिकारिक समाचार पत्र 'पीपुल्स डेली' को दिए साक्षात्कार में वांग यी ने 2019 में चीन की कूटनीतिक उपलब्धियों के बारे में बताया है। इसी क्रम में वांग यी ने पुलवामा हमले का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था तो चीन ने अपने विदेश उपमंत्री कोंग झुआनयू को पाकिस्तान भेजकर उसे संयम बरतने के लिए समझाया था। वांग के इस साक्षात्कार की प्रतियां चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया को वितरित कीं। इसमें वांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच चेन्नई में हुई दूसरी अनौपचारिक वार्ता का जिक्र करते हुए कहा, 'हमने अपने पड़ोसियों के साथ समग्र रूप से संबंधों में सुधार और विकास किया है। राष्ट्रपति चिनफिंग और

चीन के विदेश मंत्री वांग यी। फाइल/एएफपी

प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में दूसरी सफल शिखर बैठक की और चीन-भारत संबंधों के सतत विकास का मार्ग प्रशस्त किया।' इससे पहले 13 दिसंबर को '2019 में चीन की कूटनीति' विषय पर एक संगोष्ठी में भी वांग ने कहा था कि चेन्नई शिखर बैठक ने भारत-चीन संबंधों के सतत और मजबूत विकास की टोन तय कर दी थी। साक्षात्कार में वांग यी ने आगे कहा कि पिछले एक साल में चीन ने पड़ोसियों के साथ संबंधों को समग्र रूप से मजबूत किया है और क्षेत्रीय स्थिरता व विकास को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान दिया है।

चीनी विदेश मंत्री ने कहा, 'अफगानिस्तान पर अपनी कूटनीति के तहत चीन ने अंतर अफगान, चीन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान और चीन-रूस-अमेरिका वार्ता में सहायता की और पहली चीन-रूस-अमेरिका-पाकिस्तान वार्ता का आयोजन किया।' रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में वांग यी ने कहा, 'चीन ने म्यांमार और बांग्लादेश के बीच उनके लंबित मुद्दों के समाधान के लिए वार्ता को बढ़ावा में मध्यस्थ की भूमिका निभाई।' उन्होंने चीन और जापान के बीच रिश्तों में सुधार को लेकर भी बात की। हाल के समय में पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव रहा है। वांग यी ने कहा कि चीन और जापान द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के लिए 10 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं ताकि रिश्ते सही ट्रैक पर लौट सकें। साथ ही चीन और आसियान देशों ने विवादित दक्षिण चीन सागर के मसले पर खासी प्रगति की है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है।

बीजीबी के सामने जवान की हत्या का मुद्दा उठाएगा बीएसएफ

- अक्टूबर में बांग्लादेश की तरफ से फायरिंग में शहीद हुआ था जवान
- आज से छह दिन की भारत यात्रा पर आ रहा है बीजीबी का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, प्रेट्र : बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को भारत की यात्रा पर आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) प्रतिनिधिमंडल के सामने अपने एक जवान की बांग्लादेश की तरफ से की गई फायरिंग में मौत के मुद्दे को उठाएगा। बीएसएफ जवान की शहादत के बाद बांग्लादेश का यह पहला शीर्ष स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है, जो भारत के दौरे पर आ रहा है।

बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय दल छह दिन की यात्रा पर भारत आ रहा है। बीएसएफ के दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित कैंप में दोनों पक्षों के बीच 26 दिसंबर से बातचीत शुरू होगी। 10 सदस्यीय बीएसएफ के दल का नेतृत्व उसके महानिदेशक वीके जौहरी करेंगे। इसमें गृह और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ अपने हेड कांस्टेबल विजय भान सिंह की हत्या और कांस्टेबल राजवीर यादव के घायल होने के मसले को बीजीबी के दल के सामने सख्ती के साथ उठाएगा। पश्चिम बंगाल के मर्शिदाबाद जिले में ककमारीचार सीमा चौकी के पास अक्टूबर में बीजीबी की फायरिंग में हेड कांस्टेबल विजय भान सिंह शहीद हो गए थे। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच दशकों से सीमा पर फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई है। बीजीबी की तरफ से बताया गया है कि जिस जवान ने फायरिंग की थी, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया था, उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू की गई है।

नेपाल में 122 चीनी नागरिक हिरासत में

काठमांडू, रायटर : नेपाल की पुलिस ने पर्यटक वीजा पर आए 122 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इन लोगों पर साइबर अपराध को अंजाम देने के साथ बैंक की कैश मशीनों को हैक करने का भी संदेह है। राजधानी काठमांडू के पुलिस प्रमुख उत्तम सूबेदी ने सोमवार को कहा कि पकड़े गए सभी लोगों के पासपोर्ट और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। नेपाल में संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों के आरोप में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है।

नेपाल पुलिस की कार्रवाई पर चीनी दूतावास ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। नेपाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होबिंद्र बोगाटी ने हालांकि बताया कि चीनी दूतावास को इस कार्रवाई के बारे में पता था और उसने संदिग्धों को हिरासत में लेने का समर्थन किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, इस मामले में चीन और नेपाल की पुलिस संपर्क में है। चीन अपने पड़ोसी के साथ पूरी तरह सहयोग करने के

पर्यटक वीजा पर नेपाल आए चीनी नागरिकों (चेहरा छिपाए) को हिरासत में लेकर काठमांडू में मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। एपी

लिए तैयार है। नेपाल में इससे पहले सितंबर में बैंक की कैश मशीनों को हैक कर रकम निकालने के आरोप में पांच चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। इस साल सोने की तस्करी के आरोप में भी चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गत अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपराधिक मामलों में एक-दूसरे की मदद करने के करार पर हस्ताक्षर किए थे। हाल के वर्षों में नेपाल में चीन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। चीन ने नेपाल के कई क्षेत्रों सड़क, ऊर्जा और अस्पतालों में हजारों करोड़ का निवेश कर रखा है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अक्टूबर तक एक लाख 34 हजार चीनी पर्यटक नेपाल आए। जो पिछले साल की तुलना में 9.2 फीसद अधिक है।

जापान में पहली बार एक साल में जन्मे नौ लाख से भी कम बच्चे

- द्वीपीय देश की मौजूदा आबादी करीब 12.68 करोड़ है

टोक्यो, रायटर : घटती आबादी की समस्या से जूझ रहे जापान में इस साल नौ लाख से भी कम शिशुओं का जन्म हुआ। जापान के जनकल्याण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 में देश में सिर्फ आठ लाख 64 हजार बच्चों ने जन्म लिया। देश में 1899 से जनसंख्या संबंधी आंकड़े जुटाने की व्यवस्था शुरू हुई थी, तब से यह शिशु जन्म का सबसे कम आंकड़ा है। वर्ष 2018 में देश में नौ लाख 18 हजार चार सौ बच्चे जन्मे थे।

ताजा आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जापान में इस साल जन्म की तुलना में मौत का आंकड़ा पांच लाख 12 हजार ज्यादा रहा। यह भी जन्म और मृत्यु में अब तक का सबसे बड़ा अंतर है। घटती जनसंख्या की चिंता के बीच जापान सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस साल जन्मदर पिछले साल के 1.42 प्रतिशत से कुछ अधिक 1.8 प्रतिशत रहेगी। जापान की मौजूदा आबादी करीब 12.68 करोड़ है।

तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की संख्या : जापान की आबादी बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका असर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जापान में ज्यादातर युवा शादी से भी इन्कार कर रहे हैं। कम बच्चे और कम युवा आबादी देश के लिए संकट बनी हुई है। इसके चलते शादीशुदा महिलाओं को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है ताकि जनसंख्या बढ़ा सके और देश की जन्म दर भी बढ़ सके। एक अनुमान के मुताबिक, यदि आगामी वर्ष जापान में जन्मदर के आंकड़ों में वृद्धि नहीं हुई तो इससे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आने वाले दशकों में प्रभावित हो सकती है।

मैं लिवरपूल के मैनेजर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। ऐसे में मैं उनसे मिलने को लेकर काफी उत्सुक हूं।
— फाफ डुप्लेसिस, दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान

पियरे व कार्लोविक करेंगे टाटा ओपन से वापसी

पुणे : फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी और विश्व रैंकिंग में 24वें पायदान पर काबिज बेनोइट पियरे टाटा ओपन महाराष्ट्र में आकर्षण का केंद्र होंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गत चैंपियन केविन एंडरसन तीन फरवरी से शुरू हो रही भारत की एकमात्र एटीपी 250 प्रतियोगिता में अपने खिताब का बचाव करने नहीं आएंगे। पिछले सत्र के उप विजेता इवो कार्लोविक टूर्नामेंट के तीसरे सत्र में वापसी करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत क्रिकेटर फिलिप ह्यूज अगर आपको याद होंगे तो उन्हीं के देश के तेज गेंदबाज सीन एबॉट का नाम भी आपको अच्छे से याद होगा। 2014 में सीन के बाउंसर से ही ह्यूज को चोट लगी थी जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। एक महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण करने के बाद ही घटी उस घटना के बाद सीन पूरी तरह से टूट गए थे। पांच साल बाद सीन ने राष्ट्रीय टीम में वापसी की और वह भारत में तीन वनडे खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा हैं। वह अगले टी-20 विश्व कप और ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का सपना देख रहे हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेल रहे 27 वर्षीय सीन एबॉट से अभिषेक त्रिपाठी ने उनके करियर से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की। पेश है उस बातचीत के प्रमुख अंश :

अगले साल टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बनाना इस तेज गेंदबाज का लक्ष्य

भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करूंगा : सीन एबॉट

साक्षात्कार

● पिछले महीने आपने पांच साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टी-20 टीम में वापसी की। आपके लिए राष्ट्रीय टीम में यह वापसी कितनी मुश्किल रही?

-हमेशा से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी करना मुश्किल होता है। पिछले कुछ वर्षों से मैं टी-20 प्रारूप में अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूं। इस दौरान मैंने अपने खेल में सुधार पर काफी ध्यान दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल खिलाड़ी भी इस समय अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय टीम में वापसी आसान नहीं थी। फिलहाल मेरी कोशिश न्यू साउथ वेल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर है।

● भारत दौरे पर आने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में आप शामिल हैं। क्या आपने विराट और उनकी टीम से निपटने के लिए कोई खास रणनीति बनाई है ?

-अभी तक कुछ खास रणनीति नहीं बनाई है। अभी हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा खेलने और नेट्स पर समय बिताने पर है। मुझे अभी बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए अहम भूमिका निभानी है। मैं इस दौरान दिन-ब-दिन अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल मेरी पूरी कोशिश घरेलू लीग में अच्छा प्रदर्शन करने पर है और उम्मीद है कि भारत में मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। भारतीय टीम काफी मजबूत है।

● बिग बैश लीग में कई नामी खिलाड़ी आपकी टीम सिडनी सिक्सर्स में शामिल हैं। आपके और टीम के क्या लक्ष्य हैं ?

-हमारा लक्ष्य हर मुकाबला जीतने के साथ-साथ 2011 में हुए बिग बैश लीग के पहले संस्करण की तरह फाइनल जीतना भी है। मौजूदा सत्र में राष्ट्रीय टीम में शामिल कई खिलाड़ी चोट के डर से ज्यादा मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। हालांकि फिर भी हमारी कोशिश प्रबल दावेदार नहीं होने के बावजूद खिताब जीतने की है। मेरे व्यक्तिगत लक्ष्य की बात करें तो मेरे दिमाग में अगला टी-20 विश्व कप है लेकिन अभी उसमें काफी समय है। भारत दौरे पर भी जाने में अभी वक्त है। ऐसे में मेरी नजर अभी आनेवाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने पर है। खासतौर से बॉक्सिंग डे पर पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ बिग बैश लीग में अच्छा प्रदर्शन करने पर है।

● इंडियन प्रीमियम लीग और बिग बैश लीग युवा खिलाड़ियों के लिए कितनी जरूरी है?

-मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ियों की इन लीगों काफी अहम भूमिका है। यहां इन युवा खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। साथ ही इस लीग में खिलाड़ियों के उनके परिवार वालों को मैदान में आकर मैच देखने का भी मौका मिलता है। यह एक रोचक प्रारूप है और इस लीग में हमारे देश के कई बड़े खिलाड़ी अपना खेल दिखाते हैं।

● 2020 के लिए आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

-निश्चित तौर पर मेरी कोशिश अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बनाने की होगी। देश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में मुझे उनसे अच्छी चुनौती मिलने की आशा है। हालांकि मेरी कोशिश अभी बिग बैश लीग में अच्छा प्रदर्शन करने पर है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है।

● आप ऑस्ट्रेलिया के लिए टी-20 और वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं लेकिन आपको अब तक बैगी ग्रीन नहीं मिली है। आपका पसंदीदा प्रारूप कौन सा है?

-टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरा सपना है। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मेरे पसंदीदा प्रारूप की बात करें तो मुझे चार दिवसीय क्रिकेट मैच खेलना बेहद पसंद है क्योंकि अभी तक मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है लेकिन उम्मीद है कि मेरा यह सपना एक दिन जरूर पूरा होगा।

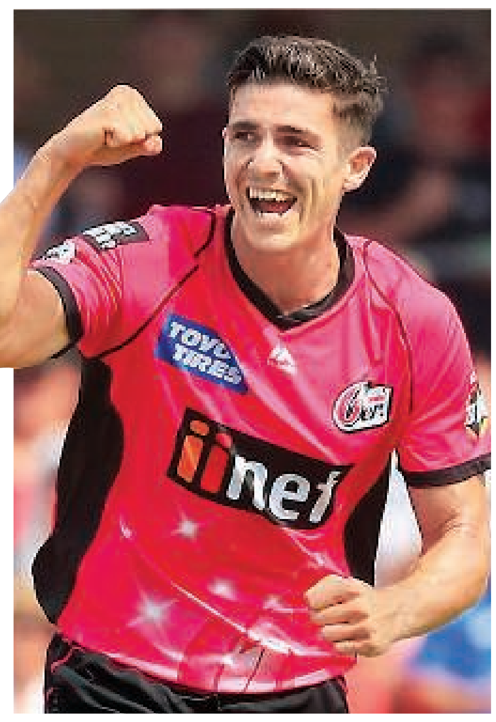

बिग बैश लीग में गेंदबाजी के दौरान सीन एबॉट ● फाइल फोटो, ट्विटर

एक नजर में

हरभजन सिंह ने उठाए चयनकर्ताओं पर सवाल

नई दिल्ली : श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा के बाद हरभजन सिंह ने सीनियर चयन समिति पर सवाल खड़े किए हैं। हरभजन ने मुंबई के सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम में नहीं चुनने पर चयनकर्ताओं को कोसा है। मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सूर्यकुमार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टूर मैचों और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत-ए टीम में जगह मिली थी, लेकिन राष्ट्रीय टीम में उनका नाम नहीं देखकर हरभजन भड़क गए। हरभजन ने ट्वीट किया कि मुझे हैरानी हो रही है कि सूर्यकुमार ने क्या गलत किया है? भारतीय टीम, भारत-ए, भारत-बी में चुने गए बाकी खिलाड़ियों की तरह उन्होंने भी रन किए हैं तो उनके साथ अलग सलूक क्यों हो रहा है। सूर्यकुमार ने 73 प्रथम श्रेणी मैचों में 4920 रन बनाए हैं। (आइएएनएस)

नसीम को नहीं भेजें अंडर-19 विश्व कप में : हफीज

लाहौर : पाकिस्तानी क्रिकेटर मुहम्मद हफीज का मानना है कि नसीम शाह को अगले महीने शुरू हो रहे अंडर-19 यूथ विश्व कप में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वह पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और उन्हें इस स्तर के लिए तकनीकी और शारीरिक तौर पर बेहतर होने की जरूरत है। शाह ने पिछले महीने ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने उन्हें अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में खेले जाने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए टीम में चुना है। यह विश्व कप 17 जनवरी से नौ फरवरी के बीच खेला जाएगा। हफीज ने ट्वीट किया कि जूनियर चयन समिति से एक मांग है वह नसीम शाह को अंडर-19 विश्व कप के लिए नहीं भेजें। वह पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं और उन्हें तकनीकी तथा शारीरिक रूप से मेहनत करने की जरूरत है ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हो सकें। (प्रेट्र)

बाल्डर्सन करेंगे अंडर-19 विश्व कप में कप्तानी

लंदन : लंकाशायर के गेंदबाजी ऑलराउंडर जॉर्ज बाल्डर्सन को अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर-19 विश्व कप में इंग्लैंड टीम की कप्तानी सौंपी गई है। यह विश्व कप 17 जनवरी से नौ फरवरी तक खेला जाएगा। इंग्लैंड के मुख्य कोच जॉन लुइस ने कहा कि मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि टीम विश्व कप में कैसा प्रदर्शन करती है। टीम के लिए यह टूर्नामेंट बड़ी चुनौती होगा। **इंग्लैंड टीम :** बाल्डर्सन (कप्तान), एलड्रिज, बेन चार्ल्सवर्थ, हैरी ड्यूक, जॉर्डन एविंसन, लुइस गोल्डसवर्थी, जैक हैंस, ज्यॉर्ज हिल, डैन मौस्ले, कादरी, सैम यंग। (आइएएनएस)

ला लीगा के अध्यक्ष बने तेबास

मैड्रिड : जेवियर तेबास को तीसरी बार स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का अध्यक्ष चुना गया है। वह अगले चार साल तक इस पद पर रहेंगे। तेबास ने पिछले साल दिसंबर में पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में कहा था कि वह इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। सोमवार को उनके अध्यक्ष बनने की घोषणा की गई। वह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। ला लीगा की ओर से कहा गया, 'ला लीगा के अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नाम आया और यह नाम सही तरीके से सामने आया। इसलिए जेवियर तेबास को अगले चार साल के लिए चुना गया, वह भी बिना अतिरिक्त आम सभा के।' (प्रेट्र)

10 साल बेमिसाल

● भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के लिए स्वर्णिम साबित हुए हैं पिछले 10 वर्ष
● 2010-19 में खेल के हर क्षेत्र में जमाया भारतीय खिलाड़ियों ने अपना कब्जा

निखिल शर्मा ● नई दिल्ली

पिछली सदी का आठवां और नौवां दशक कैरेबियाई क्रिकेट के लिए जाना जाता है। इस सदी के पहले दशक में ऑस्ट्रेलियाई टीम का कब्जा रहा। ये वो समय था जब भारतीय टीम के खिलाड़ी इन दोनों टीम के खिलाफ घुटने टेक देते थे। 1983 का विश्व कप जीतकर जो उम्मीद कपिल देव ने दिखाई थी वो अब जाकर पूरी हुई। विश्व क्रिकेट में पिछले 10 साल (2010-19) भारतीय टीम के नाम रहे हैं। रहा। खेल के अधिकतर हर क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ी अव्वल साबित हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धौनी ने इस दशक की शुरुआत में टीम इंडिया को नई राह दिखाई तो दशक के अंत तक विराट कोहली ने इस टीम को दुनिया का सबसे बड़ा निडर योद्धा बना डाला।

कोहली सब पर भारी : 2010 से पहले दुनिया ने डेसमंड हैंस, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग जैसे खिलाड़ियों को देखा लेकिन पिछले 10 वर्षों को विराट कोहली ने अपना बना लिया। पोंटिंग ने 2000-09 के 10 साल के काल में 9103 रन बनाए थे। पिछले 40 सालों में वनडे में उनके अलावा ऐसा कोई नहीं कर पाया था लेकिन विराट कोहली ने 2010-19 में इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर दिया। वह पिछले 10 वर्ष के काल में वनडे में सबसे ज्यादा 11125 रन बनाने वाले दुनिया के खिलाड़ी बने। एक दशक में उनके अलावा वनडे में इतने रन कोई नहीं बना पाया है।

गेंदबाजी में जगी भविष्य की उम्मीद : पिछले 50 वर्षों की बात करें तो भारतीय क्रिकेट के लिए 1980 से 1989 का दौर गेंदबाजी के लिहाज से शानदार माना जाता रहा है। उस दौर में कपिल देव ने सबसे ज्यादा 168 विकेट चटकाए थे, लेकिन इसके बाद वसीम अकरम, मुथैया मुरलीधरन और फिर लसिथ मलिंगा का युग रहा। वसीम ने अपनी स्विंग से, मुरलीधरन ने अपनी स्पिन से और पिछले 10 वर्षों में 248 विकेट लेने वाले मलिंगा ने अपनी यॉर्कर से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया। भारतीय गेंदबाजी में जहीर खान का दौर इस दशक में ही समाप्त हुआ और इसके बाद अन्य भारतीय गेंदबाज इस दौर में टीम में स्थापित हुए। 2019 के अंत तक भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी आक्रामक हो गई है और उम्मीद है अगले 10 वर्षों में बुमराह या कुलदीप जैसे गेंदबाज दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेकर शीर्ष पर पहुंचेंगे।

मिला सर्वश्रेष्ठ कप्तान और विकेटकीपर : अगर पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धौनी के रूप में भारतीय क्रिकेट को ना सिर्फ एक दिग्गज विकेटकीपर मिला, बल्कि एक ऐसा कप्तान भी मिला जिसने भारतीय युवाओं को सपने देखना सिखाया। तीन वर्ष पहले सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ने के बावजूद भी पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने हैं। तीन आइसीसी ट्रॉफी (2007 टी-20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी) जीतने वाले दुनिया के अकेले कप्तान धौनी ने इस दौर में सबसे ज्यादा 71 वनडे मुकाबले जीते। वहीं विकेटकीपिंग में भी वेस्टइंडीज के जेफ डुजोन, ऑस्ट्रेलिया के इयान हिली, ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गजों की फहरिस्त में अपना नाम शुमार करा लिया। धौनी ने पिछले 10 वर्षों में वनडे में सबसे ज्यादा 242 स्टंप और कैच पकड़े।

रोहित-धवन बने गांगुली-सचिन के उत्तराधिकारी : भारतीय क्रिकेट के लिए सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे ओपनर की भरपाई करना आसान नहीं था। ये जोड़ी अलग भी हुई और कभी गौतम गंभीर तो उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने इस स्थान पर जगह बनाई, लेकिन कोई भी गांगुली-सचिन की सलामी जोड़ी को नहीं भूल सकता है। पिछले 10 वर्षों में रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी वनडे में गांगुली-सचिन की उत्तराधिकारी बनी। इन दोनों ने वनडे में सबसे ज्यादा 4753 रन बनाए। इस जोड़ी ने वनडे में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से ही एक साथ भारत के लिए ओपनिंग करना शुरू किया।

अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय टीम के सदस्य भुवनेश्वर कुमार, मुहम्मद शमी, कप्तान विराट कोहली, धौनी और हार्दिक पांड्या ● फाइल फोटो, एपी

पिछले 50 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ वनडे विकेटकीपर

दशक	विकेटकीपर	देश	स्टंप/कैच
1970-79	रॉड मार्श	ऑस्ट्रेलिया	35
1980-89	जैफ डुजोन	वेस्टइंडीज	181
1990-99	इयान हिली	ऑस्ट्रेलिया	212
2000-09	गिलक्रिस्ट	ऑस्ट्रेलिया	362
2010-19	धौनी	भारत	242

50 वर्षों में सबसे ज्यादा वनडे जीतने वाली टीम

दशक	टीम	जीत
1970-79	इंग्लैंड	27
1980-89	वेस्टइंडीज	122
1990-99	पाकिस्तान	146
2000-09	ऑस्ट्रेलिया	202
2010-19	भारत	157

2010-19 में प्रत्येक देश के सबसे सफल वनडे गेंदबाज

गेंदबाज	देश	विकेट
मिशेल स्टार्क	ऑस्ट्रेलिया	172
शाकिब	बांग्लादेश	177
क्रिस वोक्स	इंग्लैंड	142
रवींद्र जडेजा	भारत	171
ट्रेंट बोल्ट	न्यूजीलैंड	164
सईद अजमल	पाकिस्तान	157
इमरान ताहिर	द. अफ्रीका	173
लसित मलिंगा	श्रीलंका	248
जेसन होल्डर	वेस्टइंडीज	133

2010-19 में प्रत्येक देश के सबसे सफल बल्लेबाज

बल्लेबाज	देश	रन
डेविड वार्नर	ऑस्ट्रेलिया	4884
मुशफिकुर रहीम	बांग्लादेश	5178
इयोन मोर्गन	इंग्लैंड	6241
विराट कोहली	भारत	11125
रॉस टेलर	न्यूजीलैंड	6428
मुहम्मद हफीज	पाकिस्तान	5740
हाशिम अमला	द. अफ्रीका	7265
कुमार संगकारा	श्रीलंका	6356
मर्लोन सैमुअल्स	वेस्टइंडीज	3093

2010-19 का वनडे का सर्वाधिक स्कोर

स्कोर	टीम	बनाम	वर्ष
481/6	इंग्लैंड	ऑस्ट्रेलिया	2018
444/3	इंग्लैंड	पाकिस्तान	2016
439/2	द. अफ्रीका	वेस्टइंडीज	2015
438/4	द. अफ्रीका	भारत	2015
418/5	भारत	वेस्टइंडीज	2011
418/6	इंग्लैंड	वेस्टइंडीज	2019

50 वर्षों के सबसे सफल बल्लेबाज

दशक	बल्लेबाज	देश	रन
1970-79	ग्रेग चैपल	ऑस्ट्रेलिया	919
1980-89	डेसमंड हैंस	वेस्टइंडीज	5892
1990-99	तेंदुलकर	भारत	8571
2000-09	रिकी पोंटिंग	ऑस्ट्रेलिया	9103
2010-19	विराट कोहली	भारत	11125

50 वर्षों के सबसे सफल गेंदबाज

दशक	गेंदबाज	देश	विकेट
1970-79	क्रिस ओल्ड	इंग्लैंड	41
1980-89	कपिल देव	भारत	168
1990-99	वसीम अकरम	पाक	279
2000-09	मुरलीधरन	श्रीलंका	335
2010-19	लसित मलिंगा	श्रीलंका	248

50 वर्षों की शीर्ष वनडे जोड़ी

दशक	जोड़ी	देश	रन
1970-1979	माजिद-सदिक	पाकिस्तान	528
1980-1989	ग्रीनिज-हैंस	वेस्टइंडीज	4524
1990-1999	सोहेल-अनवर	पाकिस्तान	3397
2000-2009	गिलक्रिस्ट-हेडन	ऑस्ट्रेलिया	5409
2010-2019	रोहित-धवन	भारत	4753

50 वर्षों में सबसे सफल वनडे कप्तान

दशक	कप्तान	देश	जीत
1970-79	क्लाइव लॉयड	वेस्टइंडीज	14
1980-89	विवियन रिचर्ड्स	वेस्टइंडीज	64
1990-99	अजहरुद्दीन	भारत	90
2000-09	रिकी पोंटिंग	ऑस्ट्रेलिया	145
2010-19	एमएस धौनी	भारत	71

2010-19 में वनडे के सर्वोत्तम आंकड़े

1970 79 में 82, 1980-89 में 516, 1990-99 में 933, 2000-09 में 1405 और 2010-19 में 1287 वनडे खेले गए

2010 19 के बीच छह बार सबसे ज्यादा नर्वस नाइंटीज में आउट हुए न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। इसके बाद विराट कोहली, रॉस टेलर और ग्लेन मैक्सवेल 5-5 बार आउट हुए

227 वनडे इस दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने खेले। इसके बाद एमएस धौनी व श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज (196-196), इंग्लैंड के इयोन मोर्गन (195) और रोहित शर्मा (180) रहे

233 छक्के रोहित शर्मा ने वनडे में लगाए। इस दौरान इयोन मोर्गन ने 183, क्रिस गेल ने 180, एबी डिविलियर्स ने 155 और मार्टिन गुप्टिल ने 153 छक्के लगाए

35 मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में विराट कोहली ने जीते। इसके बाद मार्टिन गुप्टिल (21), एबी डिविलियर्स और रोहित शर्मा ने (20-20) रहे

264 रन सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर रहा, जो रोहित शर्मा ने बनाया। इसके बाद मार्टिन गुप्टिल (नाबाद 237) वीरेंद्र सहवाग (219), क्रिस गेल (215), फखर जमां (नाबाद 210) रहे

07 बार वनडे में मैन ऑफ द सीरीज बने विराट कोहली। इस मामले में इसके बाद हाशिम अमला (06), रोहित और केन विलियमसन (5-5) का नंबर आता है

12 रन देकर सात विकेट पिछले 10 वर्षों का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन रहा वनडे में, जो पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के नाम रहा। इसके अलावा राशिद खान, टिम साउथी, इमरान ताहिर ने भी एक पारी में सात विकेट लिए

बीसीसीआइ के चार देशों के टूर्नामेंट पर बात करेगा ईसीबी

लंदन, प्रेट्र : इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मंगलवार को चार देशों के प्रस्तावित टूर्नामेंट पर बीसीसीआइ के साथ चर्चा की बात स्वीकार की। इस टूर्नामेंट को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के हर साल एक बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने से रोकने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। आइसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम के इतर इस टूर्नामेंट के आयोजन की तैयारी की जा रही है।

बीसीसीआइ द्वारा प्रस्तावित इस वार्षिक टूर्नामेंट में तीन बड़े देशों (बिग थ्री) भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक और टीम हिस्सा लेगी। ईसीबी ने कहा, 'हम क्रिकेट खेलने वाले अन्य बड़े देशों के अधिकारियों से नियमित रूप से मिलते हैं जिससे कि हमने जो सीखा है उसे साझा किया जा सके और हमारे खेल को प्रभावित करने वाले विषयों पर चर्चा की जा सके। दिसंबर में बीसीसीआइ के साथ हुई बैठक में चार देशों के टूर्नामेंट का मुद्दा उठा था और हमने आइसीसी के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा का विकल्प खुला रखा है जिससे कि देखा जा सके कि इस कल्पना को साकार किया जा सकता है या नहीं।'

रणनीति

● हर साल चार देशों का नया टूर्नामेंट चाहता है भारत
● आइसीसी पर दबाव बनाना चाहते हैं भारत, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया

इस प्रस्तावित टूर्नामेंट की मेजबानी 2021 से बिग थ्री एक-एक करके करेंगे। हालांकि इसे लेकर अभी सब सहमत नहीं हैं। इस टूर्नामेंट से इसमें हिस्सा लेने वाले बोर्ड के राजस्व में इजाफे की उम्मीद है। आइसीसी तीन से अधिक टीमों के ऐसे किसी टूर्नामेंट को स्वीकृति नहीं देता जिसका आयोजन वह नहीं करता। गांगुली पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं।

उम्मीद चोट के बाद आगामी सीरीज के लिए चुने जाने पर बोले शिखर

मैं बल्लेबाजी करना नहीं भूला हूं : धवन

नई दिल्ली, प्रेट्र : अंगुली में फ्रैक्चर, गर्दन में सूजन, आंख और घुटने में चोट। शिखर धवन 2019 में चोटों से जूझते रहे लेकिन भारत का सलामी बल्लेबाज नई शुरुआत के लिए तैयार है और उन्होंने बता दिया है कि वह बल्लेबाजी करना नहीं भूले हैं। हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली की कमान संभालने वाले धवन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान घुटने में लगी चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं। घुटने की चोट के कारण धवन को 25 टांके लगे थे। धवन ने भले ही भारतीय टीम में वापसी की हो लेकिन उन्हें पता है कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में लोकेश राहुल की शानदार फॉर्म के कारण उनकी राह आसान नहीं होगी।

धवन ने यहां ट्रेनिंग सत्र के बाद कहा कि यह मेरे लिए नई शुरुआत है। पहले मेरी अंगुली में चोट लगी, फिर गर्दन में, आंख में और फिर घुटने पर टांके लगे। अच्छी खबर है कि नया साल आ रहा है। मुझे खुशी है कि राहुल ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। चोटों पर किसी का नियंत्रण नहीं है लेकिन धवन पर भी धवन ने कहा कि चोट लगना स्वाभाविक है। आपको यह स्वीकार करना होगा। यह ठीक है और मैं इसे लेकर हाय-तौबा नहीं मचाने वाला। उतार-चढ़ाव का मुझ पर असर नहीं पड़ता क्योंकि मैं बल्लेबाजी करना नहीं भूला हूं। मेरा स्तर स्थाई है और मैं रन बनाऊंगा। इस सलामी बल्लेबाज ने स्वीकार किया कि श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज उनके लिए काफी अहम होगी। इस सीरीज से रोहित शर्मा ने ब्रेक लिया है लेकिन आगामी वनडे सीरीज में तीनों सलामी बल्लेबाज उपलब्ध रहेंगे।

फिटनेस परखेंगे बुमराह, धवन

नई दिल्ली : भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की राष्ट्रीय टीम में वापसी के बाद रणजी ट्रॉफी में भी वापसी हुई है, जहां वे अपनी-अपनी टीमों के लिए खेलेंगे। बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई-अगस्त में खेली गई सीरीज से ही बाहर चल रहे थे। धवन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में घुटने में चोट लग गई थी और इसी कारण वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे तथा टी-20 सीरीज से बाहर हो गए थे। बुमराह को गुजरात की टीम में शामिल किया गया है। धवन और तेज गेंदबाज इशांत शर्मा की दिल्ली की टीम में वापसी हुई है। दिल्ली को अपना अगला मैच 25 से 28 तक अरुण जेटली स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ खेलना है।

आज से शुरू होने वाले रणजी मैच

बंगाल vs आंध्र प्रदेश	कोलकाता
मिजोरम vs पुडुचेरी	कोलकाता
झारखंड vs हरियाणा	जमशेदपुर
बिहार vs गोवा	पटना
सौराष्ट्र vs उत्तर प्रदेश	राजकोट
जे एण्ड के vs असम	जम्मू
दिल्ली vs हैदराबाद	दिल्ली
ओडिशा vs उत्तराखंड	कटक
कर्नाटक vs हि. प्रदेश	मैसुर
अरु. प्रदेश vs मणिपुर	दिब्रुगढ़
मुंबई vs रेलवे	मुंबई
विदर्भ vs पंजाब	नागपुर
गुजरात vs केरल	सूरत
म. प्रदेश vs तमिलनाडु	इंदौर
महाराष्ट्र vs छत्तीसगढ़	पुणे
सर्विसेज vs त्रिपुरा	दिल्ली
सिक्किम vs नागालैंड	भुवनेश्वर

टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली शीर्ष पर, रहाणे खिसके

दुबई, आइएएनएस : भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने आइसीसी की टेस्ट रैंकिंग में अपना पहला स्थान कायम रखा है। वहीं, मंगलवार को जारी रैंकिंग में भारतीय टीम के उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे को नुकसान हुआ है। कोहली के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन तीसरे नंबर पर काबिज हैं।

भारत के चेतेश्वर पुजारा चौथे स्थान पर हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशाने को पांचवां स्थान मिला है। कराची टेस्ट में शतकीय पारी खेलने वाले पाकिस्तान के बाबर आजम तीन स्थान आगे बढ़ते हुए छठे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने भारत के रहाणे को अपदस्थ किया है। रहाणे सातवें नंबर पर आ गए हैं। रहाणे के अलावा डेविड वार्नर और इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट को भी नुकसान हुआ है। वार्नर अब आठवें और रूट नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर आगे बढ़ते हुए 10वें नंबर पहुंच गए हैं। भारत के दो और बल्लेबाज मयंक अग्रवाल तथा रोहित शर्मा शीर्ष-20 में पहुंच गए हैं। मयंक 12वें और रोहित 15वें नंबर हैं।

गेंदबाजों में शीर्ष पर कमिंस : ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस आइसीसी की गेंदबाजों की रैंकिंग में 898 अंक लेकर शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके बाद द. अफ्रीका के रबादा 839 अंक लेकर दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड के वैगनर 834 अंक लेकर तीसरे स्थान पर काबिज हैं।

शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय गेंदबाज बुमराह
रोहित व मयंक को भी हुआ बल्लेबाजों की रैंकिंग में फायदा

शीर्ष पांच टेस्ट बल्लेबाज

बल्लेबाज	देश	रेटिंग
विराट कोहली	भारत	928
स्टीव स्मिथ	ऑस्ट्रेलिया	911
विलियमसन	न्यूजीलैंड	864
चेतेश्वर पुजारा	भारत	791
मार्नस लाबुशाने	ऑस्ट्रेलिया	786

शीर्ष पांच टेस्ट गेंदबाज

गेंदबाज	देश	रेटिंग
पैट कमिंस	ऑस्ट्रेलिया	898
कैगिसो रबादा	द. अफ्रीका	839
नील वैगनर	न्यूजीलैंड	834
जेसन होल्डर	वेस्टइंडीज	830
मिशेल स्टार्क	ऑस्ट्रेलिया	806

बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए फिट वार्नर : लैंगर

मेलबर्न, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से फिट हैं। वार्नर को यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी करते हुए अंगूठे पर गेंद लग गई थी। इसी मैदान पर दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। कोच ने कहा कि मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है।

यह मेरा आखिरी रणजी सत्र है। इस सत्र को खेलने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा।
– वसीम जाफर, भारतीय क्रिकेटर

विश्व क्रिकेट में कोहली और धौनी का डंका

उम्दा ▸ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की सर्वश्रेष्ठ टीमों के कप्तान विराट कोहली और एमएस धौनी

सिडनी, प्रेट्र : 2019 खत्म होने जा रहा है लेकिन विश्व क्रिकेट में वर्तमान कप्तान विराट कोहली के साथ-साथ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी का भी डंका बज रहा है। जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) की आधिकारिक वेबसाइट ने धौनी को दशक (2010-19) की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम और विराट को टेस्ट टीम का कप्तान चुना है तो वहीं क्रिकेट की बाइबल विजडन ने भी पिछले 10 सालों के लिए चुनी अपनी दोनों टीमों में भारतीय कप्तान को जगह दी है। कुछ दिन पहले विजडन ने दशक की वनडे टीम की भी घोषणा की थी जिसमें कोहली के अलावा धौनी और रोहित को स्थान दिया गया था।

रोहित को भी जगह : सीए की दशक की वनडे टीम में धौनी और कोहली के अलावा ओपनर रोहित शर्मा शामिल हैं। धौनी को इस टीम का विकेटकीपर और कप्तान चुना गया है। रोहित को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विराट तीसरे नंबर पर रखे गए हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी इस टीम में पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मिशेल स्टार्क ही इसमें जगह बना सके हैं।

विजडन में भी भारत का बोलबाला : विजडन की दशक की टेस्ट और वनडे दोनों टीमों में विराट कोहली को शामिल किया गया है। धौनी को सिर्फ वनडे टीम में जगह दी गई थी। मंगलवार को जारी टेस्ट टीम में कोहली के अलावा ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का भी नाम है। कोहली ने 94 टेस्ट में 54.97 की औसत से 7202 रन बनाए। इस दौरान 27 शतक और 25 अर्धशतक लगाए। अश्विन ने 70 टेस्ट में 362 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 27 बार एक पारी में पांच विकेट लिए।

भारतीय कप्तान विराट कोहली। फाइल फोटो, प्रेट्र

टेस्ट टीम के कप्तान विराट

विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष को ही देखा जाए तो भारत ने आठ मैच खेले और सात जीते, जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा। सीए की दशक की टेस्ट टीम में ओपनिंग के लिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर को चुना गया है, जबकि तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को शामिल किया गया है। स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के अलावा मध्यक्रम में एबी डिविलियर्स को रखा गया है। ऑलराउंडर के तौर पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन के साथ ऑस्ट्रेलियन स्पिनर नाथन लियोन को इस 11 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है।

सीए की दशक की टेस्ट टीम

कुक, डेविड वॉर्नर, विलियमसन, स्टीव स्मिथ, कोहली (कप्तान), डिविलियर्स, बेन स्टोक्स, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड, नाथन लियोन, जेम्स एंडरसन।

वनडे टीम : रोहित शर्मा, हाशिम अमला, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिब अल हसन, जोश बटलर, एमएस धौनी (कप्तान), राशिद खान, मिशेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, लसिथ मलिंगा।

विजडन की दशक की टेस्ट टीम

कुक, डेविड वार्नर, कुमार संगकारा, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, बेन स्टोक्स, एबी डिविलियर्स, आर. अश्विन, डेल स्टेन, कैगिसो रबादा, एंडरसन।

वनडे टीम : रोहित शर्मा, डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, जोश बटलर, एमएस धौनी, शाकिब अल हसन, लसिथ मलिंगा, मिशेल स्टार्क, ट्रेंट बेल्ट, डेल स्टेन।

ऑस्ट्रेलियन ओपन की पुरस्कार राशि में बड़ी वृद्धि

टेनिस डायरी

मेलबर्न, एएफपी : ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने साल के पहले ग्रैंडस्लैम की पुरस्कार राशि में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि की है और अब इसकी कुल पुरस्कार राशि सात करोड़ 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 350 करोड़ रुपये) कर दी गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष और महिला सिंगल्स विजेता को एक समान 41 लाख 20 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 20 करोड़ 31 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो कि पिछले साल की राशि से थोड़ा अधिक है लेकिन, शुरुआत में हारने वाले खिलाड़ियों को अधिक फायदा होगा।

पहले दौर में बाहर होने वाले खिलाड़ी को 90 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 44 लाख रुपये) की धनराशि मिलेगी, जो कि पिछले साल से 20 प्रतिशत अधिक है। दूसरे दौर में हारने वाले खिलाड़ी को पिछले साल की तुलना में 21.9 प्रतिशत अधिक यानी एक लाख 28 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 63 लाख रुपये) की राशि मिलेगी।

टूर्नामेंट के निदेशक क्रेग टिले ने कहा कि फाइनलिस्ट को छोड़कर प्रत्येक अगले दौर की पुरस्कार राशि में 10 से अधिक प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा, 'इस साल भी हमने हर साल की तरह पुरस्कार राशि में प्रत्येक दौर के हिसाब से वृद्धि की और हमने सिंगल्स एवं डबल्स में शुरुआती दौर में बाहर होने वाले खिलाड़ियों को भी अच्छी धनराशि से पुरस्कृत करने का फैसला किया है। हम खेल के प्रत्येक स्तर पर पुरस्कार राशि में वृद्धि करने में विश्वास रखते हैं। हम खेल में व्यवहारिक करियर के लिए मार्ग प्रशस्त करने और खिलाड़ियों को अधिक कमाई करने में मदद करने के लिए खेल समूह के साथ काम करना जारी रखेंगे।' पिछले पांच वर्षों में पुरस्कार राशि में 61.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में भी ऐसा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 20 जनवरी से मेलबर्न पार्क में शुरू होगा।

ऑकलैंड में जोड़ी बनाएंगी विलियम्स व वोज्नियाकी

ऑकलैंड : सेरेना विलियम्स और कैरोलाइन वोज्नियाकी पिछले लंबे समय से बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन अब टेनिस कोर्ट पर भी वे साथ में खेलती हुई दिखेंगी। इन दोनों स्टार ने छह जनवरी से ऑकलैंड में शुरू होने वाले डब्ल्यूटीए टूर क्लासिक में पहली बार डबल्स में जोड़ी बनाकर खेलने का फैसला किया है। विश्व की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी वोज्नियाकी ने 2015 के बाद हर साल ऑकलैंड में अपने सत्र की शुरुआत की और इस बार भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद संन्यास लेने से पहले इस हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया। वोज्नियाकी ने 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था, लेकिन इसके तुरंत बाद इस 29 वर्षीय खिलाड़ी को पता चला कि वह संधिवात गठिया (रूमेटाइड अर्थराइटिस) से पीड़ित हैं। वह अगले महीने मेलबर्न में खेलने के बाद संन्यास ले लेंगी। 23 बार की ग्रैंडस्लैम विजेता सेरेना 2015 में फेड कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ के बाद अपनी बड़ी बहन वीनस के अलावा किसी अन्य के साथ डबल्स में नहीं खेली हैं। वह डब्ल्यूटीए में आखिरी बार 2002 में वीनस के बिना डबल्स में खेली थीं। वोज्नियाकी भी तीन साल से अधिक समय से डबल्स में नहीं खेली हैं। सेरेना और वोज्नियाकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। इस साल के शुरू में वोज्नियाकी की शादी में सेरेना ने उनकी ब्राइड्समेड (दुल्हन की सहेली) की भूमिका निभाई थी। वह मई में कोपेनहेगेन में प्रदर्शनी मैच में खेलेंगी।

अभ्यास टूर्नामेंट से हटीं एंड्रीस्कू

वेलिंगटन : यूएस ओपन चैंपियन बियांका एंड्रीस्कू घुटने की चोट के कारण मंगलवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के अभ्यास टूर्नामेंट ऑकलैंड डब्ल्यूटीए टेनिस क्लासिक से हट गईं। इस साल विश्व रैंकिंग में 152 से पांचवीं रैंकिंग पर पहुंचने वाली कनाडा की 19 वर्षीय इस खिलाड़ी को ऑकलैंड में शीर्ष वरीयता दी गई थी, लेकिन आयोजकों ने कहा कि वह घुटने की चोट के कारण बाहर हो गई हैं। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेल पाएंगी या नहीं। एंड्रीस्कू ने इस साल तीन प्रतिष्ठित टूर्नामेंट इंडियन वेल्स, टोरंटो और यूएस ओपन के खिताब जीते थे। इसके बाद हालांकि चोट के कारण वह सत्र की आखिरी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाई थीं। वह लगभग सात सप्ताह तक बाहर रहीं। छह जनवरी से शुरू हो रहे ऑकलैंड टूर्नामेंट में अब सेरेना विलियम्स शीर्ष वरीय खिलाड़ी बन गई हैं।

रुडिगर नस्ली टिप्पणी मामले में नया मोड़

फुटबॉल डायरी

लंदन, एएफपी : टॉटनहम हॉटस्पर और चेल्सी के बीच रविवार को हुए लंदन डर्बी मुकाबले के दौरान टॉटनहम के सोन ह्युंग-मिन की चेल्सी के एंटोनियो रुडिगर के साथ झड़प हुई थी। हालांकि, इस झड़प के बाद दर्शकों द्वारा रुडिगर के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की खबर ने सोमवार को अंग्रेजी फुटबॉल से जुड़े नवीनतम नस्लवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है।

टॉटनहम हॉटस्पर के मैदान पर चेल्सी की 2-0 से प्रीमियर लीग जीत के दौरान रेफरी एंथोनी टेलर ने दूसरे हाफ के दौरान उस समय खेल रोक दिया था, जब रुडिगर ने दर्शकों की ओर से बंदर की आवाज सुनने की शिकायत की थी। इससे कुछ समय पहले ही चेल्सी के डिफेंडर रुडिगर के साथ सोन को झगड़ते हुए देखा गया था, जिसके बाद सोन को मैदान से बाहर भेज दिया गया था लेकिन ब्रिटिश वेबसाइट का कहना है कि चेल्सी के एक समर्थक को सोन के साथ नस्ली टिप्पणी के लिए रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन की महानगरीय पुलिस ने कहा कि कथित नस्ली टिप्पणी से संबंधित एक गिरफ्तारी हुई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह व्यक्ति किसी क्लब का समर्थक था। पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'पुलिस को 22 दिसंबर रविवार को टॉटनहम बनाम चेल्सी मैच के दूसरे हाफ के दौरान नस्ली टिप्पणी के बारे में सूचित किया गया था। पुलिस इसके जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने के लिए क्लब के साथ काम करेगी।' टॉटनहम ने रुडिगर के मामले की गहन जांच करने का वादा किया था लेकिन कई घंटों की आंतरिक पूछताछ के बावजूद क्लब दोषी की पहचान करने में असफल रहा। इस दौरान स्टेडियम के वीडियो कैमरे के फुटेज की समीक्षा की गई और पेशेवर लिप रीडर्स की भी मदद ली गई। टॉटनहम ने कहा कि किसी भी समर्थक को यदि दोषी पाया गया तो उस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन उसने जोर दिया कि, 'इस समय हमारे निष्कर्षों का कोई परिणाम नहीं निकला है।'

रुडिगर की शिकायत के तुरंत बाद रेफरी टेलर ने खेल रोक दिया था और दोनों टीमों के मैनेजर जोस मौरिन्हो एवं फ्रैंक लैंपार्ड से बात की थी।

माफिया शैली में हुए हमले के खिलाफ रेफरियों की हड़ताल

एथेंस : ग्रीक सुपर लीग के रेफरियों ने सोमवार को घोषणा की कि वे अपने एक साथी पर हुए ताजा हमले के विरोध में अपनी हड़ताल को अब एक हफ्ते पहले चार-पांच जनवरी को बुला रहे हैं। रेफरी संघ ने पहले यह हड़ताल 11-12 जनवरी को बुलाई थी। हथियारों के साथ कुछ बदमाशों ने रविवार को वोलोस-ओलंपिकोस के बीच मैच के गोलरहित ड्रॉ होने का आरोप लगाते हुए एक मैच अधिकारी के घर पर हमला किया था। ग्रीक फुटबॉल संघ ने 'सुपर लीग रेफरी पर माफिया की तरह के नए हमले' की कड़ी निंदा की है। ओलंपिकोस का धरना 'खराब मेजबानी' और पांच रेफरियों के खिलाफ रिश्वत लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ है। क्लब ने फुटबॉल की शासकीय संस्थाओं यूएफा और फीफा को भी धरने को लेकर पत्र भेजा है, जिसमें दावा किया गया कि मैच में वार का सही इस्तेमाल नहीं किया गया।

बोल्ट के 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट तक फिट होने की उम्मीद

मेलबर्न टेस्ट

मेलबर्न, एएफपी : न्यूजीलैंड को उम्मीद है कि जब उनकी टीम 30 साल से भी अधिक समय बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट खेलने के लिए उतरेगी तो तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट फिट होकर गेंदबाजी की अगुआई करने के लिए तैयार रहेंगे। यह अनुभवी तेज गेंदबाज मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पर्थ में पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाया था जिसमें न्यूजीलैंड को उनकी बड़ी कमी खली। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 296 रन से जीता था, लेकिन अब वह नेट्स पर पसीना बहा रहे हैं और लगता है कि क्रिकेट कैलेंडर की सर्वाधिक प्रचलित तारीखों में से एक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। बायें हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कहा कि मैं वास्तव में इसे आत्मसात करना चाहता हूं और इस माहौल की सराहना करता हूं। इस मंच पर उतरने के लिए बहुत से लोग सपना देखते हैं और अपने करियर में यह मौका मिलना, निश्चित तौर पर मैं इसको लेकर उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं पूरी तरह से फिट रहा तो फिर मैं यहां मैदान पर उतरने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस एक लाख क्षमता वाले स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के भी कई दर्शक इस मशहूर मैदान पर 26 दिसंबर को अपनी टीम की उपस्थिति का गवाह बनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। न्यूजीलैंड ने इससे पहले आखिरी बार 1987 में 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था। तब वर्तमान टीम के कई सदस्यों का जन्म भी नहीं हुआ था।

छोटी गेंद का अभ्यास कर रहे स्मिथ

मेलबर्न, एएनआइ : न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ छोटी गेंद का अभ्यास कर रहे हैं। स्मिथ ने कहा कि मैंने अभ्यास में छोटी गेंद का सामना किया है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि टेस्ट में मुझे छोटी गेंद की जाएंगी।

विविध

भोपाल के पत्रकारिता विवि में दो छात्राएं रात में धरने पर बैठीं

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दो छात्राओं ने मंगलवार रात पहुंचकर जमकर बवाल मचाया। पहले तो उन्होंने पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रबंधन को जमकर कोसा फिर वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। छात्राओं से मिलने पहुंचे रैक्टर श्रीकांत सिंह से छात्राओं ने कहा कि उनके एचओडी संजीव गुप्ता उनसे बॉयफ्रेंड का नाम पूछते हैं। साथ ही उनकी कक्षाओं में उपस्थिति कम बताते हुए परीक्षा में बैठने से भी रोक दिया है। इनमें से एक छात्रा भोपाल की और दूसरी लखनऊ की रहने वाली हैं।

छात्राओं ने बताया कि वे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मॉस कम्युनिकेशन में सेकंड ईयर की छात्र हैं। तबीयत खराब होने की वजह से वे कक्षाओं में नहीं बैठ सकीं थी। उनकी शनिवार से परीक्षाएं शुरू हुई हैं। परीक्षा के पहले उन्होंने पिता के साथ कुलपति दीपक तिवारी से मुलाकात कर सारी स्थिति से अवगत कराया था। इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है।

छात्राओं को उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे धरने प्रदर्शन के कारण किसी को नियमों से बाहर जाकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कुलपति से हल निकालने के लिए चर्चा की जाएगी।
–श्रीकांत सिंह, रैक्टर पत्रकारिता विश्वविद्यालय

देर रात पहुंचीं थाने : दोनों छात्राएं रात में एमपी नगर थाने भी पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के एचओडी संजीव गुप्ता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर शिकायत की। इसके बाद वे वापस आकर धरने पर बैठ गईं। समाचार लिखे जाने तक वे धरने पर बैठी थीं। गौरतलब है कि इससे पहले दो प्रोफेसरों द्वारा समाज विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर इसी विवि में हंगामा हो चुका है।

हरित क्रिसमस का संदेश..

यह कलाकृति मंगलवार को ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस कलाकृति के जरिए पटनायक ने पर्यावरण की बेहतरी के लिए हरित क्रिसमस मनाने का संदेश दिया। प्रेट्र

पाकिस्तानी तस्करों ने पाइप के जरिये पहुंचाई थी हेरोइन की दस से ज्यादा खेपें

नवीन राजपूत, अमृतसर

▸ पकड़े गए पांच तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को बताए रास्ते

▸ पाकिस्तान के नारोवाल गांव का आबाद अली दर्जनभर तस्करों के साथ गिरोह बना भेज रहा भारत में हेरोइन

पाकिस्तान से भारत भेजी गई 15 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए पांच तस्करों ने संयुक्त पूछताछ केंद्र में तीन पाकिस्तानी तस्करों के नाम कुबूल किए हैं। आरोपितों ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के नारोवाल गांव के आबाद अली, कसूर निवासी बिट्टू और जीओ अब्दुल्ला के इशारे पर भारत में नशा तस्कर कारोबार फैला रहे हैं। जांच में सामने आया कि पाक तस्कर आरोपितों के इशारे पर अलग-अलग सुरक्षित ठिकानों पर प्लास्टिक की पाइप के जरिये हेरोइन की दस से ज्यादा खेप भारत भेज चुके हैं।

पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा मंगलवार की शाम पांचों तस्करों को बख्तरबंद गाड़ी में बैठाकर रमदास सेक्टर के गांवों में लेकर पहुंची। आरोपितों ने भारत-पाक सीमा पर लगी कंटीली तार के साथ लगते वह ठिकाने दिखाए जहां से वह हेरोइन मंगवा चुके हैं। भिंडी सैदां थाना के तहत पड़ते खसुपुरा गांव निवासी बलकार सिंह और कोटली दोसंधा सिंह गांव निवासी दलबीर सिंह ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान के उक्त तस्कर उन्हें अलग-अलग लोकेशन पर हेरोइन की खेपें भेज चुके हैं। बीएसएफ की बटालियन के जाते ही वह खेप वाले ठिकाने पर पहुंच कर हेरोइन को उठाकर ठिकाने लगा देते थे। आरोपितों ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी तस्कर आबाद अली ने सीमा के साथ सटे पाकिस्तानी गांवों में रहने वाले दर्जनभर तस्करों के साथ मिलकर गिरोह बना रखा है। यह गिरोह आइएसआइ के इशारे पर भारत में हेरोइन का कारोबार फैला रहा है।

स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और काउंटर इंटेलिजेंस ने 20 दिसंबर की शाम खसुपुर गांव निवासी बलकार सिंह, कोटली दोसंधा गांव निवासी दलबीर सिंह, बिट्टू उर्फ सुक्खा सिंह, सराय अमानत खां गांव निवासी भूपिंदर सिंह उर्फ भिंदा और गुरजंट सिंह उर्फ जंटा को गिरफ्तार किया था। आरोपितों की कार की तलाशी ली गई तो उसमें रखी 15 किलो हेरोइन बरामद की गई थी जिसे आरोपित दिल्ली में सप्लाई करने जा रहे थे।

बॉर्डर पर हेरोइन पहुंचने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क : दैनिक जागरण में इस बारे में खबर प्रकाशित होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-पाक सीमा पर चौकसी बढ़ी दी है।

होमगार्ड वेतन घोटाला : मस्टर रोल में आग लगाने वाले प्लाटून कमांडर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

प्रवीण विक्रम सिंह, ग्रेटर नोएडा

जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में बीते 18 नवंबर की रात उन फर्जी मस्टर रोल में आग लगा दी गई थी जो कि होमगार्ड वेतन घोटाले से जुड़े थे। आग लगाने के आरोपित प्लाटून कमांडर राजीव कुमार निवासी सैदपुरा हापुड़ के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस जांच में कहा गया है कि राजीव ने अकेले ही कार्यालय में रखे फर्जी मस्टर रोल में आग लगाई थी। चार्जशीट में बताया गया है कि राजीव कार्यालय की दीवार कूदकर अंदर गया था। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी संलग्न की है। इसमें घटना वाली रात आरोपित जाता हुआ दिख रहा है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि आग लगाने के लिए मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला गया। लोहे की राड से कार्यालय का ताला तोड़ा गया था। होमगार्ड वेतन घोटाले से जुड़े दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक में चार्जशीट दाखिल हो गई है कि जब दूसरे मुकदमे में पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं जल्द ही दूसरे मुकदमे में भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। जिसके मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है उसकी जांच सूरजपुर कोतवाली के एसएसआइ दिलीप सिंह ने की है।

बता दें कि जुलाई के महीने में राजीव ने ही एसएसपी वैभव कृष्ण से शिकायत कर आरोप लगाया था कि होमगार्ड विभाग में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर वेतन घोटाला किया जा रहा है। कागजों में होमगार्ड की अधिक ड्यूटी दिखाकर सरकार से वेतन वसूला जा रहा है जबकि धरातल पर सच्चाई कुछ और है। एसएसपी ने मामले की जांच तत्कालीन एसपी सिटी विनीत जायसवाल से कराई थी। जांच में आरोप सही पाए गए और होमगार्ड वेतन घोटाला करोड़ों में पाया गया। मामले में सूरजपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लंबे समय तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज प्लाटून कमांडर राजीव ने फर्जी मस्टर रोल में आग लगा दी थी। उसको लगा था कि अधिकारियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उसके आग लगाने के बाद मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा और वेतन घोटाले से जुड़े होमगार्ड के मंडल कमांडेंट राम नारायण चौरसिया समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

कमांडेंट के खिलाफ जल्द दाखिल होगी चार्जशीट : प्लाटून कमांडर के आग लगाने के बाद पुलिस हरकत में आई थी और घोटाले के आरोपित कमांडेंट को गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद कमांडेंट के खिलाफ भी पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। फिलहाल पुलिस घोटाले से जुड़े मस्टर रोल को बतौर साक्ष्य कोर्ट में पेश करेगी। प्रत्येक थानों का मस्टर रोल इन दिनों तैयार किया जा रहा है।

अंगीठी जलाकर सोने के दौरान दम घुटने से दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बेगमपुर इलाके में ठंड से बचाव के लिए दुकान में अंगीठी जलाकर सोना दो लोगों की जान पर भारी पड़ गया। अंगीठी के कारण दुकान में धुआं भर गया और दम घुटने से किशोर सहित दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अख्तर (38) व कासिम (15) के रूप में हुई है। दोनों मुरादाबाद स्थित बिलारी के रहने वाले थे। पुलिस ने मंगलवार को दोनों के शवों का पोस्टमार्टम मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया।

अख्तर 20 वर्ष से रोहिणी के सेक्टर-22 में लक्खीराम पार्क में सैलून चला रहे थे, जबकि कासिम एक माह पहले ही दिल्ली आया था। पोस्टमार्टम के दौरान अख्तर के साले माजिद ने बताया कि सोमवार रात दोनों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद दुकान में अंगीठी जलाकर सो गए। उन्होंने बताया कि वह लोग पड़ोस में स्थित हलवाई की दुकान से रोज सुबह पीने का पानी लेते थे। मंगलवार सुबह जब दोनों में से कोई पानी लेने नहीं आया तो हलवाई ने दोनों को जगाने की कोशिश की, लेकिन सैलून के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हलवाई ने फोन पर मामले की जानकारी दी। इसके बाद वह अन्य रिश्तेदारों के साथ मौके पर आए और दुकान का शटर खोला, तो दोनों अंदर बेसुध पड़े हुए थे। मामले की जानकारी पुलिस को देकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दुकान का शटर बंद होने के कारण अंदर धुआं भर गया। इस कारण दोनों की दम घुटने से मौत हो गई।

अख्तर के परिजनों ने बताया कि कासिम अख्तर के बिलारी स्थित घर के पड़ोस में रहता था। एक माह पहले वह सैलून का काम सीखने अख्तर के पास आया था। कासिम की मौत से परिजनों को गहरा सदमा लगा है।

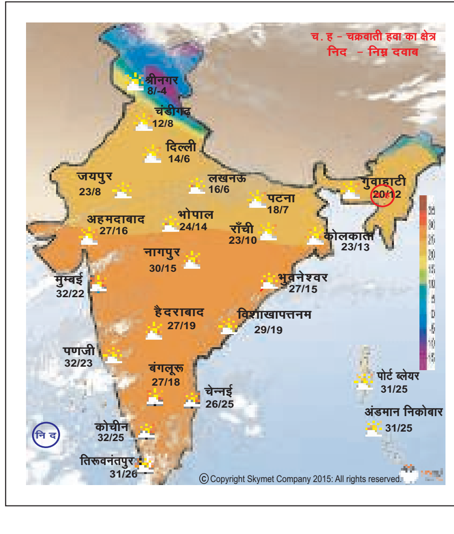

मौसम विशेष

पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। ठिठुरनभरी सुबह व दिन ठंड बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। रात के तापमान में गिरावट आएगी और दिन ठंडा बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/22/व	अहमदाबाद	28/11/आंबा
कोलकाता	24/14/आंबा	बड़ौदा	30/15/आंबा
चेन्नई	30/24/आंबा	नागपुर	29/16/आंबा
हैदराबाद	28/18/आंबा	इन्दौर	25/08/आंबा
बंगलूरू	27/19/आंबा	राँची	23/10/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/25/आंबा	पटना	21/09/आंबा
गुवाहाटी	22/10/आंबा	जमशेदपुर	23/08/आंबा
गंगटोक	07/-10/आंबा	पुणे	32/19/आंबा

पहली बार 336 ईस्वी में मनाया गया था क्रिसमस

आज ही के दिन 336 ईस्वी में पहली बार क्रिसमस मनाने का पता चलता है। सम्राट कांस्टेंटाइन ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की घोषणा की। उन्हें पहले ईसाई रोमन सम्राट के रूप में जाना जाता है। कुछ समय बाद पॉप जूलियस ने घोषित किया कि यह दिन प्रभु ईसा मसीह के जन्म का प्रतीक होगा।

गोर्बाच्योव के इस्तीफे के बाद टूटा था सोवियत संघ

आज ही के दिन 1991 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योव ने इस्तीफा दिया था। सोवियत संघ से रूस बना। बोरिस येल्तसिन इसके पहले राष्ट्रपति थे। इसी के बाद यूक्रेन, बेलारूस, कजाखिस्तान और उजबेकिस्तान सहित 15 नए देश अस्तित्व में आए।

कभी हार नहीं मानने वाले अटल बिहारी वाजपेयी

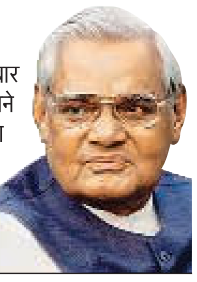

कवि, पत्रकार और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म आज ही के दिन 1924 में ग्वालियर में हुआ। वे 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। पहली बार 1957 में बलरामपुर से सांसद चुने गए। वाजपेयी भाजपा की नींव रखने वालों में भी शामिल रहे और तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने। पोखरण परमाणु परीक्षण कर दुनिया में धाक जमाई। पांच साल देश का नेतृत्व करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। उन्हें भारत रत्न और पद्मविभूषण से नवाजा गया। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली।

इधर-उधर की

लॉटरी की खुशी में रिपोर्टर ने छोड़ दी नौकरी

मैड्रिड, एजेंसी : स्पेन की एक टीवी रिपोर्टर ने गलतफहमी के चलते लाइव प्रसारण के दौरान अपना इस्तीफा दे दिया। रिपोर्टर को कवरेज के दौरान लगा कि वह लॉटरी जीत गई है। इसी उत्साह में इस्तीफा दे दिया। असलियत सामने आई तो उसका चेहरा लाल हो गया। आरटीवीई के लिए काम करने वाली नतालिया ने स्पेन की एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। अति उत्साह में उसने लाइव के दौरान कहा कि वह कल काम पर नहीं आएगी। उसे लगा कि लॉटरी में वह बड़ी राशि जीत चुकी है। यह राशि महज 5 हजार यूरो (करीब 3.94 लाख रुपये) थी। बाद में नतालिया ने इसके लिए ट्विटर पर खेद जताया और कहा कि वह व्यक्तिगत कारण से मुश्किल दौर से गुजर रही है।

आखिरी बार जावा द्वीप में पाए गए थे होमो इरेक्टस

वाशिंगटन, प्रेट्र : आधुनिक मानव के पूर्वजों में से एक होमो इरेक्टस यानी नर वानर आखिरी बार इंडोनेशियाई द्वीप जावा के नगंडोंग में पाए गए थे। हालिया अध्ययन में कहा गया है कि मानवों की यह प्रजाति लगभग चार लाख साल पहले विलुप्त हो गई थी। अमेरिका की इवोआ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, आधुनिक मानवों के पूर्वजों की यह प्रजाति इंडोनेशियाई द्वीप पर एक लाख आठ हजार से लेकर एक लाख 17 हजार वर्ष पूर्व के बीच रहती थी। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, इसका पता इसी इलाके में मिली हड्डियों के जीवाश्मों का अध्ययन कर लगाया गया। इस क्षेत्र में जानवरों के जीवाश्मों के साथ-साथ होमो इरेक्टस की 12 खोपड़ियां और पिंडलियों की दो हड्डियां मिली थीं।

पुरातत्वविदों ने धरती पर इस प्रजाति की संभावित आखिरी मौजूदगी का पता लगाने के लिए नगंडोंग के आसपास के इलाकों का अध्ययन किया। इवोआ यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञान विभाग में प्रोफेसर और अध्ययन के सह-लेखक रसेल सियोकॉन ने कहा, 'यह क्षेत्र दुनिया में कहीं भी पाए जाने वाले होमो इरेक्टस की आखिरी ज्ञात जगह है।' उन्होंने आगे कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि हमने इसकी विलुप्ति की तिथि निर्धारित की है, लेकिन हमने उनकी आखिरी मौजूदगी का पता लगाया है। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि होमो इरेक्टस इसके अलावा कहीं और भी रहते थे।

एक लाख आठ हजार से एक लाख 17 हजार वर्ष पूर्व तक था प्राचीन मानव की इस प्रजाति का अस्तित्व

ऐसे लगाया पता : जानवरों के जीवाश्म के टुकड़े और दोबारा खोजे गए जीवाश्म जैसे नमूनों का आकलन करने के बाद नए अनुमान लगाए गए थे। इससे पता चला कि ये वही जगह थे, जहां हॉलैंड के सर्वेक्षणकर्ताओं को 1930 में मूल होमो इरेक्टस के अवशेष मिले। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने दक्षिणी पहाड़ी गुफाओं में खनिजों का तिथि निर्धारण के जरिये यह भी अनुमान लगाया कि नगंडोंग के दक्षिणी पहाड़ पहली बार ऊपर की ओर उठे। इस जानकारी प्रयोग कर उन्होंने तय किया कि जब सोलो नदी नगंडोंग क्षेत्र से होकर बहने लगी, तो वहां नदी की तलहटी का निर्माण हुआ।

पर्यावरण बदलने के कारण हुए विलुप्त : शोधकर्ताओं के अनुसार, होमो इरेक्टस ने इंडोनेशियाई द्वीप समूह में अपना रास्ता बनाया और जावा द्वीप पर लगभग 16 लाख साल पहले पहुंचे। उनका कहना है कि तब नगंडोंग के आसपास का इलाकों में घास ही घास थी और पेड़-पौधों तथा जानवरों की संख्या भी अत्यधिक थी। हालांकि, लगभग एक लाख तीस हजार साल पहले नगंदोंग का पर्यावरण बदल गया, जिससे होमो इरेक्टस के लिए भी परेशानियां आने लगीं और धीरे-धीरे वे विलुप्त हो गए।

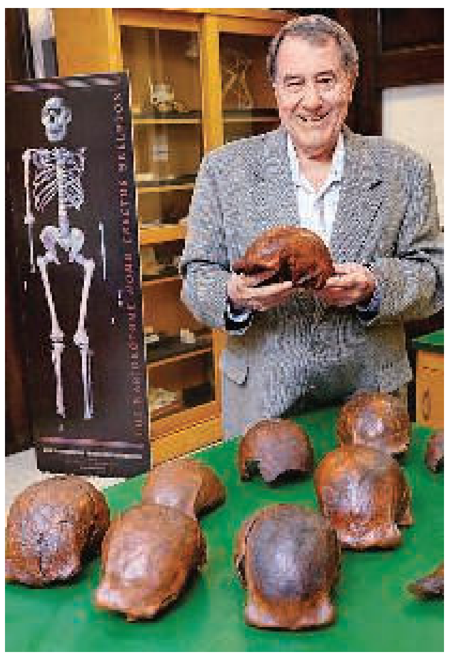

होमो इरेक्टस की खोपड़ी दिखाते इस अध्ययन के लेखक रसेल सियोकॉन। साभार : इवोआ यूनिवर्सिटी

ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ाया हिंद महासागर का जल स्तर

- पिछली दो सदी में लगभग एक मीटर तक हुई है वृद्धि
- तटीय शहरों के डूबने का मंडरा रहा है बड़ा खतरा

यह अध्ययन साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। फाइल

टोरंटो, प्रेट्र : ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिंद महासागर का बढ़ता जल-स्तर चिंता का सबब बनता जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, पिछली दो शताब्दियों में मध्य हिंद महासागर के जल-स्तर में लगभग एक मीटर की बढ़ोतरी हुई है। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित शोध में समुद्र के जल-स्तर के बारे में नई जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल केंच ने बताया, 'हम जानते हैं कि खास तरह के शैवाल जीवाश्म अतीत में समुद्र के जल-स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम इन जीवाश्मों की आयु और गहराई को मापकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सैकड़ों साल पहले हिंद महासागर के कई हिस्सों में जल-स्तर हमारी सोच से काफी कम था।

शोधकर्ताओं का कहना है कि पिछली दो सदियों में समुद्री जल-स्तर में काफी

स्पेक्ट्रम

बदलाव आया है। औद्योगिक काल शुरू होने के बाद इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि समुद्र का जल-स्तर ऐतिहासिक रूप से कैसा रहा है और उनके बढ़ने पर क्या होता है, ये तमाम बातें यह समझने में काफी मददगार होंगी कि भविष्य में समुद्री जल-स्तर बढ़ने से शैवाल-भित्तियों और द्वीपों पर क्या असर पड़ेगा।

यह अध्ययन 2017 में शुरू हुआ, जिसमें जल-स्तर बढ़ने से तटीय शहरों और समुदायों के लिए गंभीर खतरे की बात कही गई। इसमें यह भी कहा गया कि अगर जल-स्तर में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही, तो आने वाली सदी में हिंद महासागर का जल-स्तर ऐतिहासिक रूप से अपने उच्चतम स्तर पर होगा।

तेजी से वायरस की पहचान करेगी नई डिवाइस

तकनीक ▶ अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया 'विररियोन'

वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने में मिलेगी मदद

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : शोधकर्ताओं ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, जो वायरस के विभिन्न उपभेदों के विकास का तेजी से पता लगाने में समक्ष है। यह इतनी हल्की है कि इसे हाथों से पकड़कर कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस डिवाइस की मदद से वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा।

पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े और इस अध्ययन के शोधकर्ता मौरिसियो टेरोनस ने कहा, 'हमने एक किफायती डिवाइस बनाई है, जो वायरस की उसके आकार के आधार पर पहचान कर सकती है।' उन्होंने कहा कि हमारी डिवाइस में नैनोट्यूब्स का उपयोग किया, जो आकार में वायरस की एक विस्तृत श्रृंखला जैसी दिखती है। टेरोनस ने कहा, 'वायरस की पहचान के लिए हमने इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी उपयोग किया। इस तकनीक का प्रयोग सामान्यतः कंपन, घूर्णन तथा अन्य कम आवृत्ति के प्रकारों के अध्ययन के लिए किया जाता है।

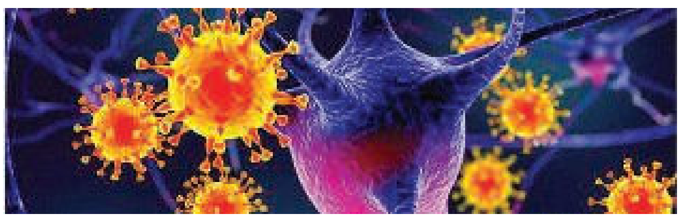

यह अध्ययन जर्नल प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

इस डिवाइस को 'विररियोन' नाम दिया गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इस डिवाइस की मदद से किसानों को फसल की बोआई के बाद समय रहते खेत में फैले वाइरस का पता लग सकता है। इसके अलावा पशुधन में भी वायरस का संक्रमण होने पर उनके बड़े झुंड को इसकी चपेट में आसे बचाया जा सकता है। किसी वायरस का संक्रमण का पता लगाने के लिए वर्तमान में कम से कम एक दिन का समय तो लग ही जाता है लेकिन इस डिवाइस की मदद से मिनटों में ही वायरस का पता लगाकर जरूरी चिकित्सा कराई जा सकती है।

जर्नल प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, इस डिवाइस के छोटे आकार और किफायती होने के कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि कई बार डॉक्टरों के लिए हर मशीन अपने ऑफिस में रखना संभव नहीं हो पाता और दूरस्थ क्षेत्रों में संक्रमण फैलने पर भारी-भरकम मशीनों को वहां ले जाना असंभव होता है। ऐसे में नई डिवाइस काफी मददगार सिद्ध हो सकती है।

जानवरों में मौजूद होते हैं 16.7 लाख वायरस : वायरोलॉजिस्टों का अनुमान है कि वर्तमान में 16.7 लाख अज्ञात वायरस जानवरों में मौजूद हैं, जिनमें से कई मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ज्ञात वायरस जैसे-एच1एन1, जीका और इबोला के कारण बीते दशक में कई लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि इनका समय रहते पता नहीं चल पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि यदि इन वायरसों के बारे में जल्दी पता लगाने से इसके खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

बनाई वायरस लाइब्रेरी : टेरोनस ने कहा, 'वर्तमान में वायरस का पता लगाने वाली ज्यादातर तकनीकें काफी महंगी हैं। भविष्य में विररिओन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी गुणवत्ता में प्रभावी बनाने के लिए हमने इस डिवाइस में सोने के नैनोपार्टिकल्स भी मिलाए हैं। इसके बाद वायरस की कम मौजूदगी पर भी हम आसानी से पता लगा लिया। हमने मशीन लर्निंग विधि के जरिये एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें अलग-अलग प्रकार के वाइरस रखे गए हैं।

वैज्ञानिकों ने बनाई सबसे सटीक घड़ी

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नासा-जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) के वैज्ञानिकों ने मिलकर सबसे सटीक समय बताने वाली घड़ी का निर्माण किया है। ऑप्टिकल परमाणु घड़ी प्रणाली की इस सबसे उन्नत घड़ी को वैज्ञानिकों ने 'ट्वीजर क्लॉक' का नाम दिया है। इस घड़ी में ट्वीजर की तरह दिखने वाले लेजर की मदद से सीजियम के परमाणुओं को नियंत्रित कर सही समय की गणना की जाती है। यह घड़ी इतना सटीक समय बताती है कि करोड़ों वर्ष की गणना में शायद अधिक से अधिक एक सेकेंड की चूक हो जाए।

ट्वीजर घड़ी के बारे में सारी जानकारी फिजिकल रिव्यू एक्स जर्नल में प्रकाशित की गई है। इसके शोधकार्य में शामिल

प्रतीकात्मक

भौतिकी के असिस्टेंट प्रोफेसर मैनुएल एंडर्स ने बताया कि इस घड़ी की मदद से समय की सटीकता के अलावा समय की बड़ी-बड़ी गणनाएं त्रुटि रहित की जा सकेंगी। आम दिनचर्या में हालांकि इस विशेष परमाणु घड़ी के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शोध जैसे क्षेत्र में जहां समय की सटीकता की जरूरत खूब पड़ती है, वहां ट्वीजर घड़ी का इस्तेमाल बखूबी किया जा सकेगा।

शोध अनुसंधान

नए इलाज से कम हो सकता है घातक ब्रेन ट्यूमर का खतरा

कुछ खास प्रकार के कैंसर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर दवाएं वयस्कों में होने वाले सबसे घातक प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर ग्लियोब्लास्टोमा में अप्रभावी हो जाती हैं। मैसाच्युसेट्स जनरल हास्पिटल और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा चूहों पर किए गए शोध से इसका पता चला है कि ये दवाएं ग्लियोब्लास्टोमा के प्रति संवेदनशील हैं। ग्लियोब्लास्टोमा के मरीजों पर इन दवाओं के प्रभाव नहीं पड़ने का बड़ा कारण यह है कि एमडीएससी नामक कोशिकाएं ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर के आसपास के क्षेत्र में घुसपैठ करती हैं, जहां ये उपचार में गतिरोध प्रदान करने के साथ ही ट्यूमर को बढ़ाने में मदद प्रदान करती हैं। इसीलिए अगर इन कोशिकाओं को खत्म करने का लक्ष्य बनाकर इलाज किया जाए तो प्रभावित मरीज ठीक भी हो सकता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित शोध में यह संकेत दिया गया है कि इन दवाओं का क्लीनिकल ट्रायल ग्लियोब्लास्टोमा से प्रभावित मरीजों पर किया जाना चाहिए। (एएनआइ)

दिल की गंभीर बीमारी से बचाता है मैग्नीशियम

मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति के बाद अगर महिलाएं आहार के तौर पर ज्यादा मैग्नीशियम लेती हैं तो उनमें दिल की गंभीर बीमारी की संभावना कम होगी। अल्बर्ट मेडिकल स्कूल ऑफ ब्राउन यूनिवर्सिटी के चार्ल्स इटन और शोधकर्ताओं की टीम ने एक लाख 53 हजार से ज्यादा मीनोपॉज महिलाओं में मैग्नीशियम के सेवन की जांच की और इसके बाद 10.5 वर्षों के दौरान दिल की गंभीर बीमारी व इसके चलते हुई मौत के आंकड़ों को देखा। इससे पता चला कि जिन महिलाओं ने आहार में ज्यादा मैग्नीशियम का प्रयोग किया था उनमें कोरोनरी हृदय रोग का जोखिम कम मिला। (एएनआइ)

पानी में मिल गया 600 गैलन डीजल

इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप समूह के सैन क्रिस्टोबाल द्वीप के बंदरगाह पर मालवाहक पोत पलट जाने से छह सौ गैलन (लगभग 2300 लीटर) डीजल बह गया। यह हादसा तब हुआ जब एक क्रेन पोत पर गिर गया और पोत पलट गया। यह द्वीप समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शुमार है और यहां का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। डीजल फैलने से पारिस्थितिकी को नुकसान की आशंका है। एएफपी

सांता क्लॉज के गांव में क्रिसमस का उत्साह

फिनलैंड में सांता क्लॉज का गांव कहे जाने वाले रोविनेमी में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। ईसाइयों के मुख्य त्योहार के मौके पर दुनिया भर से यहां पर्यटक पहुंचते हैं। इन दिनों स्थानीय लोगों ने यहां बर्फ के होटल और स्कीइंग रिजॉर्ट बनाकर पूरे इलाके को वंडरलैंड में बदल दिया है, जिसके चलते इस बार यहां अब तक रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। सर्दियों के महीनों में इस इलाके में सूरज मुश्किल से ही दिखता है। एएफपी

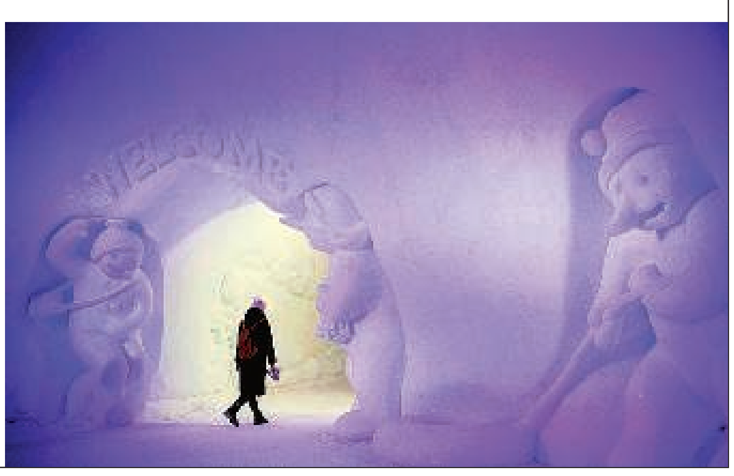

स्क्रीन शॉट

मेरा पति मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए : कंगना रनोट

अभिनेत्री कंगना रनोट अपनी बेबाकी की वजह से अक्सर लोगों से पंगा लेती रहती हैं। उनकी अगली फिल्म का नाम भी 'पंगा' ही है। इसमें वह कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका में हैं जो शादी करके घर गृहस्थी में रम जाती है। हालांकि बाद में वह फिर खेल में वापसी की तैयारी करती है। 'बरेली की बर्फी' और 'निल बट्टे सन्नाटा' का निर्देशन कर चुकी अश्विनी अय्यर तिवारी ने पंगा का निर्देशन किया है। अश्विनी चाहती हैं कि कंगना शादी कर लें। उनका कहना है कि उन्होंने साड़ियां पसंद कर ली हैं। समारोह स्थल भी देख लिया है। बस लड़का देखना बाकी है। हालांकि कंगना का कहना है कि उन्हें शादी को लेकर लगता था कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढ़ना मुश्किल है जहां बराबरी का दर्जा हो लेकिन अश्विनी की शादी देखने के बाद लगता है कि यह संभव है। वह अश्विनी के पति नीतेश तिवारी की प्रशंसक हैं। वह अश्विनी को उनके काम में पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अपने हमसफर को लेकर कंगना का कहना है कि वह ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हैं जो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, खूबसूरत और टैलेंटेड हो। हालांकि पंगा लेने से आगे भी उन्हें गुरेज नहीं हैं। असल जिंदगी में पंगा लेने से सावधानी बरतने को लेकर कंगना का कहना है कि पंगा लेने से पहले यह ध्यान रखें कि आप जो कहें सच कहें फिर आप कोई भी हों, लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। मगर झूठ को वे नहीं पसंद करते। मैं हमेशा से स्पष्ट रही हूं। कहते हैं कि सच को साबित करने में समय लगता है लेकिन उसे छिपाया नहीं जा सकता है। लिहाजा सच बोलें।

'हंगामा 2' का पोस्टर आया सामने

मंगलवार को कॉमेडी फिल्म 'हंगामा 2' का पहला पोस्टर जारी किया गया। फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन करीब सात साल बाद हिंदी सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। प्रियदर्शन ने इससे पहले 'हंगामा', 'दे दना दन', 'चुप चुप के', और 'भागम भाग' जैसी कॉमेडी फिल्मों को निर्देशित किया है। 'हंगामा 2' में मीजान जाफरी, परेश रावल, शिल्पा शेट्टी और प्रनीता सुभाष मुख्य भूमिका में हैं। अगले साल 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही यह फिल्म साल 2003 में बनी 'हंगामा' की सीक्वल है। 'हंगामा' की स्टारकास्ट से सिर्फ परेश रावल और राजपाल यादव ही इस सीक्वल का हिस्सा हैं। 'हंगामा' में आफताब शिवदासानी, अक्षय खन्ना और रिमी सेन मुख्य भूमिका में थे। सोशल मीडिया पर एक प्रशंसक के सवाल के जवाब में परेश ने अगले मानसून से पहले फिल्म 'ओ माई गॉड 2' और 'हेरा फेरी 3' के भी आने का संकेत दिया है।

कपिल व सुमोना ने किया मेट्रो का सफर

दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक से बचने का आसान रास्ता है मेट्रो से सफर करना, पर यह सफर सेलिब्रिटीज के लिए संभव नहीं हो पाता है। हालांकि अक्षय कुमार ने कुछ महीने पहले ट्रैफिक से बचने के लिए मुंबई मेट्रो से सफर किया था और वह बीस मिनट में मीटिंग के लिए पहुंच गए थे। इसका वीडियो भी अक्षय ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। अब कपिल शर्मा को मेट्रो का सफर भा रहा है।

कपिल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे हैं। उनके साथ कपिल शर्मा शो की भूरी यानी सुमोना चक्रवर्ती भी हैं। कपिल ने इस तस्वीर के साथ लिखा है, 'ट्रैफिक में रहने की जरूरत नहीं है। मेट्रो लीजिए।'

63 के हुए अनिल, सोनम ने इसे पापा का 21वां जन्मदिन कहा

हिंदी सिनेमा के सबसे युवा कलाकार कहे जाने वाले अनिल कपूर मंगलवार यानी 24 दिसंबर को 63 वर्ष के हो गए। अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'मलंग' का अपना लुक भी जारी किया। तस्वीर में वह पुलिस अफसर की वर्दी में हैं। रंगीन चश्मा पहने हुए अनिल के हाथ टैटू से भरे हैं। उनके किरदार का नाम अंजनेय आगाशे होगा। 'मलंग' का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है। अनिल ने तस्वीर के साथ लिखा, 'मेरे जन्मदिन पर मलंग।' मुंबई में सोमवार की रात उनके जन्मदिन पर एक खास पार्टी भी रखी गई थी। इसके कुछ वीडियो सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर साझा भी किए हैं। साथ ही उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बचपन की एक तस्वीर साझा की, जिसमें सोनम और रिया अपने पापा के साथ केक काट रही हैं। उन्होंने लिखा, 'सबसे प्रेरणादायक, समझदार, घर के सबसे युवा व्यक्ति। हमेशा मेरा समर्थन करने और मेरे साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप जैसे हैं और जिस तरह से हमारा खयाल रखते हैं उसके लिए धन्यवाद।'

अध्ययन

पोट्र्समाउथ और नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसट्रिक्ट के शोधकर्ताओं ने किया दावा, मैसेज, फोन या सोशल मीडिया की बजाय आमने-सामने झूठ बोलना अधिक पसंद करने हैं लोग

महिलाओं की तुलना में बेहतर झूठ बोलते हैं पुरुष

लंदन, प्रेट्र : वैसे तो हर बात कहने का अपना ही अलग अंदाज होता है। जब इन बातों की चासनी में झूठ का घोल घोला जाता है, तो अक्सर पकड़े जाने का खतरा बना रहता है। फिर चाहे झूठ कोई महिला बोले या फिर पुरुष... लेकिन, हालिया अध्ययन से पता चला है कि जब झूठ बोलने की बात आती है, तो महिलाओं के मुकाबले पुरुष बेहतर झूठ बोलते हैं। ब्रिटेन की पोट्र्समाउथ यूनिवर्सिटी के अनुसार, झूठ बोलने में महारथी व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होता है और वह दूसरों की तुलना में अपने परिवार, दोस्तों, पार्टनर और सहयोगियों से अधिक झूठ बोलता है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि झूठ बोलने में माहिर शख्स मैसेज की बजाय आमने-सामने झूठ बोलने अधिक पसंद करता है और सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां वे बहुत कम झूठ बोलते हैं। पोट्र्समाउथ और नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसट्रिक्ट की ब्रियन्ना वेरिजिन ने बताया 'झूठ बोलने के मामले में विशेज्ञता और महिला-पुरुषों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। महिलाओं की तुलना में पुरुष खुद को दोगुना बेहतर झूठ बोलने वाला मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि झूठ बोलने के बाद आसानी से बच निकलते हैं।' पहले के अध्ययनों में बताया गया था कि अधिकांश व्यक्ति हर रोज एक से दो झूठ बोलते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। झूठ बोलने वालों का एक छोटा समूह है। पीएलओएस वन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि लगभग आधे झूठ बोलने वालों की संख्या कम है और ये लोग अपने करीबियों से छुटकारा या उनसे माफी के लिए झूठ बोलते हैं।

ऐसे किया अध्ययन : वेरिजिन ने इस अध्ययन के लिए 39 वर्ष की औसत उम्र वाले 194 महिला-पुरुषों से सवाल-जवाब किए। उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, जिनमें यह भी पूछा गया कि वे दूसरों को धोखा देने के मामले में खुद को कितना बेहतर मानते हैं। अध्ययन में पाया गया कि झूठ बोलने वालों की सबसे अहम रणनीति होती है कि वे ऐसा झूठ बोलते हैं, जो सच के करीब हो। शोधकर्ताओं ने बताया कि लोगों को लगता है कि वह जितनी अच्छी तरह बोल सकता है, वह उतना ही अधिक झूठ बोलता है।

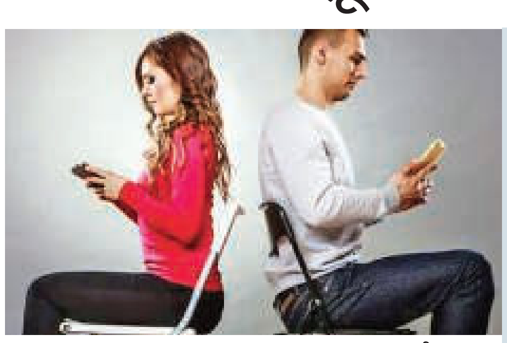

प्रतीकात्मक

इस तरह के झूठ बोलते हैं लोग

इन 194 लोगों में झूठ बोलने के अलग-अलग तरीके भी सामने आए। उदाहरण के तौर पर, सबसे अधिक लोग सफेद झूठ, फिर अतिशयोक्ति, सूचनाएं छिपाना, सच की आड़ में झूठ बोलना आदि शामिल हैं।